चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

देशमुख के लिए चुनौती होंगे ऐसे अधिकारी

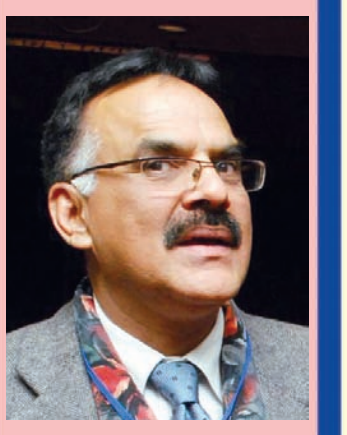

पेज-3

मुसलमान अपनी लड़ाई भारतीय नागरिक बनकर लड़ें

पेज-5

मंत्री जी, किसान पागल नहीं हैं

पेज-6

साई की महिमा

पेज-12

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 31 जनवरी–06 फरवरी 2011 | मूल्य 5 रुपये

मनमोहन-सोनिया के मतभेद

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

संतोष भारतीय

केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार का शोर एक साल से मच रहा था. माना जा रहा था कि बड़ा फेरबदल होगा और वे मंत्री नहीं रहेंगे, जिनके काम का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा तथा वे भी नहीं रहेंगे, जिनके ख़िलाफ़ संगीन आरोप लगे हैं. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ, यही रहस्य है और इस रहस्य के पीछे एक नहीं, कई कारण हैं. कई लोगों की आईबी क्लियरेंस ले ली गई, पर उन्हें मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया और जिन्हें लिया गया, उन्हें लेकर कांग्रेस पार्टी में चर्चाएं चल रही हैं. इन सब बातों की जड़ में मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं. मंत्रिमंडल विस्तार से एक दिन पहले मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी में दो घंटे बातें हुईं. इस बातचीत में अहमद पटेल भी शामिल थे. अगले दिन, जिस दिन विस्तार होना था, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अहमद पटेल में फिर एक घंटे से ज़्यादा बातचीत हुई. इसके बाद सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को फोन कर अपना फ़ैसला सुनाया. इसीलिए शाम पांच बजे जब विस्तार हुआ तो केवल तीन लोगों को नए सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई और सैंतीस मंत्रियों का विभाग बदला. कई सदस्यों को राज्य मंत्री से मंत्री भी बनाया गया. आख़िर क्या हुआ था 7 रेसकोर्स की मीटिंग में, जिसमें सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और अहमद पटेल थे, और क्या हुआ था उस मीटिंग में, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अहमद पटेल थे. इसकी निन्यान्बे प्रतिशत विश्वसनीय और सच्ची कहानी आपको बताते हैं.

मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के नाते अपने मंत्रिमंडल के लगभग दस मंत्रियों के कामकाज से ख़ुश नहीं हैं. वह विस्तार के बहाने इन मंत्रियों को हटाना चाहते थे तथा नए लोगों को मंत्रिमंडल में लेना चाहते थे. प्रधानमंत्री ने तय कर लिया था कि कमलनाथ, सी पी जोशी, कांतिलाल भूरिया, मुरली देवड़ा, शैलजा, अंबिका सोनी को वह मंत्रिमंडल से हटा देंगे. पहली मीटिंग में सोनिया गांधी ने इसका विरोध किया. उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि इससे बजट सेशन में परेशानी पैदा हो जाएगी, क्योंकि इन मंत्रालयों के बजट को न केवल अंतिम रूप देना है, बल्कि पेश भी करना है. दूसरा तर्क था कि कुछ राज्यों के चुनाव भी होने वाले हैं. प्रधानमंत्री की इस सूची में विलासराव देशमुख और वीरप्पा मोइली का भी नाम था. प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी की बातचीत सुनी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मंत्री न केवल अक्षम हैं, बल्कि इनकी शिकायतें भी हैं तथा इनमें से कुछ की वजह से बदनामी भी काफ़ी हुई है. दो घंटे बाद जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री आवास से निकलीं तो वह आश्वस्त नहीं थीं कि मनमोहन सिंह वही करेंगे या नहीं, जो वह चाहती हैं.

दरअसल सोनिया गांधी और राहुल गांधी चाहते थे कि कपिल सिब्बल, अंबिका सोनी और चिदंबरम के विभाग बदले जाएं. अंबिका सोनी से नाराज़गी इसलिए थी कि उनके सूचना प्रसारण मंत्री रहते हुए हर चैनल पर कांग्रेस की, सोनिया गांधी की आलोचना हो रही थी, जिसे वह संभाल नहीं पा रही थीं. सोनिया गांधी के महामंत्रियों को लगता है कि वह यह जानबूझ कर रही हैं. चिदंबरम से इसलिए, क्योंकि चिदंबरम ने देश में ऐसा माहौल बना दिया, मानो क़ानून व्यवस्था केंद्र का विषय है. उनके बयान भी ऐसे आए, जैसे नक्सल हों या अपराधी, आतंकवादी हों या जालसाज़, सबसे उन्हें या कहें कि केंद्र सरकार को निबटना है. राहुल गांधी के सख्त हस्तक्षेप से चिदंबरम चुप हुए थे, वरना लोग भूल गए थे कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है.

अगले दिन यानी उन्नीस जनवरी को, जिस दिन विस्तार होना था, दस जनपथ में राहुल और अहमद पटेल आए तथा सोनिया गांधी से एक घंटे बात की. तीनों ने तय किया कि प्रधानमंत्री से कहा जाए कि वह वही करें, जो कांग्रेस अध्यक्ष चाहती हैं. अहमद पटेल ने बारह बजे प्रधानमंत्री को सूचित किया. हमारी जानकारी बताती है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हटाने वाले मंत्रियों में एक नाम ऐसे मंत्री का भी है, जो उस सूची में है, जिसे जर्मनी के लिख–टेन–श्टाइन बैंक ने भेजा है और जो सीलबंद लिफ़ाफ़े में सुप्रीम कोर्ट के पास है. एक मंत्री का नाम नीरा राडिया के साथ भी वैसे ही उछलने वाला है, जैसा ए. राजा का उछला था. प्रधानमंत्री से कहा गया कि सारा मसला बाद में देखेंगे.

सोनिया गांधी का मानना है कि शरद पवार तो महंगाई बढ़ाने वाले बयान देते हैं, वह ठीक है, क्योंकि उनकी प्रतिबद्धता कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन अंबिका सोनी क्यों नहीं समझतीं और देश को समझातीं कि महंगाई रोकना राज्यों का विषय है. केंद्र के नियंत्रण में सिर्फ गेहूं, चावल, चीनी, यूरिया और पेट्रोल है, बाकी सब राज्यों के दायरे में है. मनमोहन सिंह से नाराज़गी की एक वजह सोनिया गांधी की शरद पवार भी हैं. उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री और प्रणव मुखर्जी जानबूझ कर शरद पवार को न नियंत्रित कर पा रहे हैं और न समझा पा रहे हैं.

तब प्रधानमंत्री ने कहा कि वह विभाग अवश्य बदलेंगे. और इसी पर समझौता हुआ. प्रधानमंत्री ने जो बदलाव किया, उसने देश के सामने कांग्रेस को अजीब स्थिति में खड़ा कर दिया. अगर मंत्रियों को अक्षम होने की वजह से बदला गया तो वे नए विभाग में क्या कमाल दिखाएंगे, या तो उसे लूटेंगे या बर्बाद करेंगे और अगर वे सक्षम थे तो उन्हें बदला क्यों गया, क्योंकि उन्हें साल भर तो समझने में ही लग जाएगा. कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों का कहना है कि जिन्हें राज्यमंत्री से मंत्री बनाया गया, उनमें वे हैं जिनके पास न वोट की ताक़त है और न उनके समाज की. श्रीप्रकाश जायसवाल को मंत्री बनाने से कांग्रेस को चुनाव में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. सलमान खुर्शीद का प्रमोशन नहीं हुआ, बल्कि डिमोशन हुआ है. उनके पास से कंपनी मामले ले लिए गए और जल संसाधन दे दिया गया. सलमान खुर्शीद को लेकर राहुल गांधी से शिकायतें की गई थीं कि अल्पसंख्यक मामले ये देखते नहीं, कारपोरेट अफेयर में व्यस्त रहते हैं. राहुल ने यह बात सोनिया गांधी को बताई. अजय माकन को भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी पसंद नहीं करते, पर उन्हें भी मंत्री बना दिया गया. विभाग ऐसा दिया गया, खेल, जिसमें अभी करने के लिए कुछ भी नहीं है.

राहुल गांधी ने बेनी प्रसाद वर्मा को कैबिनेट मंत्री बनाने की सिफ़ारिश की थी. प्रधानमंत्री ने मान भी लिया था, पर उन्हें शपथ दिलाई गई राज्य मंत्री की. एक घंटे के भीतर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से बात की और बेनी वर्मा को संकेत मिला कि उन्हें अप्रैल में मंत्री पद पर तरक्की दे दी जाएगी. श्रीकांत जेना को तरक्की न देने का उड़ीसा में बुरा संकेत गया है. कांग्रेस के लोगों का कहना है कि बेनी वर्मा को मंत्री न बनाने के पीछे प्रधानमंत्री ने एक संकेत राहुल गांधी को दिया कि वह सभी बातें नहीं मानेंगे तथा दूसरा बेनी वर्मा को कि आप अभी तो कांग्रेस में आए हैं. बेनी वर्मा के साथियों का कहना है कि कांग्रेस नासमझों की पार्टी है. शंकर सिंह बाघेला भाजपा से निकले, अपनी पार्टी बनाई और बाद में वह कांग्रेस में आए. आते ही उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया गया और बाद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष. इसी तरह राणे शिवसेना से आए, उन्हें मंत्रिमंडल में नंबर दो की जगह मिल गई. उनके बेटे को सांसद बना दिया. लेकिन बेनी वर्मा सारी जिंदगी सेक्युलर रहे, केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे और उन्हें अब जब कांग्रेस ने मंत्री बनाया तो राज्य मंत्री. कांग्रेस को यह भी नहीं समझ आया कि बेनी वर्मा के साथ उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण पिछड़ा तबका कुर्मियों का है. राहुल गांधी और मनमोहन सिंह के अहम की लड़ाई में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपना नुक़सान कर लिया, जहां चुनाव अगले साल होने वाले हैं.

सोनिया गांधी का मानना है कि शरद पवार तो महंगाई बढ़ाने वाले बयान देते हैं, वह ठीक है, क्योंकि उनकी प्रतिबद्धता कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन अंबिका सोनी क्यों नहीं समझतीं और देश को समझातीं कि महंगाई रोकना राज्यों का विषय है. केंद्र के नियंत्रण में सिर्फ़ गेहूं, चावल, चीनी, यूरिया और पेट्रोल है, बाक़ी सब राज्यों के दायरे में है. मनमोहन सिंह से नाराज़गी की एक वजह सोनिया गांधी की शरद पवार भी हैं. उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री और प्रणव मुखर्जी जानबूझ कर शरद पवार को न नियंत्रित कर पा रहे हैं और न समझा पा रहे हैं.

इस विस्तार के अंतर्विरोध हैं. आरपीएन सिंह ने उत्तर प्रदेश में 18 हजार करोड़ की नई योजना सड़कों की बनाई, उन्हें हटाकर पेट्रोलियम भेज दिया और जितिन प्रसाद को भूतल परिवहन में. दोनों को समझने में ही छः महीने लग जाएंगे. सीपी जोशी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा मनरेगा का कोई फ़ायदा नहीं उठाया, जबकि यह अकेली ऐसी योजना थी, जिसकी वजह से कांग्रेस हर प्रदेश में चुनाव जीत जाती. आज़ादी के बाद रोज़गार की इससे बड़ी योजना नहीं बनी थी, पर कांग्रेस इसका कोई फ़ायदा न उठा पाई. अब इसका जिम्मा विलासराव देशमुख को दिया गया है, जो प्रधानमंत्री की उस लिस्ट में हैं, जिन्हें मंत्रिमंडल से हटाया जाना है.

सोनिया गांधी मुरली देवड़ा को पेट्रोलियम मंत्री के तौर पर ही चाहती थीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें हटाना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया. उन्होंने विभाग बदला और जयपाल रेड्डी को पेट्रोलियम मंत्रालय दिया, जिनकी छवि ईमानदार मंत्री की है और जिनके बारे में आज

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सबकी निगाहें नीतीश की ओर हैं. उन्होंने राज्य के सभी आईएएस अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा कर दें.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

बाबू अपनी संपत्ति की घोषणा करें

वर्ष 2010 में अवैध रूप से 280 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा करने के मामले में एक आईएएस अधिकारी का नाम आने के बाद अब लगता है कि 2011 में बाबुओं को अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए कहा जा सकता है. नीतीश कुमार बिहार में यह अभियान शुरू भी कर चुके हैं और सफल होते दिख रहे हैं. जब ऐसा अभियान बिहार में सफल हो सकता है तो अन्य जगहों पर भी हो सकता है. पिछले साल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इस दिशा में कदम उठाए गए थे. लेकिन फ़िलहाल सबकी निगाहें नीतीश की ओर हैं. उन्होंने राज्य के सभी आईएएस अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा कर दें. ऐसा माना जा रहा है कि वह अपने उस वादे को पूरा कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि भ्रष्ट बाबुओं की संपत्ति ज़ब्त की जाएगी. अब देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि बिहार के बाबू ऐसा करते हैं या नहीं.

फाइल गुम जांच जारी

भारतीय वायु सेना ने आंतरिक जांच में अपने अधिकारियों को क्लीन चिट तो दे दी है, फिर भी गुम हुई फाइल का रहस्य गहराता जा रहा है. टॉप सीक्रेट वाली यह फाइल, जिसमें काम्बेट जेट की खरीदारी से जुड़ी सूचना थी, बाहर पहुंच गई. जबकि रक्षा मंत्रालय के बाबू इस बात पर अड़े हुए हैं कि इस फाइल में कोई बहुत महत्वपूर्ण सूचना नहीं थी. फिर भी रक्षा मंत्री ए के एंटोनी ने जल्दबाजी में मंत्रालय की ओर से जांच की घोषणा कर दी. इस जांच का परिणाम अब तक सामने नहीं आया है. सूत्रों का कहना है कि शक की सुई मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के एक आईएएस अधिकारी की तरफ घूमी हुई है. हालांकि अब तक किसी का नाम सामने नहीं आया है.

पीसीएस अधिकारियों के लिए ख़ुशख़बरी

ज़्यादातर राज्य लोक सेवा अधिकारियों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होना किसी सपने से कम नहीं होता. उदाहरण के लिए कर्नाटक में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को राज्य के अंदर ही आईएएस कैडर में शामिल करने के लिए सिर्फ 5 ही रिक्तियां होती हैं. यानी हर साल राज्य प्रशासनिक सेवा के 5 बाबुओं को आईएएस कैडर में जगह मिलती रही है. हालांकि इस साल राज्य सेवा के इन अधिकारियों के पास ख़ुश होने की एक ज़बरदस्त वजह है. येदुरप्पा सरकार को आईएएस कैडर के 26 रिक्त पद भरने हैं. मुख्य सचिव एस वी रंगनाथ के मुताबिक, राज्य सेवा के बाबुओं को पिछले दो सालों से कुछ क़ानूनी अड़चनों की वजह से पदोन्नति नहीं दी जा रही थी. इस बीच राज्य सेवा के 10 बाबू रिटायर भी हो चुके हैं. ज़ाहिर है, प्रशासनिक कार्यालयों में अधिकारियों की कमी है और इसे भरना ज़रूरी हो गया है.

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

हुडको सीएमडी की दौड़ में आगे वीपी

आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के तहत आने वाले संगठन हुडको के लिए नए सीएमडी की तलाश जारी है. ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी वी पी बलिगार का चयन इस पद के लिए हो सकता है. मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉ. पी के मोहंती के पास अभी इस पद का अतिरिक्त प्रभार है.

गुजराल एनएचएआई चेयरमैन!

वर्ष1976 बैच के आईएएस अधिकारी आई एस गुजराल राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के नए चेयरमैन बन सकते हैं. गुजराल अभी सड़क परिवहन मंत्रालय में सचिव के पद पर तैनात हैं. 31 दिसंबर, 2010 को बृजेश्वर सिंह का कार्यकाल खत्म होने के बाद गुजराल एनएचएआई चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार भी देख रहे हैं.

आनंद को एक साल और

केरल कैडर और 1977 बैच के आईएएस अधिकारी आनंद बोस, जो अभी संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं, को एक साल का सेवा विस्तार और मिल सकता है. उनका कार्यकाल 15 जनवरी को खत्म हो चुका है. यह पद अतिरिक्त सचिव के समकक्ष है.

राव जा सकते हैं दूरसंचार विभाग

एस आर राव अभी सूचना तकनीक विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं. 1978 बैच के इस आईएएस अधिकारी का तबादला दूरसंचार विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर हो सकता है. उन्हें 1977 बैच के आईएएस अधिकारी सुबोध कुमार की जगह भेजा जा सकता है.

रंधावा होंगे नए डीजी?

क्या टी एस रंधावा खेल मंत्रालय के तहत आने वाले संगठन भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के नए महानिदेशक बनाए जा सकते हैं? अंदरखाने से खबर आ रही है कि रंधावा जल्द ही भारत सरकार में शामिल हो सकते हैं और उन्हें इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है. यह पद सयान चटर्जी के जाने के बाद से रिक्त है. सयान स्वास्थ्य मंत्रालय में नाको सचिव के पद पर चले गए हैं.

मनमोहन-सोनिया के मतभेद

पृष्ठ 1 का शेष

तक अफ़वाह भी नहीं फैली है. कपिल सिब्बल सोनिया गांधी की पसंद नहीं हैं, लेकिन मनमोहन सिंह ने जैसे अंबिका सोनी के बारे में सोनिया की नहीं सुनी, वैसे ही सिब्बल के बारे में उनकी नहीं सुनी. राहुल गांधी और सोनिया गांधी चिदंबरम को भी पसंद नहीं कर रहे, पर मनमोहन सिंह उन्हें बनाए रखना चाहते हैं. अश्विनी कुमार को भी प्रधानमंत्री ने अपनी मर्ज़ी से राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया है.

अब आपको बताते हैं कि किन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होना था. इन सबकी आईबी क्लियरेंस प्रधानमंत्री ने मंगा ली थी. इनमें पहला नाम एम ए खान का है, जिन्हें तेलंगाना की वजह से मंत्रिमंडल में लिया जाना था. यह शिया समाज से ताल्लुक़ रखते हैं. दूसरा नाम परवेज़ हाशमी का है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, लेकिन जिन्हें राहुल गांधी ने मंत्रिमंडल में जाने नहीं दिया. परवेज़ राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश ऑपरेशन में दिग्विजय सिंह के बाद दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं. तीसरा नाम केशव राव का, चौथा नाम जयंती नटराजन और पांचवां नाम चरण दास महंत का है, जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं.

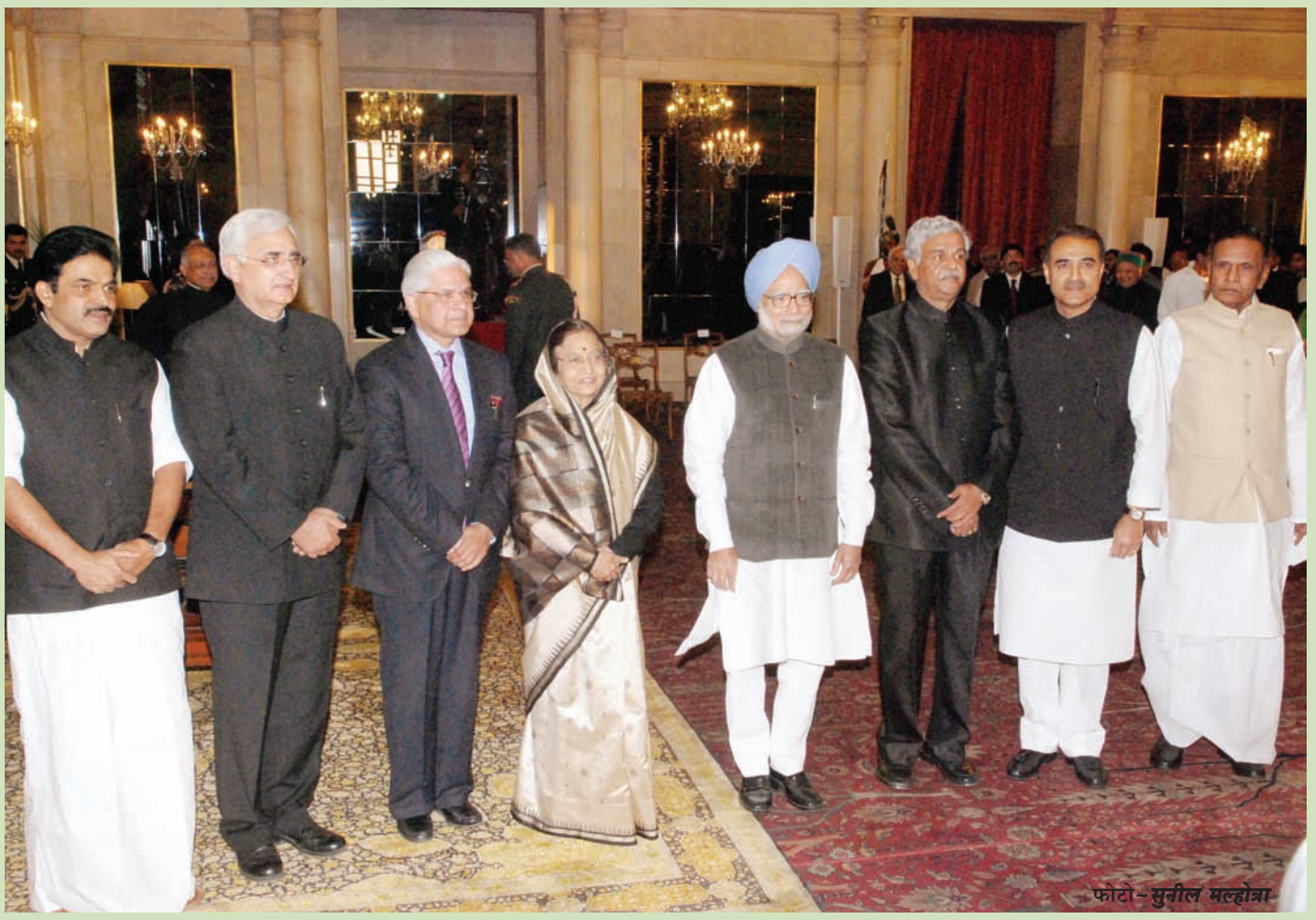

फोटो– सुनील मल्होत्रा

देश के लोगों जैसा आकलन कांग्रेस के लोगों का भी है. उनका मानना है कि अगर यह बदलाव नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि तब प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष के बीच के मतभेद सामने नहीं आते और यह अति बुद्धिमानी भरा काम भी नहीं होता. इस विस्तार से न कोई असर पड़ा, कोई वोट कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ा और जिससे वोट जुड़ता, बेनी प्रसाद वर्मा से, उसे बेइज़्ज़त किया. इतना ही नहीं, कमलनाथ, सीपी जोशी, कांति लाल भूरिया, मुरली देवड़ा, कुमारी शैलजा, अंबिका सोनी, चिदंबरम, अजय माकन ऐसे मंत्रियों के रूप में उभरे हैं, जिन पर दोनों में मतभेद हैं.

तो क्या राहुल गांधी का असर सरकार में है? इसका सीधा जवाब है कि नहीं. सरकार उन्हें अभी परिपक्व नहीं मानती और प्रधानमंत्री, प्रणव मुखर्जी, शरद पवार और चिदंबरम उन्हें किसी लायक नहीं समझते. लेकिन संगठन में राहुल गांधी असरदार हैं. पर राहुल गांधी को, कितने भी मतभेद हो जाएं, कोई प्रधानमंत्री बनाने को तैयार नहीं है. कांग्रेस का इसमें कोई रोल नहीं है. इन चारों के रिश्ते कांग्रेस के लोगों से ज्यादा सहयोगियों से हैं. कोई सहयोगी उन्हें प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है. इसलिए कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह का कोई विकल्प कांग्रेस में नहीं है. प्रणब मुखर्जी को सोनिया गांधी नहीं चाहेंगी.

इस पूरी स्थिति ने कांग्रेस को राज्यों में हास्यास्पद स्थिति में ला दिया है. न प्रधानमंत्री को, न सोनिया गांधी को और न राहुल गांधी के पास समय है कि वे राज्यों के आने वाले चुनावों की रणनीति बनाएं. आंध्र, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, प. बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम और गुजरात ऐसे राज्य हैं, जहां चुनाव होने वाले हैं. इनमें से किस राज्य में कांग्रेस जीत रही है, कोई नहीं कह सकता. आज की तारीख़ में न मनमोहन सिंह कह सकते हैं और न सोनिया गांधी. कांग्रेस के लोगों की यही सबसे बड़ी चिंता है.

देश के लोगों जैसा आकलन कांग्रेस के लोगों का भी है. उनका मानना है कि अगर यह बदलाव नहीं होता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि तब प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष के बीच के मतभेद सामने नहीं आते और यह अति बुद्धिमानी भरा काम भी नहीं होता

मैं जिन लोगों पर भरोसा कर सकता हूं, उनका कहना है कि राहुल गांधी का भी यह मानना है कि अगले छ: महीने या ज़्यादा से ज़्यादा साल भर तक ही यह सरकार चल पाएगी. आंतरिक दबाव बहुत ज़्यादा है. महंगाई और भ्रष्टाचार दो बड़े मुद्दे हैं, जो कांग्रेस पार्टी को हर राज्य में बिहार की गति में ले जाएंगे. अगर एक के बाद एक राज्य हारे तो क्या होगा. और लिख़–टेन–श्टाइन बैंक की सूची में अगर एक केंद्रीय मंत्री का नाम है तो सरकार का क्या होगा. पेट्रोल की क़ीमतों को सरकार ने बाज़ार के हवाले कर दिया. नतीजा यह है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में क्रूड आयल की कीमत कम हुई तो उसके अनुपात में पेट्रोल की क़ीमतों में मामूली कमी हुई, लेकिन जब वहां थोड़ी बढ़त हुई तो यहां जमकर दाम बढ़े. राहुल का नौजवानों को साथ रखने का सपना दम तोड़ रहा है, क्योंकि अस्सी प्रतिशत नौजवान लड़के–लड़कियों के पास मोपेड और मोटर साइकिलें हैं. राहुल इसका ज़िम्मेदार सरकार में उन तत्वों को मानते हैं, जो उन्हें असफल करना चाहते हैं.

इस सारी जानकारी का सार यही है कि कांग्रेस बिना दिमाग़, बिना समझ, बिना सोच और बिना कल्पना शक्ति के अपनी नीतियां तय कर रही है और वैसा ही उसकी सरकार कर रही है. सरकार और कांग्रेस संगठन उस कहावत को उलटा साबित करने में लगे हैं कि ख़ुदा गंजे को नाख़ून नहीं देता, पर यहां तो गंजे को नाख़ून भी दिए हैं और तेज़ नाख़ून दिए हैं. हर फ़ैसला लहूलुहान करने वाला बनता जा रहा है.

editor@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 2 अंक 47
दिल्ली, 31 जनवरी –06 फरवरी 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/11–23418962
विज्ञापन + 91 9810017924
प्रसार + 91 9013478398
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड एवं उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

ख़ास बात यह है कि इन 11 प्रोजेक्ट में से सारे प्रोजेक्ट कांग्रेसी सांसदों या मंत्रियों के क्षेत्र में ही आवंटित किए गए.

पुरा प्रोजेक्ट आवंटन में धांधली

देशमुख के लिए चुनौती होंगे ऐसे अधिकारी

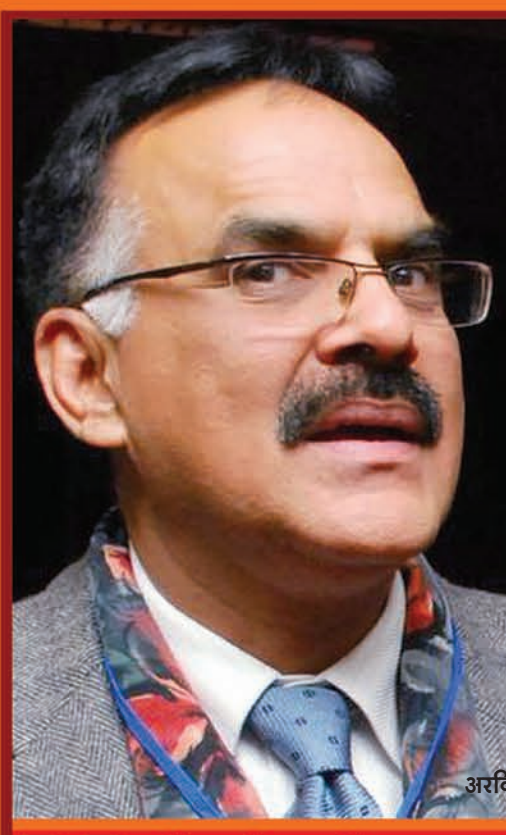

अरविंद मायाराम

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

जयपुर कैडर के अरविंद मायाराम मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव

बेटा जिस कंपनी में, उसे मिले पुरा के तहत तीन प्रोजेक्ट

चार मंत्रियों, बाक़ी कांग्रेस सांसदों के क्षेत्र में दिए प्रोजेक्ट

मनरेगा पर विवादास्पद बयान दे चुके हैं अरविंद मायाराम

गांवों में शहरी सुविधाएं पहुंचाने की योजना पुरा असल में एपीजे अब्दुल कलाम का एक सपना है, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय में बैठे कुछ आईएएस अधिकारियों की वजह से कलाम साहब का यह सपना यानी पुरा शायद अधूरा रह जाए. चौथी दुनिया की ख़ास पड़ताल से पता चलता है कि पुरा के तहत तीन प्रोजेक्ट एक ऐसी कंपनी को आवंटित किए गए हैं, जिसमें मंत्रालय के एक ताक़तवर अधिकारी का बेटा कार्यरत है. इसके अलावा लगभग सारे प्रोजेक्ट कांग्रेसी नेताओं एवं मंत्रियों के क्षेत्र में आवंटित किए गए हैं. ज़ाहिर है, नए ग्रामीण विकास मंत्री विलासराव देशमुख के लिए ऐसे अधिकारियों से निपटना पहली चुनौती साबित होगा.

शशि शेखर

देश की सत्तर फ़ीसदी आबादी की नियति तय कर सकने का अधिकार है ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास. उसके कंधों पर देश के 6 लाख से भी ज़्यादा गांवों के विकास की ज़िम्मेदारी है. सैकड़ों करोड़ों का फंड है, मनरेगा और पुरा जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं भी हैं. ज़ाहिर है, इतने संसाधनों के साथ कोई भी मंत्रालय बेहतर परिणाम देने में सक्षम बन जाता है. फिर भी क्या वजह रही कि मंत्रिमंडल में हुए हालिया फेरबदल में राहुल गांधी के चहेते मंत्री सी पी जोशी का विभाग ही बदल दिया गया. उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय से हटाकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भेज दिया गया. कारण कई थे, जिनकी चर्चा कभी मीडिया में हुई, कभी नहीं हुई, लेकिन चौथी दुनिया की ताज़ा तफ्तीश में जो तथ्य सामने आए, वे बताते हैं कि कैसे इस मंत्रालय में बैठे कुछ आईएएस अधिकारी इतने बेलगाम हो चुके हैं, जिन्हें नियंत्रित कर पाना शायद सी पी जोशी के लिए मुमकिन नहीं था. हालांकि, नए ग्रामीण विकास मंत्री विलासराव देशमुख के लिए भी इन अधिकारियों से निपट पाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा.

चौथी दुनिया द्वारा पुरा योजना से जुड़े कुछ दस्तावेजों की जांच और उनसे जुड़े अन्य तथ्यों की पड़ताल से बहुत चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जो बताते हैं कि कैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक कद्दावर आईएएस अधिकारी, जो मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार की भूमिका में हैं, का बेटा जिस कंपनी में काम करता है, उसे पुरा स्कीम के तहत तीन प्रोजेक्ट आवंटित किए गए. दरअसल, पुरा योजना के तहत पिछले साल यानी 2010 में निजी कंपनियों से निविदाएं मंगाई गई थीं. देश के कुछ हिस्सों में इस पुरा योजना के तहत 11 पायलट प्रोजेक्ट लागू किए जाने थे.

मंत्रालय ने पहले ही घोषणा की थी कि यह योजना पब्लिक–प्राइवेट सहभागिता के आधार पर चलाई जाएगी. यानी निजी कंपनियों के लिए इस योजना में हिस्सेदारी की पर्याप्त गुंजाइश थी. इसलिए कई कंपनियों ने अपनी निविदाएं भेजी. ग्रामीण विकास मंत्रालय में तैनात 1978 बैच और जयपुर कैडर के आईएएस अधिकारी अरविंद मायाराम का नाम सियासी गलियारों में एक ताक़तवर अधिकारी के रूप में लिया जाता है. वह सी पी जोशी के चहेते थे, सो उन्हें मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, दोनों पद मिले हुए हैं. पुरा प्रोजेक्ट आवंटन में अरविंद मायाराम की ही चली. कुल 11 पायलट प्रोजेक्ट के आवंटन के लिए 15 नवंबर, 2010 को मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें मंत्रालय के सचिव, अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार अरविंद मायाराम, संयुक्त सचिव, मुख्य सतर्कता अधिकारी और निदेशक शामिल थे. बैठक में 14 निविदाओं में से 11 को हरी झंडी मिल गई. इन 11 निविदाओं यानी 11 जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट के लिए 6 कंपनियों का चयन किया गया. इनमें से एक कंपनी है आईएल एंड एफएस लिमिटेड. 11 प्रोजेक्ट में से सबसे ज़्यादा तीन प्रोजेक्ट इसी कंपनी को मिले. जबकि किसी भी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा दो ही प्रोजेक्ट मिले.

सवाल उठता है कि इस कंपनी में ऐसी क्या ख़ास बात थी कि इसे 3 प्रोजेक्ट मिल गए? दरअसल, मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अरविंद मायाराम के बेटे अभिनव मायाराम आईएल एंड एफएस फाइनेंसियल सर्विसेज में नवंबर, 2009 से काम कर रहे हैं. यह कंपनी अलग–अलग क्षेत्रों में काम करती है. प्रोजेक्ट के लिए 2010 के मध्य में निविदाएं मंगाई जाती हैं और साल के आख़िर में आईएल एंड एफएस लिमिटेड को तीन प्रोजेक्ट आवंटित कर दिया जाता है. ज़ाहिर है, इस आवंटन पर शक़ की पर्याप्त गुंजाइश बनती है. क्या इस बात से इंकार किया जा सकता है कि अरविंद मायाराम ने अपने बेटे का करियर बेहतर बनाने के लिए उक्त कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट दिलाने की कोशिश न की हो. वैसे भी इस तरह के सरकारी कामों में कितनी पारदर्शिता की उम्मीद की जा सकती है. वह भी तब, जब ऐसे प्रोजेक्ट का ख़र्च करोड़ों में हो.

ख़ास बात यह है कि इन 11 प्रोजेक्ट में से सारे प्रोजेक्ट कांग्रेसी सांसदों या मंत्रियों के क्षेत्र में ही आवंटित किए गए. मसलन, राजस्थान में जयपुर और राजसमंद के लिए दो प्रोजेक्ट आवंटित किए गए. जयपुर के सांगानेर से अरविंद मायाराम की मां इंदिरा मायाराम कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं. वहीं राजसमंद सी पी जोशी का निर्वाचन क्षेत्र रह चुका है. पुदुचेरी, शिवगंगा एवं मल्लापुरम के लिए भी प्रोजेक्ट आवंटित किए गए हैं. पुदुचेरी का प्रतिनिधित्व संसदीय मामले और कार्मिक मंत्रालय में राज्यमंत्री वी नारायणसामी करते हैं तो शिवगंगा गृहमंत्री पी चिदंबरम का संसदीय क्षेत्र है. मल्लापुरम विदेश राज्यमंत्री ई अहमद का संसदीय क्षेत्र है. एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र अमेठी में भी प्रोजेक्ट आवंटित किया गया है, जिसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी करते हैं. हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अमेठी में यह प्रोजेक्ट लागू करने के लिए एनओसी नहीं दिया. बाकी बचे प्रोजेक्ट भी कांग्रेसी सांसदों के क्षेत्र के लिए ही आवंटित किए गए हैं.

ज़ाहिर है, पुरा प्रोजेक्ट आवंटन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. नए ग्रामीण विकास मंत्री विलासराव देशमुख के लिए सबसे बड़ी चुनौती ऐसे अधिकारियों को क़ाबू में रखने की होगी, जिनके रहते शायद ग्रामीण भारत की तस्वीर और तक़दीर दोनों ही बदरंग बनी रहेगी. ज़रूरत इस बात की है कि इस खुलासे के ज़रिए उठाए जा रहे सवालों पर नए मंत्री महोदय ध्यान दें, ताकि कलाम साहब का सपना पूरा हो सके.

shashishekhar@chauthiduniya.com

किसे और कहां आवंटित हुआ प्रोजेक्ट

- आईएल एंड एफएस लि.–जयपुर–इंदिरा मायाराम (अरविंद मायाराम की मां) यहां से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं.
- आईएल एंड एफएस लि.–राजसमंद– सी पी जोशी यहां से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं.
- आईएल एंड एफएस लि.–देहरादून–कांग्रेसी सांसद विजय बहुगुणा के संसदीय क्षेत्र टिहरी गढ़वाल में.
- इंफ्रास्ट्रक्चर केरल लि.–त्रिचूर–कांग्रेस सांसद पी सी चाको का संसदीय क्षेत्र.
- इंफ्रास्ट्रक्चर केरल लि.–मल्लापुरम–विदेश राज्यमंत्री ई अहमद का संसदीय क्षेत्र.
- मार्ग लि.–करईकल, पुदुचेरी–कार्मिक राज्यमंत्री नारायण सामी का संसदीय क्षेत्र.
- मार्ग लि.–कांचीपुरम–कांग्रेस सांसद पी विश्वनाथन का संसदीय क्षेत्र.
- मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लि.–जिला कृष्णा.
- श्रेई (एसआरईआई) इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लि.–शिवगंगा– गृहमंत्री पी चिदंबरम का संसदीय क्षेत्र.
- श्रेई (एसआरईआई) इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लि.–छत्रपति शाहू जी महाराज नगर (अमेठी)–राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र.
- एसवीईसी–वारंगल– कांग्रेस सांसद राजैय्या श्रीसिला का संसदीय क्षेत्र

यहां आवंटित हुए पुरा प्रोजेक्ट

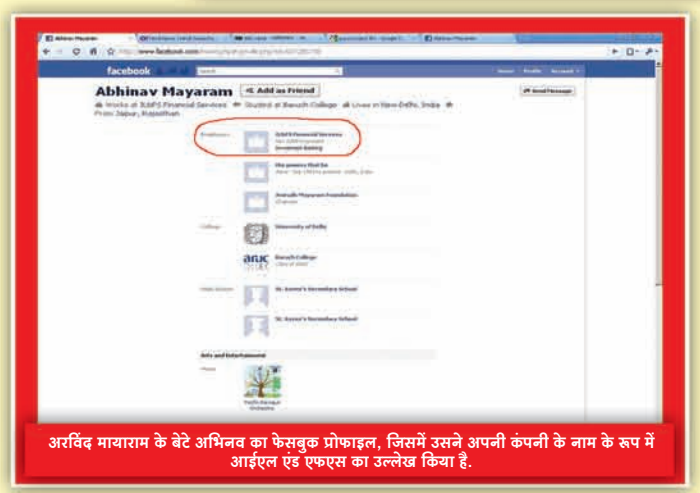

अरविंद मायाराम के बेटे अभिनव का फेसबुक प्रोफाइल, जिसमें उसने अपनी कंपनी के नाम के रूप में आईएल एंड एफएस का उल्लेख किया है.

क्या है पुरा

पुरा (पीयूआरए) यानी प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटिज इन रूरल एरिया. इसका अर्थ हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना. पुरा दरअसल एपीजे अब्दुल कलाम की सोच है, जब वह राष्ट्रपति थे. लेकिन कई सालों तक सरकार चुप्पी साधे रही. आख़िरकार मार्च, 2010 में इस योजना को लागू करने के बारे में सोचा गया. इसकी जिम्मेदारी मिली ग्रामीण विकास मंत्रालय को. मार्च 2010 में ही मंत्रालय की ओर से घोषणा की गई कि पब्लिक–प्राइवेट सहभागिता के आधार पर देश के कुछ हिस्सों में पहले पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी. प्रोजेक्ट के तहत गांवों में पीने का साफ पानी, स्ट्रीट लाइट, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं दूरसंचार सुविधाएं पहुंचाए जाने की बात कही गई. अंतत: 2010 के आखिरी महीने में देश के 11 शहरों को इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया.

अरविंद मायाराम और विवाद

चौथी दुनिया की ख़ास पड़ताल से यह ख़ुलासा होता है कि कैसे अरविंद मायाराम जैसे ताक़तवर आईएएस अधिकारी ने उस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया, जिसमें उसका बेटा मुलाजिम है. इसके अलावा कुछ और ऐसी घटनाएं हैं, जो इस अधिकारी का सच सामने लाती हैं. मसलन, मनरेगा को लेकर अरविंद मायाराम का रवैया शुरू से ही मज़दूर विरोधी रहा. मंत्रालय में इनकी हैसियत का अंदाज़ा एक घटना से लगाया जा सकता है. सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर कहा था कि कुछ राज्यों में मनरेगा के तहत मज़दूरों को तय मेहनताने से भी कम मज़दूरी दी जा रही है. इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है. साथ ही मनरेगा के तहत न्यूनतम मेहनताना बढ़ाए जाने की ज़रूरत है. इस मामले में अरविंद मायाराम द्वारा तैयार नोट के आधार पर प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी की सलाह अस्वीकार कर दी. दरअसल, अपने नोट में मायाराम ने मेहनताना बढ़ाने के रास्ते में आने वाली वित्तीय समस्याओं का ज़िक्र किया था. यह अलग बात है कि बाद में मेहनताना बढ़ा दिया गया. 2009 में भी मायाराम ने वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के मनरेगा से जुड़े एक बयान को झूठा साबित करने की कोशिश की थी. दरअसल, मुखर्जी ने 2009 में अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार मनरेगा के तहत कम से कम 100 रुपये की मज़दूरी देने के लिए कृतसंकल्प है. बाद में मायाराम ने कहा कि सरकार ने यह कहा था कि हम 100 रुपये मेहनताना देने के लिए कृतसंकल्प हैं, न कि देंगे. बहरहाल, इन सारी घटनाओं से साबित हो जाता है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय में जब तक ऐसे अधिकारी तैनात रहेंगे, तब तक गांवों का विकास महज़ एक सपना ही रहेगा.

गौ हत्या और सुअर हत्या की आड़ में अंग्रेज़ों को हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने का भी मौक़ा मिल गया. इस दौरान हिंदू संगठनों ने गौ हत्या के ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ दी.

कब लगेगा गौ हत्या पर प्रतिबंध

फिरदौस ख़ान

भारत में गौ हत्या को लेकर कई आंदोलन हुए हैं और कई आज भी जारी हैं, लेकिन किसी में भी कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हो सकी. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें जनांदोलन का रूप नहीं दिया गया. यह कहना क़तई ग़लत न होगा कि ज़्यादातर आंदोलन सिर्फ़ अपनी सियासत चमकाने या चंदा उगाही तक सीमित रहे. अल कबीर स्लास्टर हाउस में रोज़ हज़ारों गाय काटी जाती हैं. कुछ साल पहले हिंदुत्ववादी संगठनों ने इसके ख़िलाफ़ मुहिम भी छेड़ी थी, लेकिन जैसे ही यह बात सामने आई कि इसका मालिक ग़ैर मुसलमान है तो अभियान को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. जगज़ाहिर है, गौ हत्या से सबसे बड़ा फ़ायदा तस्करों एवं गाय के चमड़े का कारोबार करने वालों को होता है. इनके दबाव के कारण ही सरकार गौ हत्या पर पाबंदी लगाने से गुरेज़ करती है. वरना क्या वजह है कि जिस देश में गाय को माता के रूप में पूजा जाता हो, वहां सरकार गौ हत्या रोकने में नाकाम है.

ग़ौरतलब है कि देश में बड़े पैमाने पर गौकशी होती है. यह सब गौ मांस और उसके अवशेषों के लिए किया जाता है, जिससे भारी मुनाफ़ा होता है. मांस के लिए गायों को तस्करी के ज़रिए पड़ोसी देशों में भेजा जाता है. इस सबकी वजह से सवा अरब से ज़्यादा की आबादी वाले इस देश में दुधारू पशुओं की तादाद महज़ 16 करोड़ है. केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ़ एनिमल हसबेंडरी के मुताबिक़, 1951 में 40 करोड़ की आबादी पर 15 करोड़ 53 लाख पशु थे. इसी तरह 1962 में 93 करोड़ की आबादी पर 20 करोड़ 45 लाख, 1977 में 19 करोड़ 47 लाख, 2003 में 18 करोड़ 51 लाख 80 हज़ार पशु बचे और 2009 में यह तादाद घटकर महज़ 16 करोड़ रह गई. पशुधन विभाग के मुताबिक़, उत्तर प्रदेश में 314 वधशालाएं हैं. इनकी वजह से हर साल लाखों पशु कम हो रहे हैं. केरल में 2002 में एक लाख 11 हज़ार 665 दुधारू पशु थे, जो 2003 में घटकर 64 हज़ार 618 रह गए. राजधानी दिल्ली में 19.13 फ़ीसदी दुधारू पशु कम हुए हैं, जबकि गायों की दर 38.63 फ़ीसदी घटी है. यहां महज़ छह हज़ार 539 गाय हैं, जबकि दो लाख तीन हज़ार भैंसें हैं. मिज़ोरम में 34 हज़ार 988 गाय एवं सांड हैं, जो पिछले साल के मुक़ाबले 1.60 फ़ीसदी कम हैं. तमिलनाडु में 55 लाख 93 हज़ार 485 भैंसें और 16 लाख 58 हज़ार 415 गाय हैं.

हैरत की बात यह है कि गौ हत्या पर पाबंदी लगाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है. इसके बावजूद अभी तक इस पर कोई विशेष अमल नहीं किया गया, जबकि मुस्लिम शासनकाल में गौ हत्या पर सख्त पाबंदी थी. क़ाबिले ग़ौर है कि भारत में मुस्लिम शासन के दौरान कहीं भी गौकशी को लेकर हिंदू और मुसलमानों में टकराव देखने को नहीं मिलता. अपने शासनकाल के आख़िरी साल में जब मुगल बादशाह बाबर बीमार हो गया तो उसके प्रधान ख़लीफ़ा निज़ामुद्दीन के हुक्म पर सिपहसालार मीर बाक़ी ने अवाम को परेशान करना शुरू कर दिया. जब इसकी ख़बर बाबर तक पहुंची तो उन्होंने क़ाबुल में रह रहे अपने बेटे हुमायूं को एक पत्र लिखा. बाबरनामे में दर्ज इस पत्र के मुताबिक़, बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को नसीहत करते हुए लिखा-हमारी बीमारी के दौरान मंत्रियों ने शासन व्यवस्था बिगाड़ दी है, जिसे बयान नहीं किया जा सकता. हमारे चेहरे पर कालिख पोत दी गई है, जिसे पत्र में नहीं लिखा जा सकता. तुम यहां आओगे और अल्लाह को मंजूर होगा, तब रूबरू होकर कुछ बता पाऊंगा. अगर हमारी मुलाक़ात अल्लाह को मंजूर न हुई तो कुछ तजुर्बे लिख देता हूं, जो हमें शासन व्यवस्था की बदहाली से हासिल हुए हैं, जो तुम्हारे काम आएंगे.

1. तुम्हारी ज़िंदगी में धार्मिक भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए. तुम्हें निष्पक्ष होकर इंसाफ़ करना चाहिए. जनता के सभी वर्गों की धार्मिक भावना का हमेशा ख्याल रखना चाहिए.
2. तुम्हें गौ हत्या से दूर रहना चाहिए. ऐसा करने से तुम हिंदुस्तान की जनता में प्रिय रहोगे. इस देश के लोग तुम्हारे आभारी रहेंगे और तुम्हारे साथ उनका रिश्ता भी मज़बूत हो जाएगा.
3. तुम किसी समुदाय के धार्मिक स्थल को न गिराना. हमेशा इंसाफ़ करना, जिससे बादशाह और प्रजा का संबंध बेहतर बना रहे और देश में भी चैन-अमन क़ायम रहे.

हदीसों में भी गाय के दूध को फ़ायदेमंद और मांस को नुक़सानदेह बताया गया है-

1. उम्मुल मोमिनीन (हजरत मुहम्मद साहब की पत्नी) फरमाती हैं कि नबी-ए-करीम हज़रत मुहम्मद सल फ़रमाते हैं कि गाय का दूध व घी फ़ायदेमंद है और गोश्त बीमारी पैदा करता है.
2. नबी-ए-करीम हज़रत मुहम्मद सल. फ़रमाते हैं कि गाय का दूध फ़ायदेमंद है, घी इलाज है और गोश्त से बीमारी बढ़ती है.

(इमाम तिबरानी व हयातुल हैवान)

3. नबी-ए-करीम हजरत मुहम्मद सल. फ़रमाते हैं कि तुम गाय के दूध और घी का सेवन किया करो और गोश्त से बचो, क्योंकि इसका दूध और घी फ़ायदेमंद है और इसके गोश्त से बीमारी पैदा होती है.

(इबने मसूद रज़ी व हयातुल हैवान)

4. नबी-ए-करीम हज़रत मुहम्मद सल. फ़रमाते हैं कि अल्लाह ने दुनिया में जो भी बीमारियां उतारी हैं, उनमें से हर एक का इलाज भी दिया है. जो इससे अंजान है वह अंजान ही रहेगा. जो जानता है, वह जानता ही रहेगा. गाय के घी से ज़्यादा स्वास्थ्यवर्द्धक कोई चीज़ नहीं है.

(अब्दुल्लाबि मसूद हयातुल हैवान)

क़ुरआन में कई आयतें ऐसी हैं, जिनमें दूध और ऊन देने वाले पशुओं का ज़िक्र किया गया है.

भारत में गौ हत्या को बढ़ावा देने में अंग्रेज़ों ने अहम भूमिका निभाई. जब 1700 ई. में अंग्रेज़ भारत आए थे, उस वक़्त यहां गाय और सुअर का वध नहीं किया जाता था. हिंदू गाय को पूजनीय मानते थे और मुसलमान सुअर का नाम तक लेना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अंग्रेजों को इन दोनों ही पशुओं के मांस की ज़रूरत थी. इसके अलावा वे भारत पर क़ब्ज़ा करना चाहते थे. उन्होंने मुसलमानों को भड़काया कि क़ुरआन में कहीं भी नहीं लिखा है कि गाय की क़ुर्बानी हराम है. इसलिए उन्हें गाय की क़ुर्बानी करनी चाहिए. उन्होंने मुसलमानों को लालच भी दिया और कुछ लोग उनके झांसे में आ गए. इसी तरह उन्होंने दलित हिंदुओं को सुअर के मांस की बिक्री कर मोटी रकम कमाने का झांसा दिया. ग़ौरतलब है कि यूरोप दो हज़ार बरसों से गाय के मांस का प्रमुख उपभोक्ता रहा है. भारत में अपने आगमन के साथ ही अंग्रेज़ों ने यहां गौ हत्या शुरू करा दी. 18वीं सदी के आख़िर तक बड़े पैमाने पर गौ हत्या होने लगी. अंग्रेज़ों की बंगाल, मद्रास और बंबई प्रेसीडेंसी सेना के रसद विभागों ने देश भर में कसाईखाने बनवाए. जैसे-जैसे यहां अंग्रेज़ी सेना और अधिकारियों की तादाद बढ़ने लगी, वैसे-वैसे गौ हत्या में भी बढ़ोत्तरी होती गई.

गौ हत्या और सुअर हत्या की आड़ में अंग्रेज़ों को हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने का भी मौक़ा मिल गया. इस दौरान हिंदू संगठनों ने गौ हत्या के ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ दी. आख़िरकार महारानी विक्टोरिया ने वायसराय लैंस डाउन को पत्र लिखा. महारानी ने कहा, हालांकि मुसलमानों द्वारा की जा रही गौ हत्या आंदोलन का कारण बनी है, लेकिन हक़ीक़त में यह हमारे ख़िलाफ़ है, क्योंकि मुसलमानों से कहीं ज़्यादा गौ वध हम कराते हैं. इसके ज़रिए ही हमारे सैनिकों को गौ मांस मुहैया हो पाता है. आख़िरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने भी 28 जुलाई, 1857 को बकरीद के मौक़े पर गाय की क़ुर्बानी न करने का फ़रमान जारी किया था. साथ ही चेतावनी दी थी कि जो भी गौ वध करने या कराने का दोषी पाया जाएगा, उसे मौत की सज़ा दी जाएगी. इसके बाद 1892 में देश के विभिन्न हिस्सों से सरकार को हस्ताक्षरयुक्त पत्र भेजकर गौ वध पर रोक लगाने की मांग की जाने लगी. इन पत्रों पर हिंदुओं के साथ मुसलमानों के भी हस्ताक्षर होते थे. इस समय भी देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और भारतीय गौवंश की रक्षा के लिए कठोर क़ानून बनाए जाने की मांग की जा रही है.

गाय की रक्षा के लिए अपनी जान देने में भारतीय मुसलमान किसी से पीछे नहीं हैं. उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले के गांव नंगला झंडा निवासी डॉ. राशिद अली ने गौ तस्करों के ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ रखी थी, जिसके चलते 20 अक्टूबर, 2003 को उन पर जानलेवा हमला किया गया और उनकी मौत हो गई. उन्होंने 1998 में गौ रक्षा का संकल्प लिया था और तभी से डॉक्टरी का पेशा छोड़कर वह अपनी मुहिम में जुट गए थे. गौ वध को रोकने के लिए विभिन्न मुस्लिम संगठन भी सामने आए हैं. दारूल उलूम देवबंद ने एक फ़तवा जारी करके मुसलमानों से गौ वध न करने की अपील की है. दारूल उलूम देवबंद के फतवा विभाग के अध्यक्ष मुती हबीबुर्रहमान का कहना है कि भारत में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है. इसलिए मुसलमानों को उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए गौ वध से ख़ुद को दूर रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि शरीयत किसी देश के क़ानून को तोड़ने का समर्थन नहीं करती. क़ाबिले ग़ौर है कि इस फ़तवे की पाकिस्तान में कड़ी आलोचना की गई थी. इसके बाद भारत में भी इस फ़तवे को लेकर ख़ामोशी अख्तियार कर ली गई.

गाय भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है. यहां गाय की पूजा की जाती है. यह भारतीय संस्कृति से जुड़ी है. महात्मा गांधी कहते थे कि अगर निस्वार्थ भाव से सेवा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहीं देखने को मिलता है तो वह गौ माता है. गाय का ज़िक्र करते हुए वह लिखते हैं, गौ माता जन्म देने वाली माता से श्रेष्ठ है. हमारी माता हमें दो वर्ष दुग्धपान कराती है और यह आशा करती है कि हम बड़े होकर उसकी सेवा करेंगे. गाय हमसे चारे और दाने के अलावा किसी और चीज़ की आशा नहीं करती. हमारी मां प्राय: रूग्ण हो जाती है और हमसे सेवा की अपेक्षा करती है. गौ माता शायद ही कभी बीमार पड़ती है. वह हमारी सेवा आजीवन ही नहीं करती, अपितु मृत्यु के बाद भी करती है. अपनी मां की मृत्यु होने पर हमें उसका दाह संस्कार करने पर भी धनराशि व्यय करनी पड़ती है. गौ माता मर जाने पर भी उतनी ही उपयोगी सिद्ध होती है, जितनी अपने जीवनकाल में थी. हम उसके शरीर के हर अंग-मांस, अस्थियां, आंतों, सींग और चर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह बात जन्म देने वाली मां की निंदा के विचार से नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह दिखाने के लिए कह रहा हूं कि मैं गाय की पूजा क्यों करता हूं.

ग़ौरतलब है कि उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां सरकार ने गौ हत्या एक्ट में संशोधन कर सज़ा को दस साल करने का प्रावधान किया है. पिछले साल पंजाब में गौ सेवा बोर्ड ने गौ हत्या रोकने के लिए दस साल की सज़ा का प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री के पास भेजा था, जिसे विधानसभा से मंज़ूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति को भेजा जा चुका है. इसके अलावा गौ सेवा बोर्ड के प्रस्ताव में राजाओं द्वारा गौधन की सेवा के लिए दान दी गई ज़मीनों को भू-माफ़ियाओं के क़ब्ज़े से छुड़ाने, सुप्रीमकोर्ट एवं हाईकोर्ट के गौधन संबंधी आदेश लागू करना भी शामिल है. जम्मू-कश्मीर सरकार ने भी गौ हत्या और गौ तस्करी रोकने के लिए कड़े क़दम उठाए थे. दरअसल भारत में गौ वध रोकने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जाने की ज़रूरत है. मुसलमान तो गाय का गोश्त खाना छोड़ देंगे, लेकिन गाय के चमड़े का कारोबार करने वाले क्या इससे हो रही मोटी कमाई छोड़ने के लिए तैयार हैं. इस बात में कोई दो राय नहीं कि गौ हत्या से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ग़ैर मुसलमानों को है और उन्हीं के दबाव में सरकार गौ हत्या पर पाबंदी नहीं लगाना चाहती.

feedback@chauthiduniya.com

हैरत की बात यह है कि गौ हत्या पर पाबंदी लगाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है. इसके बावजूद अभी तक इस पर कोई विशेष अमल नहीं किया गया, जबकि मुस्लिम शासनकाल में गौ हत्या पर सख्त पाबंदी थी. क़ाबिले ग़ौर है कि भारत में मुस्लिम शासन के दौरान कहीं भी गौकशी को लेकर हिंदू और मुसलमानों में टकराव देखने को नहीं मिलता.

भारतीय मुसलमानों का स्वभाव दुर्भाग्य से भावनात्मक है. हमारा शोषण राजनीतिक पार्टियों ने एक लंबे समय तक किया है. हमें असुरक्षित होने के एहसास का शिकार भी सियासी पार्टियों ने ही बनाया.

मुसलमान अपनी लड़ाई भारतीय नागरिक बनकर लड़ें : मदनी

फोटो–प्रभात पाण्डेय

जमीअत उलेमा–ए–हिंद के महासचिव एवं सांसद महमूद मदनी एक सुलझे हुए नेता हैं. वह सिर्फ़ मुस्लिमों की बात नहीं करते, बल्कि पूरे देश के विकास और ख़ुशहाली की बात करते हैं. पिछले दिनों चौथी दुनिया उर्दू की संपादक वसीम राशिद ने विभिन्न मुद्दों पर उनसे एक लंबी बातचीत की. पेश हैं प्रमुख अंश:

आपकी नज़र में इस समय भारतीय मुसलमानों की क्या स्थिति है?

मुसलमान इस समय दोहरे हालात में हैं. भारतीय मुसलमानों की अगर देश के अन्य समुदायों से तुलना करें तो देखेंगे कि वे उनसे पीछे हैं. आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सभी तरह से. तीनों हालात में वे भारत की उन जातियों से भी पीछे हैं, जो अल्पसंख्यक कहलाती हैं. जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय मुसलमानों की क्रीमी लेयर पाकिस्तान चली गई और लेबर क्लास के लोग रह गए या फिर छोटे किसान–मज़दूर. जब मुसलमानों को यह विकल्प मिला कि जो पाकिस्तान जाना चाहे, जा सकता है और जो भारत में रहना चाहे, वह रह सकता है तो उस समय भी सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की संख्या 6 प्रतिशत थी. सवाल यह है कि आज़ादी हासिल होने और क्रीमी लेयर के पाकिस्तान जाने के बाद भी जब हम 6 प्रतिशत थे तो अब 1.6 प्रतिशत कैसे हो गए? इन 63 सालों के दौरान एक विशेष लक्ष्य के तहत लोगों को उनके जायज़ अधिकारों से वंचित रखा गया. नतीजा यह हुआ कि वह क़ौम जो पहले से पिछड़ी हुई थी, वह इस स्थायी व्यवहार के नतीजे में इस दर्जे तक पहुंच गई, जहां बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वह अनुसूचित जनजाति से भी नीचे चली गई है और हालत यह हो गई है कि भारत का मुसलमान यह मांग करने पर मजबूर हो गया है कि उसे आरक्षण मिलना चाहिए. हालांकि मैं भी मानता हूं कि आरक्षण समस्या का हल नहीं है और जो लोग यह कहते हैं, वे सही कहते हैं. वजह, नौकरियों के अवसर प्राइवेट सेक्टर में हैं और अगर योग्यता नहीं होगी तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं मिलेगी. मेरा कहना है कि भले ही आरक्षण के बाद नौकरियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा न हो, लेकिन एक मानसिकता को ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि लोग शिक्षा हासिल नहीं कर रहे हैं. मुसलमान का बच्चा होटल में बर्तन साफ़ करने लग जाता है, रिक्शा चलाता है, ठेले पर मूंगफली बेचता है या फिर मज़दूरी करता है. यह इस वजह से हुआ कि एक मानसिकता सी बन गई है कि नौकरी तो मिलेगी नहीं. यहां तो जान के लाले पड़े हुए हैं. एक लंबे समय तक लोग दंगों का शिकार होते रहे.

क्या मुसलमान अपनी तकलीफें अन्य वर्गों के साथ नहीं बांट सकते?

जब हम मुस्लिम की हैसियत से बात करते हैं तो हमें यह देखना होगा कि क्या समस्याएं सिर्फ़ हमारे साथ हैं, दूसरों के साथ नहीं हैं. मैं हमेशा कहता हूं कि यह तस्वीर का सिर्फ़ एक रुख़ है, जो मैंने बयान किया और जो बिल्कुल उचित है. तस्वीर का दूसरा रुख़ यह है कि भारत के मुसलमान ही सिर्फ़ वंचित नहीं हैं, ऐसे दूसरे वर्ग भी हैं, जो मौलिक अधिकारों से वंचित हैं. ऐसे में अपनी लड़ाई मुसलमान की हैसियत से नहीं, बल्कि भारतीय नागरिक बनकर लड़ी जानी चाहिए और इसमें दूसरे भारतीयों को भी शामिल करना चाहिए. हम अपनी लड़ाई में उन्हें दावत दें और उनकी लड़ाई में हिस्सा लें.

भारत–पाकिस्तान के राजनीतिक संबंध कैसे बेहतर हो सकते हैं, क्या दोनों की आपसी नाराज़गी का असर मुसलमानों पर पड़ता है?

भारतीय मुसलमानों पर भारत–पाकिस्तान के संबंधों का न कोई असर पड़ता है और न पड़ना चाहिए. अगर रिश्तेदारों की बात की जाए, तब भी मुश्किल से एक करोड़ लोगों के रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं, बाक़ी मुसलमानों पर इसका असर नहीं पड़ता. मैं इसे मुसलमानों के मुद्दे के नहीं, बल्कि दो पड़ोसियों के नज़रिए से देखता हूं. पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता. इसलिए दोनों देशों की ज़िम्मेदारी है कि वे शरीफ़, समझदार और ज़िम्मेदार पड़ोसियों की तरह रहें. यह दोनों को मिलकर फ़ैसला करना है और अगर यह फ़ैसला दोनों ठीक तरह से कर लेंगे तो दोनों के फौजी बजट के ख़र्चे कम होकर शिक्षा और स्वास्थ्य में लगाए जा सकेंगे. इसलिए दोनों को जल्द से जल्द अपने गंभीर और विवादित मुद्दे हल करने चाहिए.

भारत जब भी पाकिस्तान से आतंकवाद या किसी दूसरे मुद्दे पर बात करता है तो वह कश्मीर का मसला सीधे–सीधे उठा देता है और हमारे संबंध अधिक ख़राब हो जाते हैं...

ऐसा भी कहना ठीक नहीं है कि सीधे–सीधे उठा देता है, लेकिन यह ठीक है कि यह मसला ऐसा है, जो बीच में फंसा हुआ है. इस मसले को भी हल होना चाहिए, आपसी बातचीत से ही यह मसला हल किया जाना चाहिए.

मुसलमानों में हमेशा से एक अच्छे लीडर की कमी रही है और लीडरशिप की भी, आख़िर क्यों?

भारतीय मुसलमानों का स्वभाव दुर्भाग्य से भावनात्मक है. हमारा शोषण राजनीतिक पार्टियों ने एक लंबे समय तक किया है. हमें असुरक्षित होने के एहसास का शिकार भी सियासी पार्टियों ने ही बनाया. इसीलिए हमें भावनात्मक बनाया गया. सियासी लीडरशिप, हमारे संगठन, हमारा मीडिया किसी न किसी तरह इस षड्यंत्र के शिकार रहे. हम विकास के बजाय भावनात्मक मुद्दों को वरीयता देते हैं. मुसलमान अगर भावना से ऊपर उठकर 20 सालों के लिए अपना एक एजेंडा शिक्षा को बना लें और इसके अलावा कोई बात न करें और वह भी किसी लिंगीय भेदभाव के बग़ैर, क्योंकि जब मां अनपढ़ होगी तो फिर एक नस्ल कैसे शिक्षित हो पाएगी. इसलिए पूरी क़ौम को एक लक्ष्य बनाना होगा. आधी खाएंगे, रुखी–सूखी खाएंगे, बच्चों–बच्चियों को पढ़ाएंगे. इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे, इसके लिए हर क़ुर्बानी देंगे. तब मुसलमानों का शोषण बंद हो जाएगा.

क्या मुसलमानों का कोई ऐसा लीडर है, जिस पर ग़ैर मुस्लिम भी भरोसा कर सकें?

दुर्भाग्य से पूरी मुस्लिम क़ौम ग़ैर मुस्लिमों की नज़र में ऐसी बना दी गई है कि उसे शक की निगाह से देखा जाने लगा है. इसलिए मैं कहूंगा कि यह तो एक ख्वाब है. ख्वाब देखना खराब नहीं है और अगर देख रहे हैं तो ख़ुदा करे, पूरा भी हो जाए.

जमीअत उलेमा मुसलमानों की सबसे बड़ी जमाअत है, लेकिन वह दो हिस्सों में बंट गई. क्या इससे नकारात्मक संदेश नहीं जाएगा?

देखिए दो बातें हैं. पहली यह कि एकता होनी चाहिए, लेकिन किस क़ीमत पर, यह एक मुद्दा है. अगर क़ीमत है सिद्धांतों की तो आप अपने सिद्धांतों को क़ुर्बान करके संगठित हो जाइए तो यक़ीनन यह एकता हर हाल में होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ़ दो जमाअतों के बीच नहीं, बल्कि सारे मुसलमानों के बीच. अब सवाल पैदा होता है कि जब हम सिद्धांतों के ऊपर बात करते हैं तो क्या हम किसी के साथ एकता कर सकते हैं. अगर सिद्धांत बचाकर कोई संगठित हो सकता है तो वह संगठित हो जाए और उसके लिए जो भी व्यक्तिगत बलिदान दिया जाना चाहिए, वह दे दिया जाए, लेकिन जब कोई व्यक्तिगत मुद्दा न हो तो फिर दो ही रास्ते रहते हैं, सिद्धांतों को क़ुर्बान किया जाए या फिर आदमी को. मौलाना अरशद मदनी साहब मेरे चाचा हैं. मेरी बेटी का निकाह उन्होंने ही पढ़ाया. हमारी जमीअत उलेमा के अध्यक्ष की माता का देहांत हुआ तो जनाज़ा मौलाना अरशद मदनी साहब से ही पढ़वाया गया. यह हमारे बीच के आपसी रिश्ते हैं और मौजूदा अध्यक्ष कारी उस्मान साहब मौलाना अरशद साहब के सगे बहनोई हैं. हमारा मतभेद इस बात पर है कि मौलाना कहते हैं कि कमेटी मुझे हटा नहीं सकती और न मुझसे जवाब–तलब कर सकती है. जमीअत उलेमा कहती है कि कमेटी को अधिकार है कि वह उनसे जवाब–तलब कर सकती है और उनके ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकती है. यह जमाअत एक लोकतांत्रिक जमाअत है, जिस तरह हमारा देश लोकतांत्रिक है. देश का प्रधानमंत्री सबसे ताक़तवर व्यक्ति होता है. क्या प्रधानमंत्री यह कह सकते हैं कि संसद मुझे नहीं हटा सकती. यही हालत अरशद मदनी साहब की है, वह कहते हैं कि मुझे कार्यकारिणी समिति हटा नहीं सकती. लोग कहते हैं कि चाचा–भतीजे का झगड़ा है. मैं उस वक़्त भी महासचिव था, जब वह कुछ भी नहीं थे. जब जमाअत ने क़ारी उस्मान साहब को अध्यक्ष बनाया तो अरशद मदनी साहब हट गए, मैंने भी इस्तीफ़ा दे दिया. अब से कुछ दिनों पहले तक मैं जमीअत उलेमा में सिर्फ़ कार्यकारिणी समिति का सदस्य था. अभी फिर ज़िद करके मुझे महासचिव बना दिया गया. हमारी लड़ाई यह है कि कार्यप्रणाली ऊपर रहेगी या व्यक्ति. आज वह यह मान लें कि जमाअत की कार्यप्रणाली को मानेंगे और जो भी फ़ैसला जमाअत करेगी, उसे स्वीकार करेंगे तो हम उन्हें आज भी सिर–आंखों पर बैठाने के लिए तैयार हैं. जहां तक जमाअत के कमज़ोर होने और बिखरने का सवाल है तो ऐसा नहीं है. जमाअत ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला करने के ठीक 42 दिनों बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में सभा की. इसके ठीक 32 दिनों के बाद पैलेस ग्राउंड में, जहां जमीअत ने इससे पहले कभी सभा नहीं की. फिर मुंबई के आज़ाद मैदान में, पालमपुर में, देवबंद में और अभी कश्मीर जैसे संवेदनशील विषय पर फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में. अगर जमाअत विभाजित हुई होती तो हमने 42 आयोजन किए हैं, वह दो तो किए होते. यह बात ज़रूर है कि काग़ज़ यानी अख़बार में वह हमसे ज़्यादा आगे हैं. उनकी सारी मेहनत इस एक मैदान पर लगी हुई है.

क्या आप कांफ्रेंस आदि के अलावा भी कोई ऐसा काम करते हैं, जिससे क़ौम को फ़ायदा हो?

हम गुजरात में अनाथ बच्चों के लिए होम चिल्ड्रेन विलेज चलाते हैं. गुजरात में ही जमीअत ने 5 हज़ार मकान बनाए उन दंगा प्रभावितों के लिए, जो मुसलमान हैं. जमीअत गुजरात में लड़कियों के लिए टीचर्स ट्रेनिंग चला रही है. हमने लड़कियों की मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए मुरादाबाद हाइवे पर 30 एकड़ ज़मीन ख़रीदी है.

क्या कारण है कि जमीअत के काम सामने नहीं आ पा रहे हैं?

हम प्रचार पर मेहनत नहीं करते हैं, हमारा उद्देश्य काम होता है. यह हमारी कमज़ोरी है.

आप पर भारत के मुसलमान बहुत भरोसा करते हैं. अगर आप अपना मीडिया हाउस शुरू करें तो बेहतर नतीजे सामने आ सकते हैं...

अपना मीडिया हाउस होना चाहिए, यह एक ज़रूरत है. यह काम एक प्रोफ़ेशनल कर सकता है और वह क्षमता हमारे पास नहीं है, इसीलिए अभी तक नहीं कर पाए, लेकिन तमन्ना है.

अभी आपने सोनिया गांधी से मुलाक़ात की थी, वह किस सिलसिले में थी?

मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है. इस सिलसिले में हम उनसे पहले भी मिले थे कि मुसलमानों को आरक्षण मिले. एक बार फिर हमने उनसे सांप्रदायिक दंगा निरोधक क़ानून लाने और मुसलमानों के आरक्षण के लिए कुछ करने की मांग की है. उन्होंने वादा किया है कि वह अगले सत्र में सांप्रदायिक दंगा निरोधक क़ानून ले आएंगी और आरक्षण के मामले पर भी कार्यवाही करेंगी. हम लोगों ने उनसे साफ़ तौर पर कहा कि इस पर आपको कोई फ़ैसला जल्द से जल्द करना चाहिए.

रंगनाथ मिश्र आयोग और सच्चर कमेटी की अनुशंसाओं के हवाले से भी कोई बात हुई?

वह अपनी बात पर पूरी तरह अटल हैं. उन्होंने कहा कि यह अधिकार है और यह होना चाहिए. यह किस तरह होगा, इसके लिए उन्होंने एक कोर ग्रुप बनाया है और शायद उसकी रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएगी. हो सकता है कि कोर ग्रुप के साथ हमारी मीटिंग भी हो.

editor.urdu@chauthiduniya.com

किसानों के लिए त्रासद हालत निर्मित कर देने के उक्त कारण केवल मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरे देश में हैं, जिनके चलते 2009 में देश में 17,368 किसानों ने आत्महत्याएं कीं.

मंत्री जी, किसान पागल नहीं हैं

डॉ. रामकृष्ण कुसमारिया

देश की किसी भी संवेदनशील राज्य सरकार के लिए यह कितनी शर्मनाक और हक़ीक़त से मुंह चुराने वाली स्थिति है कि वह प्रदेश में एक के बाद एक मरने वाले किसानों को पागल क़रार देने की हठधर्मिता पर उतर आए और किसानों की आत्महत्याओं को पापों का प्रतिफल बताए. मुसीबत के मारे किसान क़र्ज़ में डूबे हैं, प्रकृति की ज़बरदस्त मार भी पाले के रूप में उन्हें झेलनी पड़ रही है. किसी भी संवेदनशील सरकार को ऐसी मौतों की सच्चाई को झुठलाने की घटिया सियासत से बचना चाहिए. हालांकि इन मौतों की वेदना से पीड़ित होकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मानवीयता का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री से मुलाक़ात करके न केवल किसानों के लिए पांच हज़ार करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मांग की, बल्कि मौत को गले लगाने वाले किसानों के घर जाकर उन्हें दिलासा देते हुए हरसंभव मदद पहुंचाने का आश्वासन भी दिया. हम स्वर्णिम एवं ख़ुशहाल मध्य प्रदेश के दावे चाहे जितने करें, इन दावों की परछाईं में सच्चाई यह है कि प्रदेश में मरने वाले किसानों का ग्राफ तो बढ़ ही रहा है, ग़रीबों की तादाद में भी लगातार इज़ाफ़ा हो रहा है. सच्चाई छिपाने से छिपी न रहकर और विद्रूप रूप में सामने आती है. सीहोर ज़िले की इछावर तहसील के ग्राम बृजेश नगर निवासी किसान शिव प्रसाद मेबाड़ा की आत्महत्या का ब्योरा देते हुए मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि प्रदेश में ऐसे बदतर हालात नहीं हैं कि किसी किसान को क़र्ज़ चुकाने अथवा फ़सल बर्बाद हो जाने के कारण आत्महत्या करनी पड़े. शिव प्रसाद की संपत्ति की फ़ेहरिस्त भी जारी की गई, जिसमें बताया गया कि उसके पास कृषि भूमि और मकान मिलाकर 40–50 लाख रुपये की अचल संपत्ति है. लिहाज़ा वह क़र्ज़ चुकाने में सक्षम था. इसलिए शिव प्रसाद के मरने की यह वजह नहीं है? यही नहीं, तहसीलदार को सरपंच एवं चौकीदार द्वारा दिए बयानों को आधार बनाकर भी राजनीति खेली गई कि 3–4 माह से शिव प्रसाद की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, जो आत्महत्या की प्रमुख वजह बनी. यह सर्वविदित है कि शासन–प्रशासन के लिए इस तरह के बयान दर्ज करना कितनी मामूली बात है.

अभी सीहोर और सागर ज़िलों में आत्महत्या करने वाले किसानों की चिता ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि नरसिंहपुर ज़िले के ग्राम तेंदूखेड़ा निवासी चोखेलाल मेहरा ने रेल से कटकर प्राण दे दिए. इसी दिन दमोह ज़िले के बोरीखुर्द के कनई पटेल ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की. कनई ने चार एकड़ ज़मीन 32 हज़ार रुपये देकर ठेके पर ली थी. यह रकम उसने साहूकार से उधार ली थी. पाले से फ़सल बर्बाद हो गई. मुआवज़ा मिलने की उम्मीद बंधी तो मूल भूमि स्वामी शंकर ने मुआवज़े पर अपना दावा ठोंक दिया. लाचार किसान के पास मरने के अलावा कोई चारा ही नहीं रह गया था. इन किसानों की मौत पर कृषि मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमारिया ने टिप्पणी करते हुए कहा, किसान अपना पिछला पाप ढो रहे हैं. जिस तरह उन्होंने खेतों में रसायनयुक्त दवाओं का इस्तेमाल किया है, उससे खेत तो बर्बाद हुए ही, फ़सलों को भी नुक़सान हो रहा है. अब कुसमारिया को कौन बताए कि जिन रसायनयुक्त दवाओं एवं खादों का इस्तेमाल किसानों ने किया है, उन्हें उपलब्ध तो कृषि विभाग और सहकारी संस्थाओं ने ही कराया. बेचारे किसानों ने इन्हें खेत में तो नहीं उगाया था. यही नहीं, कंपनियों द्वारा उत्पादित बीज, खाद और दवाएं लेना बाध्यकारी भी है. एग्री बिजनेस कंपनियां तो केंद्र सरकार पर ऐसी नीतियां बनाने के लिए दबाव डाल रही हैं, जिनसे खेती के मूल आधार बीज पर उनका आधिपत्य और एकाधिकार हो जाए और फिर वे पूरे देश के किसानों के सामने ज़मीन पूंजीपतियों के हवाले करने के लाचार हालात पैदा कर दें. क्या डॉ. कुसमारिया किसानों को बर्बाद करने की साजिश रचने वाली इन कंपनियों को दुत्कारने और नीति निर्माताओं को ललकारने की ज़हमत उठा पाएंगे?

किसानों की मौत पर कृषि मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमारिया ने टिप्पणी करते हुए कहा, किसान अपना पिछला पाप ढो रहे हैं. जिस तरह उन्होंने खेतों में रसायनयुक्त दवाओं का इस्तेमाल किया है, उससे खेत तो बर्बाद हुए ही, फ़सलों को भी नुक़सान हो रहा है.

सरकारी प्रवक्ताओं को मालूम होना चाहिए कि समाज में किसी भी व्यक्ति का मान–सम्मान उसकी अचल संपत्ति और मज़बूत आर्थिक स्रोतों से होता है. सामाजिक परिवेश में इंसान की काबिलियत तब स्थापित होती है, जब वह अपनी पैतृक आर्थिक हैसियत में इज़ाफ़ा करे, न कि उसे बेचकर क़र्ज़ भार से मुक्त हो जाए. एक ज़िम्मेदार पिता अपनी संतान को पर्याप्त एवं मज़बूत अर्थोपार्जन के संसाधन विरासत में सौंप कर जाने की इच्छा रखता है, न कि कंगाली. ऐसी दुविधा में किसान मरे न तो क्या करे. मौसम की प्रतिकूलता के चलते तो किसान मुसीबत में होता ही है, बेहतर फ़सल होने पर भी उसे उचित क़ीमत नहीं मिलती. खेती के आधुनिकीकरण के चलते किसान को यांत्रिक सुविधाएं तो मिली हैं, लेकिन उतनी समस्याएं भी बढ़ी हैं. बिजली, पानी और डीजल की कमी की लाचारगी तो वह झेलता ही है, ट्रैक्टर, विद्युत मोटर और डीजल पंप में ख़राबी आ जाने पर मरम्मत के लिए उसे शहर भागना पड़ता है, कलपुर्जों और मरम्मत का ख़र्च झेलना पड़ता है. इन कारणों से किसान के लिए आजीविका के जो साधन हैं, वहीं उसके जीवन के लिए दुष्चक्र साबित हो जाते हैं. नकली बीज, खाद और कीटनाशक जहां किसानों के लिए संकट का सबब बन रहे हैं, वहीं चरम पर पहुंचे भ्रष्टाचार और महंगाई के चलते भी वे हिम्मत हार रहे हैं.

किसानों के लिए त्रासद हालत निर्मित कर देने के उक्त कारण केवल मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरे देश में हैं, जिनके चलते 2009 में देश में 17,368 किसानों ने आत्महत्याएं कीं. इनमें से 62 फ़ीसदी घटनाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दर्ज की गईं. सबसे खराब हालात विदर्भ और बुंदेलखंड में देखने को मिले. नतीजतन, इन क्षेत्रों के किसानों को संकट से उबारने के लिए अकेले बुंदेलखंड को राहुल गांधी की पहल पर 71 हज़ार करोड़ रुपये का राहत पैकेज दिया गया था. किसानों की क़र्ज़ माफी के लिए मध्य प्रदेश को 915 करोड़ रुपये मिले थे, लेकिन बंदरबाट के चलते इस राशि का उचित बंटवारा नहीं हुआ. मध्य प्रदेश सरकार ने भी 114 करोड़ रुपये की गड़बड़ी मंजूर की, लेकिन उसने गड़बड़ी करने वाले किसी अधिकारी–कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की. इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब पीड़ित किसान परिवारों के बीच ढांढस बंधाने पहुंचे तो रोती–बिलखती महिलाओं ने उनसे कहा कि भैया, तुम्हीं अइयो पइसा लेकर घर–घर. तुमरे एल्कार (अधिकारी) बीच में ही पइसा खा जात हैं. इस सच्चे बयान का कोई तोड़ है किसी के पास? जब सरकार पूर्व में वितरित की गई राहत राशि में 114 करोड़ रुपये की गड़बड़ी स्वीकार कर रही है तो फिर गड़बड़ी करने वालों को सज़ा क्यों नहीं दे रही? वह उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही क्यों नहीं करती? यदि गड़बड़ी करने वाले फिर केंद्र से मिलने वाली राहत राशि बांटेंगे तो क्या वे गड़बड़ी से बाज आएंगे? दंड का विधान लागू किए बिना शिवराज सिंह उन 20 ज़िलों के किसानों को उचित राहत नहीं पहुंचा सकते, जिनमें 80 प्रतिशत फ़सल की बर्बादी देखकर रोजाना चार किसान आत्महत्या का सिलसिला जारी रखे हुए हैं. आंकड़ों के मुताबिक़, मध्य प्रदेश के क़रीब 11 हज़ार किसान क़र्ज़ में डूबे होने के कारण आत्महत्या कर चुके हैं. उक्त आंकड़े 2009 तक के हैं. यदि किसानों की क़र्ज़ मुक्ति की समस्या के समाधान के लिए शीघ्र ही ईमानदार प्रयास नहीं किए गए तो ऐसी आत्महत्याओं की तादाद बढ़ेगी, साथ ही प्रदेश में वे भयावह हालात देखने में आएंगे, जिनसे निपटना मौजूदा सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल होगा.

प्रमोद भार्गव
feedback@chauthiduniya.com

वैदिक काल में दूषित जल के शमन के भी नियम थे. गड्ढे खोदकर उसे इस प्रकार दबा दिया जाता था, जिससे बीमारी न फैले. गंगा करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है.

गंगोत्री में ही गंगा मैली

गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कथा कौन नहीं जानता. अपने पूर्वजों के तारण के लिए भगीरथ ने कई हज़ार साल तक तपस्या की थी. हालांकि इस कथा को वैज्ञानिकता की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता, किंतु हिमालय की चोटियों को शिव की जटाओं के रूप में माना जाता है. जहां पर वह ग्लेशियरों के रूप में विद्यमान है, वहां से उसका जल नियंत्रित रूप से प्रवाहित होता रहता है.

एल. मोहन कोठियाल

हर धर्म की अपनी मान्यताएं–परंपराएं होती हैं. आस्था को विज्ञान की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता, किंतु ऐसा भी नहीं कि उसमें कोई तर्क न हो. यदि धर्म न हो तो समाज में समरसता, भाईचारा और उल्लास देखने को न मिले. धर्म हमें अनुशासन सिखाता है और अधर्म के मार्ग पर चलने वाले को लगातार सजग करता है. हर धर्म की मान्यताएं अलग हैं, जो स्थान, समय एवं परिस्थितियों के अनुसार रहती हैं. तैंतीस करोड़ देवी– देवताओं की मान्यता वाले हिंदू धर्म में प्रकृति एवं परिवेश को सर्वोपरि और पूजनीय माना गया है. प्रकृति के वे तत्व जो जीने के लिए अपरिहार्य हैं, उन्हें हिंदू धर्म में देवी या देवता का स्थान प्राप्त है. इनमें जल का स्थान सर्वोपरि है और उसे विष्णु का स्थान प्राप्त है. नदियों को पूजनीय माना गया है और गंगा को मां का स्थान मिला है. हिंदू धर्म में यदि गंगा न हो तो कई मान्यताएं उलट हो जाएं. मुंडन से लेकर अंतिम संस्कार तक गंगा ही याद आती है, वहीं गंगा की पूजनीयता का वैज्ञानिक आधार भी है.

गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कथा कौन नहीं जानता. अपने पूर्वजों के तारण के लिए भगीरथ ने कई हज़ार साल तक तपस्या की थी. हालांकि इस कथा को वैज्ञानिकता की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता, किंतु हिमालय की चोटियों को शिव की जटाओं के रूप में माना जाता है. जहां पर वह ग्लेशियरों के रूप में विद्यमान है, वहां से उसका जल नियंत्रित रूप से प्रवाहित होता रहता है. गोमुख से उतरने पर गंगा का वेग बड़ा उग्र होता है, लेकिन जैसे–जैसे वह हिमालय की पहाड़ियों से नीचे उतरती है, उसका वेग मंद पड़ने लगता है. हिमालय से अनेक धाराएं निकलती हैं. गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक नदी की धारा जहां से भी गुजरती है, उन स्थानों की तीर्थ जैसी महिमा है. हिमालय को देवभूमि कहा जाता है, जहां गंगा के तट कई ऋषि–मुनियों की तपस्थली थे. उत्तराखंड में भागीरथी एवं अलकनंदा के किनारे बसे स्थलों को तीर्थ का स्थान हासिल है. कहा जाता है कि गंगोत्री में गंगा का मंदिर वह स्थान है, जहां राजा भगीरथ ने तपस्या की थी. इस मंदिर के दर्शनार्थ प्रति वर्ष लाखों लोग आते हैं. इससे आगे सबसे बड़ा नगर उत्तरकाशी पड़ता है, जो उत्तर की काशी कहा जाता है, जहां भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है. उत्तरकाशी से आगे गंगा टिहरी के डूबने तक गणेश प्रयाग में मिलती थी. बांध बनने के कारण गणेश प्रयाग का अस्तित्व अब नहीं रहा. टिहरी से आगे देव प्रयाग में उसका मिलन अपनी बड़ी बहन अलकनंदा से होता है, जो एक प्रमुख संगम है. यहां से आगे भागीरथी एवं अलकनंदा मिलकर गंगा कहलाती है. मान्यता है कि देव प्रयाग में भगवान श्रीराम ने ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित हेतु तप किया था.

यूं तो गंगा जहां से गुजरती है, वे सब स्थल तीर्थ समान हैं, किंतु गंगा को तीर्थत्व हरिद्वार में प्राप्त होता है. रावण वध के उपरांत श्रीराम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए हरिद्वार आए और फिर गंगा में स्नान करके उन्होंने देव प्रयाग की ओर प्रस्थान किया. मान्यता है कि हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर में स्नान मात्र से ब्रह्मलोक, विष्णुलोक एवं शिवलोक की प्राप्ति होती है. हरिद्वार के अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा हैं, जहां हरि पादुकाएं हैं. हरिद्वार आदिकाल से महात्माओं, ऋषियों एवं साधकों की तपस्थली रहा है. जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ने भी गंगा के तट पर मायापुरी में तपस्या की. कालांतर में शंकराचार्य ने यहां आश्रमों की स्थापना की. हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, बिठूर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना एवं गंगा सागर के तटों पर हर प्रमुख पर्व पर लाखों हिंदू धर्मावलंबी स्नान हेतु आते हैं और पुण्य लाभ की कामना एवं एक नए विश्वास के साथ घर लौटते हैं. ऋग्वेद में गंगा की महिमा का विवरण त्रिपथगा यानी तीन पथों पर चलने वाली नदी के रूप में मिलता है. गंगा का उद्भव स्वर्ग से हुआ, जहां वह पहले प्रवाहमान थी. अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए भगीरथ इसे पृथ्वी पर लाए. इसका तीसरा पथ पाताल लोक में होगा. इसका यह मतलब निकाला जा सकता है कि अत्यधिक दोहन से यह समाप्त हो जाएगी.

भारत के लिए गंगा सिर्फ नदी नहीं, बल्कि एक दर्शन है. कुछ लोग गंगा को जीवनदायिनी मानते हैं तो कुछ मोक्षदायिनी. हरिद्वार एवं प्रयागराज में पर प्रति 12 साल में कुंभ होता है और 6 साल में अर्द्धकुंभ. चार माह तक चलने वाले इन मेलों के दौरान करोड़ों लोग जाति, संप्रदाय एवं पंथ भूलकर गंगा स्नान करते हैं. साधु–संत एवं उनके अखाड़े भी इस अवसर पर जुटते हैं. प्रयागराज अध्यात्म एवं ज्ञान की धाराओं का भी संगम है, जो मोक्ष का मार्ग दिखाता है. मान्यता है कि कुंभ के दौरान प्रयाग में कल्पवास करने से मनुष्य को जीवन–मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है. गंगा आगे विंध्याचल से होते हुए बनारस पहुंचती है.

यहीं श्मशान घाट पर भगवान ने राजपाट गंवा चुके राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली थी. मान्यता है कि बनारस में जीवन त्याग करने से व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान मिलता है. इसीलिए हज़ारों लोग अपने उन बुज़ुर्गों को मृत्यु से पूर्व यहां ले आते हैं. यहां के मणिकर्णिका एवं हरिश्चंद्र घाट पर चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती. गंगाजल की अमृत जैसी महिमा है. गंगाजल को शास्त्रों में सोमरस की संज्ञा दी गई है. सोम मनुष्य के दीर्घजीवन के लिए एक औषधि है. इसी क्षेत्र में अनगिनत जड़ी–बूटियां उत्पन्न होती हैं.

गंगाजल को यदि अमृत समान माना गया है तो उसके पीछे वैज्ञानिक कारण हैं. गंगा की धारा हिमालय की धवल चोटियों से निकलती है. वहीं शिवालिक की पहाड़ियों से निकली लघु जलधाराएं इसके स्वरूप को विस्तारित करती हैं. जिस रास्ते से जलधाराएं गुजरती हैं, वहां के खनिज– लवण इसमें घुलते चले जाते हैं. गंगाजल में कई प्रकार के रोगों से मुक्ति प्रदान करने की क्षमता है. यह ऐसा रोगनाशक है, जो लंबे समय तक रखने के बाद भी ख़राब नहीं होता. गंगाजल की महिमा यह है कि हर पूजा– अनुष्ठान में इसे विघ्न–बाधा दूर करने के लिए चारों दिशाओं में छिड़का जाता है. उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालु अपने साथ गंगाजल ले जाना नहीं भूलते. सम्राट अकबर भी गंगाजल के औषधीय गुणों को मानते थे, इसलिए उनके पीने का पानी हरिद्वार से ऊंटों द्वारा आगरा लाया जाता था. गंगा करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है, इसका जल फ़सलों को जीवन देता है और यह असंख्य लोगों की आजीविका का माध्यम है. विश्व की विभिन्न सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुईं. भारत में भी हिमालय से लेकर गंगा सागर तक अनेक सभ्यताएं बसीं. कवियों, विद्वानों, लेखकों एवं छायाकारों को गंगा के अनेक रूपों ने प्रभावित किया. वर्तमान में कलियुग का प्रथम सोपान चल रहा है और आस्था की प्रतीक गंगा अपवित्र होती जा रही है. यह आशंका अपने अवतरण से पहले गंगा ने राजा भगीरथ के सम्मुख रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं एक और कारण से पृथ्वी पर नहीं जाना चाहती. मुझे लगता है, पृथ्वी के लोग तो मुझमें अपने पाप धो देंगे, लेकिन मैं उन पापों को कहां धोऊंगी? इस पर भगीरथ ने कहा था, हे माता, पृथ्वी पर इच्छा का त्याग करने वाले ब्रह्मनिष्ठ एवं पवित्र लोग भी रहते हैं, जिनमें भगवान का वास है और वे स्नान करके तुम्हारे पापों को भी दूर कर देंगे. लेकिन भगीरथ का वह कथन आज कलियुग में उलटा सिद्ध हो रहा है. भगीरथ जिस लोक कल्याण की भावना से गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, अब वह भावना हमारे कर्णधारों में नहीं दिखती. गंगा पर जबसे भोगवादी दृष्टि पड़ी है, तबसे उसका रसातल की ओर जाने का द्वार मानो खुल गया है.

गंगा आज अपने उद्गम से मैली हो रही है. कई स्थानों पर यह इतनी प्रदूषित है कि इसका जल पीने योग्य नहीं रहा. शहरों की गंदगी गंगा में जाने से रोक पाने में कोई भी सरकार सफल नहीं हो सकी. गंगाजल यदि पवित्र है तो हमें भी उसे पवित्र रखना चाहिए. बड़ी संख्या में लोगों के हिमालय में आने से भी गंगा में कचरे एवं प्लास्टिक की भरमार हो रही है

गंगा आज अपने उद्गम से मैली हो रही है. कई स्थानों पर यह इतनी प्रदूषित है कि इसका जल पीने योग्य नहीं रहा. शहरों की गंदगी गंगा में जाने से रोक पाने में कोई भी सरकार सफल नहीं हो सकी. गंगाजल यदि पवित्र है तो हमें भी उसे पवित्र रखना चाहिए. बड़ी संख्या में लोगों के हिमालय में आने से भी गंगा में कचरे एवं प्लास्टिक की भरमार हो रही है. गंगा में पूजा के नाम पर जो कुछ भी डाला जाता है, उससे गंगाजल दूषित ही होता है. गंगा में फैक्ट्रियों का दूषित जल एवं कचरा जिस प्रकार मिलाया जा रहा है, उससे गंगा विषैले नाले में परिवर्तित हो चुकी है. अधजले शवों, कोयले, लकड़ी और राख आदि से गंगा कितनी प्रदूषित हो रही है, यह कन्नौज, कानपुर, वाराणसी एवं पटना में देखा जा सकता है. आगे अनेक नदियों के मिलने से जलराशि बढ़ जाती है, जिससे उतनी गंदगी नज़र नहीं आती. फरक्का के बाद गंगा का प्रवाह कम हो जाता है, इसकी एक धारा बांग्लादेश चली जाती है. यहां एक बार फिर यह भागीरथी कहलाने लगती है और आगे जाकर हुगली. कोलकाता जैसे महानगर से गुजरने के बाद भी काफी गंदगी इसमें मिलती है. गंगाजल जब तक शुद्ध है, तभी तक यह लाभप्रद है. वैदिककालीन लोग दूषित जल को व्याधियों का कारण मानते थे. उनका कहना था कि शुद्ध जल औषधि समान है, उसके सेवन और उससे स्नान करने से रोगों का नाश होता है.

वैदिक काल में दूषित जल के शमन के भी नियम थे. गड्ढे खोदकर उसे इस प्रकार दबा दिया जाता था, जिससे बीमारी न फैले. गंगा करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है. अमीर अब बोतलबंद पानी इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन ग़रीब ऐसा नहीं कर सकता. सरकार की प्राथमिकता उद्योगों की स्थापना एवं बिजली उत्पादन है. इसलिए आज गंगा की पवित्रता के स्थान पर उसके दोहन की योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है. गंगा की अमृत समान धारा को बिजली की धारा के रूप में देखा जा रहा है. गंगा के अधिक दोहन के परिणाम हम देख रहे हैं. हिमालय को छलनी करके गंगा एवं सहायक नदियों पर अनेक जल विद्युत परियोजनाएं इस प्रकार बन रही हैं कि उनकी कलकल बहती धारा सुरंगों–बांधों में कैद होने को अभिशप्त हो जाएंगी. जहां कभी नदी बहा करती थी, आज वहां सूखी घाटियां नज़र आती हैं. उत्तर भारत की जीवन रेखा मानी जाने वाली गंगा पूरे भारत की सांस्कृतिक छवि का प्रतिबिंब है, एक दर्शन है, जिसकी धारा से मनुष्य के जीवन–मृत्यु के सवाल जुड़े हैं. गंगा का कलकल निनाद एवं निरंतरता उसकी पहचान है. आज जिस प्रकार उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है, उससे उस आस्था का समाप्त होना लगभग तय है, जो हिंदू धर्म का एक प्रमुख आधार है.

feedback@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

कैबिनेट की औसत उम्र कम हो

कैबिनेट में फेरबदल से जुड़ी एक बात मुझे बहुत अजीब लगी. साथ ही इससे मुझे गुस्सा भी आया. दरअसल बात यह है कि कैबिनेट में फेरबदल 14 जनवरी के बाद ही होना तय किया गया. इससे पहले यह संभव नहीं हो सका, क्योंकि पंचांग के मुताबिक़ 14 जनवरी से पहले इस काम के लिए कोई शुभ समय नहीं निकल रहा था. मैंने पता किया है कि 2011 में शादियों के लिए 104 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं और इसमें से एक भी 14 जनवरी से पहले का नहीं है. मैं इसे ग़लत नहीं मानता कि कुछ जोड़े अपनी शादी पंचांग के मुताबिक़ करना पसंद करते हैं, लेकिन क्या कैबिनेट में फेरबदल करने के लिए मुहूर्त का इंतजार करना जायज़ माना जा सकता है? पचास के दशक में जब मैं बड़ा हो रहा था, पंडित नेहरू ने यह साफ़ कर दिया था कि वह किसी भी अंधविश्वास से घृणा करते हैं, फिर भी इंदिरा गांधी तब तक अपने पिता के घर में नहीं गईं, जब तक कि उन्हें एक शुभ मुहूर्त नहीं मिल गया.

सोनिया गांधी के पास पावर है, लेकिन ज़िम्मेदारी नहीं है और मनमोहन सिंह की पास ज़िम्मेदारी है तो पावर नहीं है, अब और अधिक नहीं चल सकती. यह व्यवस्था यूपीए-1 के दौरान तो कामयाब रही, क्योंकि आज के मुक़ाबले तब के गठबंधन के सहयोगियों के कुछ सिद्धांत थे. जैसा कि अब नहीं है. पिछले कुछ महीनों में राजनीति का जन सरोकारों से मानो नाता ख़त्म सा हो गया है.

एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हम प्रत्येक सार्वजनिक सभाओं में दीप प्रज्जवलित (एक हिंदू रिवाज) करते हैं. मैंने नोटिस किया है कि नेता मंदिर और दरगाह की परिक्रमा करते नज़र आते हैं. हालांकि वे किसी ईसाई चर्च में नहीं जाते. रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी देना ख़ुद को धर्मनिरपेक्ष बताने के लिए मानों ज़रूरी हो गया है. हालांकि क्रिसमस या ईस्टर पर ऐसा आयोजन करते हमारे नेता नहीं दिखते. सार्वजनिक जीवन के हरेक पहलू में इस तरह की धार्मिक परंपराओं और ख़ासकर अंकशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का दबदबा साफ़ दिखता है. अपने जीवन के शुरुआती दिनों में, जब हम बड़ौदा से मुंबई आ गए थे, हमने दस सालों में 4 बार मकान बदले. लेकिन मुझे याद नहीं कि इसके लिए एक बार भी हमने वास्तु या फेंगशुई जैसी चीजों का सहारा लिया हो. मेरी मां ने कभी करवा चौथ का चांद नहीं देखा, फिर भी वह एक अच्छी हिंदू पत्नी थीं.

मैं इसलिए भी निराश हूं, क्योंकि यह निश्चित था कि कैबिनेट में फेरबदल सौ फ़ीसदी अप्रभावी और कमज़ोर होगा. सबसे पहले हमने सुना कि प्रधानमंत्री सिर्फ़ अपने कांग्रेसी सहयोगियों को ही इधर से उधर करेंगे, गठबंधन के सहयोगियों (मंत्रियों) को नहीं. ज़ाहिर है, इतने भर से हालत के बेहतर होने की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती थी. तृणमूल को कुछ और मंत्रालय मिल जाते तो मेरे हिसाब से यह तृणमूल के लिए सरकार को बार-बार दी जाने वाली धमकी, कैबिनेट में असहयोगात्मक रवैये और माओवादियों के साथ खुली सोहबत का ईनाम होता.

कैबिनेट में महत्वपूर्ण और गंभीर बदलाव की ज़रूरत थी. यूपीए-2 की गाड़ी के डिब्बे न तो आपस में जुड़े हैं और न नियंत्रण में हैं. पिछले 20 महीनों में सरकार महंगाई पर क़ाबू पाने में पूर्ण रूप से असफल रही है. शायद यह एक बुद्धिमानी भरी राजनीतिक चाल थी. इस बात की जांच के लिए कि जनता कितना और कब तक इस महंगाई को सहन कर सकती है. और वह भी तब, जब हाल-फ़िलहाल सरकार को चुनाव के मैदान में न उतरना हो.

लेकिन यह चाल उल्टी पड़ गई है और अब औद्योगिक वृद्धि की दर गिरने के बाद भारत को मुद्रास्फीति की वजह से पैदा हुई मंदी का सामना करना पड़ रहा है. यह द्विस्तरीय व्यवस्था, जहां सोनिया गांधी के पास पावर है, लेकिन ज़िम्मेदारी नहीं है और मनमोहन सिंह की पास ज़िम्मेदारी है तो पावर नहीं है, अब और अधिक नहीं चल सकती. यह व्यवस्था यूपीए-1 के दौरान तो कामयाब रही, क्योंकि आज के मुक़ाबले तब के गठबंधन के सहयोगियों के कुछ सिद्धांत थे. जैसा कि अब नहीं है. पिछले कुछ महीनों में राजनीति का जन सरोकारों से मानो नाता ख़त्म सा हो गया है. कांग्रेस सरकार में शामिल पार्टी के तौर पर ख़ुद को असहज महसूस कर रही है. कभी वह भाजपा पर हमला करती है और अचानक सरकार से कहती है कि कुछ करो.

मेरे हिसाब से सबसे पहले कैबिनेट की औसत उम्र 70 से घटाकर 45 वर्ष कर देनी चाहिए. राहुल गांधी ज़्यादा समय तक ज़िम्मेदारी से नहीं भाग सकते. उन्हें कोई न कोई पद लेना चाहिए था. मेरा तो मानना है कि उन्हें उप प्रधानमंत्री का पद दिया जाना चाहिए था. आख़िर उन्हें इस काम को कभी न कभी तो सीखना है. उनकी युवा ब्रिगेड के सदस्यों को कैबिनेट में पूर्ण प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए था. इसका अर्थ यह है कि वर्तमान के दस कैबिनेट मंत्रियों को हटा देना चाहिए था. हम सब जानते हैं कि ये कौन लोग हैं. यूपीए-2 में ये लोग अच्छा प्रदर्शन कर पाने में असफल रहे हैं. यह समय उनकी विदाई का है.

feedback@chauthiduniya.com

दस में से नौ भारतीय अप्रवासी हैं

भारत अप्रवासियों का देश है. यहां के मूल निवासी उनके पूर्वज थे, जिन्हें हम आज आदिवासी कहते हैं. इस समय आदिवासी भारत की आबादी का 8 प्रतिशत हैं अर्थात 92 प्रतिशत भारतवासी बाहर से आकर यहां बसे हैं. वे आज से लगभग 10 हज़ार वर्ष पहले उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व से आए थे. औद्योगिक क्रांति के पहले पूरी दुनिया में कृषि मुख्य व्यवसाय था. उस समय भारत कृषकों का स्वर्ग था. यहां कृषि के लिए उपयुक्त वातावरण एवं संसाधन मौजूद थे. इसलिए चारों ओर से लोग भारत में बसने आए. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े इतिहासकारों की यह मान्यता है कि आर्य भारत के मूल निवासी हैं और वे बाहर से नहीं आए हैं. अपने इस दृष्टिकोण को सही साबित करने के लिए वे आदिवासियों को वनवासी कहते हैं. उन्हें वनवासी कहकर वे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि आर्य ही यहां के मूल निवासी हैं और आज के हिंदू आर्यों की संतान हैं. दूसरी ओर अन्य इतिहासकारों का मत है कि आर्य मध्य यूरोप से भारत आकर बसे थे. लोकमान्य तिलक का तो यहां तक कहना था कि आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव था. यह विवाद लंबे समय से जारी है, परंतु पहली बार इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी राय प्रगट की है. बीती पांच जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आर्यों के आने के पूर्व जो लोग भारत में निवास करते थे, आज के आदिवासी उन्हीं की संतान हैं.

खंडपीठ ने इतिहास के अनछुए पहलुओं का सहारा लेते हुए यह दावा किया है कि वास्तव में हमारा देश अप्रवासियों का देश है. हमारे देश की 92 प्रतिशत आबादी अप्रवासियों की संतान है और मात्र आठ प्रतिशत भारतीय 10 हज़ार वर्षों से अधिक समय से भारतीय उप महाद्वीप में रह रहे हैं. पिछले हज़ारों सालों में विश्व के अनेक हिस्सों से लोग यहां आए और बस गए.

सर्वोच्च न्यायालय ने यह राय महाराष्ट्र हाईकोर्ट के एक निर्णय को रद्द करते हुए प्रगट की. इस मामले से यह भी ज़ाहिर होता है कि हम आदिवासियों से किस तरह का व्यवहार करते हैं. इस मामले का संबंध एक भील महिला से है, जिसका नाम नंदबाई है. इस महिला को नंगा किया गया, बुरी तरह पीटा गया और फिर गांव में घुमाया गया. इस महिला पर यह आरोप था कि उसके एक उच्च जाति के पुरुष से अवैध संबंध थे. जिन लोगों ने उसके साथ यह व्यवहार किया था, उन्हें ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर ने दोषी पाया और सज़ा सुनाई. सज़ा जिन धाराओं के अंतर्गत सुनाई गई, उनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम भी शामिल था. जब मामले की अपील हाईकोर्ट में हुई तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क़ानून के अंतर्गत दी गई सजा रद्द कर दी गई, यद्यपि अन्य धाराओं के अंतर्गत सुनाई गई सज़ा यथावत रखी गई. उसके बाद यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में आया. सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्तिद्वय मार्कंडेय काटजू और ज्ञानसुधा मिश्रा शामिल थे, ने न सिर्फ़ हाईकोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क़ानून के अंतर्गत दी गई सज़ा को रद्द किया जाना ग़लत बताया, वरन् इसके साथ ही भारत के मूल निवासी कौन थे, इस विषय पर अपना मत भी व्यक्त किया. निर्णय में कहा गया है कि आज के आदिवासी ही भारत के मूल निवासियों की संतान हैं. इस तथ्य के बावजूद उनके साथ सदियों से मानवोचित सुलूक नहीं किया जा रहा है. खंडपीठ ने इतिहास के अनछुए पहलुओं का सहारा लेते हुए यह दावा किया है कि वास्तव में हमारा देश अप्रवासियों का देश है. हमारे देश की 92 प्रतिशत आबादी अप्रवासियों की संतान है और मात्र आठ प्रतिशत भारतीय 10 हज़ार वर्षों से अधिक समय से भारतीय उप महाद्वीप में रह रहे हैं. पिछले हज़ारों सालों में विश्व के अनेक हिस्सों से लोग यहां आए और बस गए. इसी कारण हमारे देश में अनेक धर्मों के मानने वाले, अनेक भाषाएं बोलने वाले, अनेक प्रकार के खानपान और वेशभूषा वाले लोग रह रहे हैं. भाषाओं और अन्य प्रतीकों के आधार पर खंडपीठ ने माना कि बाहर से आए अप्रवासियों के आक्रमणों और अन्य कारणों से भारत के उक्त मूल निवासी जंगलों और पहाड़ों में सिमटने पर मजबूर हो गए. भारत के ये मूल निवासी अब मुख्यत: झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं. खंडपीठ ने अपने निर्णय में इस बात पर जोर दिया है कि भारत की नस्लीय, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भाषायी विभिन्नताओं ने हम पर एक गंभीर उत्तरदायित्व डाल दिया है. वह उत्तरदायित्व है विभिन्नताओं के बावजूद देश को एक बनाए रखने का. इस कठिन चुनौती का सामना करने में हमारे संविधान निर्माता काफी सहायक बन पड़े हैं. हमारा संविधान सभी धार्मिक समूहों, विभिन्न भाषा-भाषियों को समान अधिकार देता है और उनके अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है, परंतु सिद्धांत में सभी को बराबरी का दर्जा देना यथेष्ट नहीं है. उन समूहों को, जो पहले से ही अभावों का जीवन जी रहे हैं, विशेष संरक्षण और सहायता की जरूरत है. तभी वे ग़रीबी और असमान सामाजिक परिस्थितियों से ऊपर उठ सकेंगे. इसलिए संविधान में इस तरह के समूहों को विशेष अधिकार दिए गए हैं. इनमें आदिवासी शामिल हैं, जो भारत के मूल निवासियों की संतान हैं. वे सदियों से ग़रीबी और अभाव की ज़िंदगी जी रहे हैं. उनमें से अधिकांश आज भी निरक्षर हैं और कुपोषण एवं अज्ञानता के चलते बीमारियों की गिरफ्त में जल्दी आ जाते हैं. अन्य लोगों की तुलना में उनकी मृत्यु दर भी ज़्यादा है.

इसलिए वे सब, जो इस देश से मोहब्बत करते हैं और जो इसकी बेहतरी चाहते हैं, उनका कर्तव्य है कि वे आदिवासियों के उन्नयन में सहयोग करें. सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि आदिवासी आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से देश के अन्य नागरिकों के स्तर तक पहुंच सकें. हमें यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि वे सदियों से शोषण और अन्य प्रकार की ज़्यादतियों के शिकार रहे हैं. उनके प्रति हमारे रवैये में परिवर्तन आना चाहिए. हमें उनका पूरा आदर और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे पूर्वज हैं. हमने आदिवासियों के साथ जो अन्याय किया है, वह हमारे देश के इतिहास का सर्वाधिक शर्मनाक अध्याय है. एक समय था, जब इन आदिवासियों को हम राक्षस या असुर कहते थे. हमने इनकी हत्याएं कीं और जो बचे, उन पर हर संभव अत्याचार किए. हमने उनकी ज़मीनें छीनीं और उन्हें जंगलों में खदेड़ दिया, जहां वे अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन करते हैं. अब हम औद्योगीकरण के नाम पर उनसे जंगल भी छीन रहे हैं और उन्हें अभावों के गर्त में ढकेल रहे हैं.

निर्णय में आदिवासियों के साथ नारकीय व्यवहार के उदाहरण स्वरूप एकलव्य का उल्लेख किया गया है. द्रोणाचार्य द्वारा एकलव्य के साथ क्रूर व्यवहार किया गया. पहले तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से इंकार कर दिया, परंतु जब वह द्रोणाचार्य की मूर्ति के सहारे धनुर्विद्या में पारंगत हो गया तो द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा स्वरूप एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया. भोले भाले एकलव्य ने उन्हें अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया. इस तरह द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपंग बना दिया. द्रोणाचार्य ने अंगूठा इसलिए मांगा, क्योंकि उन्हें लगा कि एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया है. निर्णय कहता है कि उस समय से लेकर आज तक हम इन लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं.

खंडपीठ द्रोणाचार्य के व्यवहार को शर्मनाक बताते हुए कहती है कि जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा दी ही नहीं थी तो उन्हें उससे गुरु दक्षिणा मांगने का क्या अधिकार था. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इतनी ज़्यादतियां सहने के बावजूद आदिवासियों ने अपना उच्च नैतिक स्तर क़ायम रखा है. वे साधारणत: किसी को धोखा नहीं देते, झूठ नहीं बोलते और ऐसे अनैतिक कार्य नहीं करते, जो ग़ैर आदिवासियों में आम हैं. इसके बावजूद वे आज तक ज़्यादतियों के शिकार हैं. यह मामला, जिसमें हर संबंधित व्यक्ति ने आदिवासी विरोधी रवैया अपनाया, इसी तरह के व्यवहार का प्रतीक है. हमें यह रवैया बदलना होगा. यदि हम ऐसा करते हैं तो यह देशहित में होगा.

एल एस हरदेनिया
feedback@chauthiduniya.com

बदल गया है मुस्लिम समाज

17-23 जनवरी के अंक में छपा आलेख-मुस्लिम समाज बदल गया है, बहुत सटीक है. आजकल सभी धर्म विकास को तरजीह दे रहे हैं. पहले मुस्लिम समाज में लड़कियों को अधिक पढ़ने की छूट नहीं होती थी, लेकिन अब बच्चे ख़ूब पढ़ते हैं. आज इस धर्म के लोग रोज़गार और विकास चाहते हैं. इनसे बाकी धर्मावलंबियों को भी सबक लेना चाहिए.

-अमित कुमार, *फैजाबाद, उत्तर प्रदेश.*

निर्भीक पत्रकारिता

मैंने चौथी दुनिया अख़बार पहली बार लखनऊ में देखा. यह मुझे आकर्षक लगा, लिहाजा मैंने इसे खरीद लिया. अख़बार सही मायने में काबिले तारीफ़ है. रंगों का बहुत अच्छे ढंग से चुनाव किया गया है. सभी ख़बरों में ज्वलंत मुद्दे उठाए जाते हैं. आज के दौर में इस तरह की निर्भीक पत्रकारिता कम ही देखने को मिलती है. अब मैं इसका नियमित पाठक बन गया हूं.

-राजू, *लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

सटीक संपादकीय

17-23 जनवरी के अंक में प्रकाशित संपादकीय-सांप का मंत्र न जाने, बिच्छू के बिल में हाथ डाले काफी लेख है. सरकार पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है. महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम आदमी बाज़ार जाने से कतराने लगा है. सरकार अगर अब भी नहीं जागी तो आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा.

-सुमित जैन, *करनाल, हरियाणा.*

दंगों की मार

सांप्रदायिक दंगे और 2010 शीर्षक से प्रकाशित आलेख में एकदम सही कहा गया है कि स्वतंत्रता के बाद से हर वर्ष कोई न कोई दंगा हो जाता है, इन दंगों का असर सबसे अधिक आम लोगों पर पड़ता है. इन्हीं के घर-परिवार टूटते हैं और यही बेरोज़गार होते हैं. सरकार को चाहिए कि वह भविष्य में ऐसा होने से रोके.

-अरुण कुमार, *लुधियाना, पंजाब.*

आरटीआई संशोधन

आलेख-आरटीआई संशोधन: यह भ्रष्टाचार को बचाने की साज़िश है, शत प्रतिशत सही है. सरकार आरटीआई के वर्तमान स्वरूप में संशोधन के नाम पर इसे जटिल, महंगा और भोथरा बनाकर जनता के अधिकार छीनना चाहती है. आरटीआई जनता के बीच प्रभावी क़ानून साबित हुआ है. भ्रष्टाचार और घोटालों में लिप्त लोगों की जब पोल खुलने लगी तो वे इससे बचने के लिए क़ानून में संशोधन करने लगे.यदि सरकार सचमुच देश से भ्रष्टाचार का खात्मा करना चाहती है तो वह आरटीआई की धार को और तेज़ बनाए.

-गिरीश प्रसाद गुप्ता, *बेगूसराय, बिहार.*

धारदार लेखन

चौथी दुनिया के लेख और तेवर बहुत अच्छे लगते हैं. मुझे लगता है कि इस देश में जन सरोकारों की पत्रकारिता दिनोंदिन सिमट रही है. चौथी दुनिया जैसे अखबार ने इस बचाकर रखा है. बिहार में जो पत्रकारिता हो रही है, वह अपने आप सब बयान कर देती है.

-ज़ेबा अख्तर, *रांची, झारखंड.*

सुख और दु:ख

17-23 जनवरी के अंक में साईं बाबा का पेज बहुत अच्छा लगा. सही कहा गया है कि सुख-दु:ख दोनों इंसान के साथ रहते हैं, उसी के आसपास घूमते रहते हैं. दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक-दूसरे के बिना अधूरे हैं.

-रजत शर्मा, *दरभंगा, बिहार.*

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इसी पते पर भेजें. संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

आतंकवादी मानवता के दुश्मन हैं

हिंदू आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद, संघ परिवार का आतंकवाद यह तीनों ही शब्द स्वामी असीमानंद के अपराध स्वीकारने के बाद से लगातार सुनने में आ रहे हैं. एक अख़बार ने शीर्षक लगाया, असीमानंद के अपराध स्वीकारने से इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने वालों का मुंह काला. दूसरा अख़बार शीर्षक लगाता है, यह हिंदू दहशतगर्दी नहीं, संघ परिवार की दहशतगर्दी है. एक अख़बार लिखता है, स्वामी असीमानंद का इक़बालिया बयान और दहशतगर्दी का चेहरा बेनक़ाब. यानी जितने अख़बार, उतने शीर्षक. स्वामी असीमानंद की संलिप्तता विभिन्न बम धमाकों में साबित होने के बाद महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम सोचें कि यह हिंदू आतंकवाद है या मुस्लिम, बल्कि यह सोचना है कि आतंकवादी न हिंदू हैं, न मुस्लिम. वे मानवता के दुश्मन हैं, जिनकी कारगुज़ारियों से न केवल देश और समाज को क्षति होती है, बल्कि घर के घर तबाह हो जाते हैं, मासूम बच्चे अनाथ हो जाते हैं और महिलाएं विधवा हो जाती हैं. महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि कौन पकड़ा गया, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पकड़ा गया, वह मासूम और बेगुनाह तो नहीं है. इसलिए आज जरूरत है कि उन मुस्लिम नौजवानों, जिन्हें मक्का मस्जिद, मालेगांव, समझौता एक्सप्रेस और अजमेर शरीफ़ दरगाह में धमाकों के बाद पकड़ कर बंद कर दिया गया, का भविष्य बचाया जाए और तारीख़ पर तारीख़ वाली परंपरा को ख़त्म करके तत्काल उनकी रिहाई का इंतजाम हो. मुंबई में जिस तरह लगभग 50 मुस्लिम संगठनों ने रैली निकाली और वहां के ऐतिहासिक आज़ाद मैदान में हज़ारों की संख्या में मुसलमानों ने एकत्र होकर प्रदर्शन किया, वह एक अच्छी कोशिश है.

जमीअत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी और अबू आसिम आज़मी आदि ने भी इन मुस्लिम नौजवानों को रिहा करने की मांग की है. यहां अहम बात यह भी है कि असीमानंद के इक़बालिया बयान और अपराध स्वीकारने के बाद इन नौजवानों की रिहाई का इंतज़ाम क्यों नहीं किया जा रहा? इस मामले में सरकार को आरोपियों को रिहा किए जाने के लिए अदालत में याचिका डालनी चाहिए. मुस्लिम संगठनों और रहनुमाओं को चाहिए कि वे भड़काऊ बयान देने से बचें और मुस्लिम नौजवानों को हौसला दें, क्योंकि लंबे समय से उनमें अनिश्चितता की भावना पैदा हो गई है. वह दाढ़ी रखने से परहेज़ करने लगे हैं. घर से अगर कोई नौजवान पठानी सूट या इस्लामी शरीयत का कुर्ता-पायजामा पहन कर निकलने लगता है तो माता-पिता उसे फ़ौरन कपड़े बदलने पर मजबूर कर देते हैं.

इसकी वजह यही है कि पुलिस और सुरक्षागार्डों का स्वभाव सा बन गया है कि वे मुस्लिम नौजवानों को देखते ही रोक लेते हैं और फिर तलाशी के नाम पर उन्हें अपमानित करते हैं. अल्पसंख्यकों को चारों तरफ़ से अपमानित किया जाता है और उन पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उन्हें जेलों में डाल दिया जाता है. यह शायद 20 फ़रवरी, 1998 की बात है, एक मुस्लिम नौजवान मोहम्मद आमिर ख़ान अपने घर से इशा की नमाज़ पढ़कर निकल रहा था, उसे पुरानी दिल्ली के इलाक़े से पुलिस ने उठा लिया और उस पर 1996-97 के कई धमाकों का आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया. 1998 से 2006 तक वह तिहाड़ जेल में रहा और जब 2006 में उसे बेगुनाह क़रार देकर छोड़ दिया जाना था, तब उससे कहा गया कि उसे फ्रंटियर मेल धमाके में उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपी क़रार दिया है, जो 10 जनवरी, 1991 को हुआ था. यह सब सुनकर और पढ़कर बिल्कुल ऐसा लगा रहा है, जैसे पुलिस इंतजार कर रही हो कि कब कोई ऐसा लड़का मिले, जिसका कोई न हो और जो अपने बचाव का इंतज़ाम न कर सके तथा उसे किसी न किसी तरह फंसा लिया जाए. पाठकों को याद होगा कि 19 जून, 2001 को ग़ाज़ियाबाद की डासना जेल में शकील नामक एक नौजवान की लाश मिली थी, जिसे 1996 में फ्रंटियर मेल धमाके का मुजरिम क़रार देकर जेल में डाल दिया गया था. उसकी लाश उसके सेल में पंखे से लटकी हुई पाई गई, जबकि उसे ज़हर देकर मारा गया था. इसी तरह हैदराबाद का 22 वर्षीय मुस्लिम नौजवान मोहतशिम बिलाल जो इंजीनियर था, को 5 मार्च, 2008 को गिरफ्तार किया गया था.

मुस्लिम संगठनों और रहनुमाओं को चाहिए कि वे भड़काऊ बयान देने से बचें और मुस्लिम नौजवानों को हौसला दें, क्योंकि लंबे समय से उनमें अनिश्चितता की भावना पैदा हो गई है. वह दाढ़ी रखने से परहेज़ करने लगे हैं. घर से अगर कोई नौजवान पठानी सूट या इस्लामी शरीयत का कुर्ता-पायजामा पहन कर निकलने लगता है तो माता-पिता उसे फ़ौरन कपड़े बदलने पर मजबूर कर देते हैं. पुलिस और सुरक्षागार्डों का स्वभाव सा बन गया है कि वे मुस्लिम नौजवानों को देखते ही रोक लेते हैं और फिर तलाशी के नाम पर उन्हें अपमानित करते हैं. अल्पसंख्यकों को चारों तरफ़ से अपमानित किया जाता है और उन पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उन्हें जेलों में डाल दिया जाता है.

ये तो चंद नाम हैं, मगर इसी तरह न जाने कितने नौजवान हैं, जिन्हें हैदराबाद, आज़मगढ़, दिल्ली और दूसरे शहरों से बिना वजह पकड़ कर जेलों में बंद कर दिया गया. क्या इन नौजवानों के घर, परिवार और उनसे जुड़े लोगों की मानसिक स्थिति का अंदाज़ा कोई लगा सकता है कि जिनके बच्चे को आतंकवादी कहकर जेल में डाल दिया जाए और कोई सुनवाई न हो. इसी तरह सुनील जोशी की हत्या के बाद देवासी में रशीद शाह की 2007 में घर में घुसकर हत्या कर दी गई. जब उनका बेटा जलील उन्हें बचाने आया तो उसे भी जिंदा जला दिया गया, दूसरे भाई के पैर में गोली मार दी. जब दंगाई एक मासूम बच्ची को जलाकर मारने की कोशिश कर रहे थे तो उसके पिता ने बड़ी मुश्किल से उसे बचा तो लिया, मगर ख़ुद मानसिक संतुलन खो बैठा. लतीफ़ शाह, जो इस परिवार में बचने वाला बदनसीब व्यक्ति है, का कहना है कि न तो हम सुनील जोशी को जानते थे और न उससे हमारा कोई संबंध था, मगर दंगाइयों ने निर्ममता से मेरे पूरे घर को ख़त्म कर दिया और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई और अभी भी हमें डरा- धमका कर रखा जाता है. लतीफ़ शाह का कहना है कि कोई वक़ील हमारी पैरवी करने के लिए तैयार नहीं था. अब हमारी लड़ाई लड़ने के लिए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ मल्कार आगे आए हैं. ये सब तो वे मशहूर मामले हैं, जो सामने आ गए, मगर जिन ग़रीब लड़कों को सड़क से पकड़ लिया गया, जिनके माता-पिता ग़रीब हैं और समाज के भय से कोई क़दम नहीं उठाते, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है.

अब्दुल कलीम नामक 21 वर्षीय नौजवान, जो असीमानंद के अपराध स्वीकारने से काफ़ी मशहूर हुआ है, उसे भी पहले कोई नहीं जानता था. यह ग़रीब नौजवान 2007 में मक्का मस्जिद धमाके में पकड़ा गया था, मगर जैसा उसका कहना है कि उसके अच्छे चरित्र ने असीमानंद को अपराध स्वीकारने पर विवश कर दिया, बहुत आश्चर्यजनक लगता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इतने बड़े-बड़े धमाके किए हों और कुख्यात गिरोह का हिस्सा हो, वह एक नौजवान की बातों में आकर अपराध स्वीकार कर ले, यह बात कुछ पचती नहीं है और अतार्किक लगती है. कई बार ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र या कोई सोची-समझी योजना तो नहीं है. जो भी है, यह बात समझ लेनी चाहिए कि जिन मुस्लिम नौजवानों को सिर्फ़ शक़ की बुनियाद पर अपराधी बनाकर जेलों में बंद कर दिया गया है, हम सबको मिलकर उनकी रिहाई की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उनका भविष्य ख़राब होने से बच जाए.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

मुस्लिम पर्सनल लॉ को संहिताबद्ध करने का मुद्दा-2

असगर अली इंजीनियर

बहुपत्नी प्रथा का मुद्दा बहुत विवादास्पद है. इस मामले में आम सहमति यह बनी कि न तो इस प्रथा का पूरी तरह से उन्मूलन किया जाना चाहिए और न ही इसे इतना आसान बनाया जाना चाहिए कि कोई पुरुष अपनी मनमर्जी से दूसरा या तीसरा विवाह कर ले. यह पर्सनल लॉ को संहिताबद्ध करने की प्रक्रिया का सबसे दुरुह हिस्सा है. हर शहर में जाने-माने एवं सम्मानित मुसलमानों की विवाह समिति गठित होनी चाहिए. अगर कोई व्यक्ति दूसरी पत्नी लाना चाहता है तो उसे अपनी पहली पत्नी और विवाह समिति को ज़रूरी दस्तावेजों के साथ नोटिस देना होगा, जिसमें उन कारणों का स्पष्ट उल्लेख होगा, जिनके चलते वह दूसरी स्त्री से भी विवाह करना चाहता है.

यह साबित करने की ज़िम्मेदारी संबंधित पुरुष की होगी कि उसके पास दोनों पत्नियों की देखभाल करने के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन हैं और वह क़ुरान के प्रावधानों के अनुरूप दोनों के साथ न्याय कर सकेगा. इस मामले में कुछ आवश्यक शर्तें भी लगाई जानी चाहिए. एक यह कि मेडिकल जांच से साबित हो गया हो कि पहली पत्नी संतान को जन्म देने में अक्षम है. दूसरी यह कि पहली पत्नी की सहमति आवश्यक रूप से ली जानी चाहिए. विवाह समिति से विचार विमर्श करके क़ाज़ी पहली पत्नी को अपनी बात रखने का मौक़ा देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उसने किसी दबाव के चलते या डराने-धमकाने के कारण सहमति न दी हो.

दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने के कारण कोई पत्नी अपने पति की शारीरिक ज़रूरतें पूरी करने में असमर्थ हो. यह भी मेडिकल जांच से साबित किया जाना चाहिए और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए. इसके बाद विवाह समिति एवं क़ाज़ी पहली पत्नी से चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लेंगे. क़ुरान (देखिए 4:3 व 4:129) स्पष्ट कहती है कि दूसरा विवाह न्यायपूर्ण होना चाहिए और यह भी कि दूसरी पत्नी लाना पुरुष का विशेषाधिकार नहीं है.

पवित्र पैग़ंबर ने भी अपनी पत्नी जमीला का ख़ुलूअ स्वीकार किया था, क्योंकि वह उनके साथ रहना नहीं चाहती थीं. हालांकि पैग़ंबर साहब जमीला से बहुत स्नेह करते थे और उन्हें पूरा सम्मान देते थे. उन्होंने जमीला से केवल इतना कहा कि वह उस बाग को उन्हें लौटा दें, जो उन्होंने जमीला को मेहर के तौर पर दिया था. इस हदीस से स्पष्ट है कि पत्नियों का ख़ुलूअ का अधिकार संपूर्ण है और इसमें कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती. ख़ुलूअ के लिए पति की सहमति की आवश्यकता नहीं है. इसके लिए पति की सहमति को आवश्यक बताना पवित्र पैग़ंबर की आज्ञा का उल्लंघन करना होगा.

तलाक़

भारत में तलाक़ संबंधी क़ानूनों का घोर दुरुपयोग होता है. पुरुष क्षणिक गुस्से में या नशे में तीन बार तलाक शब्द का उच्चारण कर तलाक़ दे देते हैं. इससे सालों पुराने वैवाहिक संबंध एक क्षण में ख़त्म हो जाते हैं और परिवार बिखर जाते हैं. इस बात पर आम सहमति है कि यह बिदाह: (पाप) है. पैगंबर साहब ने तलाक के इस तरीक़े को बिल्कुल ग़लत क़रार दिया था. यह तरीक़ा इस्लाम के आगमन के पहले प्रचलित था.

वैसे भी सभी मुसलमान तलाक़ के इस तरीक़े को मान्यता नहीं देते. अहल-ए-हदीस एवं शिया पंथ के मुसलमान ऐसे तलाक़ को अवैध मानते हैं. क़ुरान भी एकतरफ़ा तलाक़ की पक्षधर नहीं है. क़ुरान में मध्यस्थता की बात भी कही गई है (देखिए 4:35). मध्यस्थों में से एक पति की ओर से होगा और दूसरा पत्नी की ओर से. यदि कोई पति अपनी पत्नी को तलाक़ देना चाहेगा तो वह उसे इस आशय का नोटिस देगा और विवाह समिति को भी सूचित करेगा. इसके बाद विवाह समिति उनमें मेलमिलाप कराने की कोशिश करेगी.

अगर मेलमिलाप कराने का प्रयत्न असफल हो जाता है तो विवाह समिति पति से एक बार तलाक़ शब्द का उच्चारण करके उसे तीन महीने की इद्दत की अवधि तक इंतज़ार करने को कहेगी. इस बीच वह चाहे या उसे पछतावा हो तो वह अपनी पत्नी को वापस घर ला सकेगा. इद्दत की अवधि समाप्त होने के बाद तलाक पूर्ण हो जाएगा और इसके दो गवाह होंगे (65:2). क़ाज़ी तलाक़ों का भी रिकॉर्ड रखेंगे और इस रिकॉर्ड में दोनों गवाहों के हस्ताक्षर भी होंगे. यह पुरुषों द्वारा तलाक देने का सबसे न्यायोचित तरीक़ा होगा और इससे पुरुषों की मनमानी पर अंकुश लग सकेगा.

क़ुरान में महिलाओं को भी अपने पति से ख़ुलूअ लेने का अधिकार दिया गया है (देखिए 2:229). हदीस के अनुसार, पवित्र पैग़ंबर ने भी अपनी पत्नी जमीला का ख़ुलूअ स्वीकार किया था, क्योंकि वह उनके साथ रहना नहीं चाहती थीं. हालांकि पैग़ंबर साहब जमीला से बहुत स्नेह करते थे और उन्हें पूरा सम्मान देते थे. उन्होंने जमीला से केवल इतना कहा कि वह उस बाग को उन्हें लौटा दें, जो उन्होंने जमीला को मेहर के तौर पर दिया था. इस हदीस से स्पष्ट है कि पत्नियों का ख़ुलूअ का अधिकार संपूर्ण है और इसमें कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती. ख़ुलूअ के लिए पति की सहमति की आवश्यकता नहीं है. इसके लिए पति की सहमति को आवश्यक बताना पवित्र पैग़ंबर की आज्ञा का उल्लंघन करना होगा.

विवाह, तलाक़ एवं बहुपत्नी प्रथा के अतिरिक्त हमने उत्तराधिकार और अन्य विषयों पर भी विचार किया है, परंतु स्थान की कमी के कारण इसका विवरण मैं भविष्य में अपने किसी लेख में दूंगा. यहां इतना कहना पर्याप्त होगा कि अगर इन प्रावधानों को लागू किया जाता है तो पर्सनल लॉ का दुरुपयोग पूरी तरह से रुक जाएगा और महिलाओं के साथ होने वाला अन्याय बंद हो जाएगा.

(लेखक मुंबई स्थित सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी एंड सेक्युलरिज्म के संयोजक हैं)

feedback@chauthiduniya.com

राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की शुरुआत उन बच्चों को पहचान दिलाने के उद्देश्य से की गई थी, जो उत्कृष्ट वीरता का परिचय देकर दूसरों का जीवन बचाते हैं.

आपके पत्र आपके अनुभव

इस अंक में हम अपने पाठकों के पत्र शामिल कर रहे हैं. इन पत्रों के माध्यम से हमारे पाठकों ने कुछ सुझाव मांगे है तो अपने अनुभव को भी हमसे साझा किया है. इसके अलावा, इस अंक में हमने एक आवेदन भी प्रकाशित किया है. सूचना क़ानून के तहत बना यह आवेदन आपके गांव–शहर में चल रहे विद्युतीकरण कार्य के बारे में जानकारी मांगने से संबंधित है.

पाठकों के पत्र

एडमिशन मिला, न पैसा

मैं शुरुआत से ही चौथी दुनिया साप्ताहिक को पढ़ता आ रहा हूं. आपके अख़बार के द्वारा मुझे आरटीआई की भी जानकारी हुई, साथ ही आपकी तरफ़ से संभव प्रतिनिधित्व ने साहस बढ़ाया कि मैं भी अपना जायज़ रुपया 2550 रुपया वापस पा सकूं, जिसे मैंने डिमांड ड्राफ़्ट के रूप में रजिस्ट्री के द्वारा मौलाना आज़ाद नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में एम.ए. उर्दू प्रथम के प्रवेश के लिए भेजा था. मगर न जाने क्यों, मेरा प्रवेश वहां नहीं हुआ और ड्राफ़्ट भी वापस नहीं आया.

मो. अय्यूब अंसारी, *जमुई.*

आप एक आरटीआई आवेदन देकर (ड्राफ्ट की प्रति संलग्न) इससे संबंधित सूचनाएं मांग सकते हैं.

ग़लत सूचना मिली.

मैंने जून 2010 को सूचना के अधिकार क़ानून के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल व डीडीए के चेयरमैन से 17 व 18 मई 2010 को जैतपुर में होने वाली तोड़फोड़ की कार्रवाई पर जानकारी मांगी थी. जवाब में एडीएम ने दक्षिणी दिल्ली के सरिता विहार में होने वाली इस तोड़फोड़ की घटना को सिरे से ही मना कर दिया है. जबकि यह ग़लत सूचना है.

अशरफुल हुदा, *अलफ़लाह ट्रस्ट, दिल्ली*

आप इसकी शिक़ायत सीधे केंद्रीय सूचना आयोग में कर सकते हैं.

हज ऑफिसर से जुड़ी सूचना नहीं मिली

मैने अधीक्षक डाकघर, मुरादाबाद मंडल से सूचना पट पर हज ऑफिसर व सहायक हज ऑफिसर की मांग संबंधित सरकुलर के संबंध में सूचना मांगी थी. सूचना नहीं दी गई. कहा गया कि जिस संगठन के लेटरपैड पर सूचना मांगी है, वह पंजीकृत है या नहीं इसकी जानकारी दें तब सूचना दी जाएगी.

ख़ुर्शीदुल हसन, *पोस्टल समाज, मुरादाबाद*

सूचना आपने व्यक्तिगत हस्ताक्षर के ज़रिए मांगी थी. फिर भी सूचना न देने के लिए ग़लत बहाना बनाया गया. आप इसकी शिक़ायत राज्य सूचना आयोग में कर सकते हैं.

मिल गया पीएफ

अशोक सिंघल का स्थानांतरण खंडवा से तमिलनाडु (चेन्नई) होने पर वह नौकरी से इस्तीफ़ा देकर बिहार घर वापस आ गए. पीएफ में जमा राशि लगभग 16,752 रुपये का चैक संगठन द्वारा ग़लत खाता नंबर पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा बरौनी (बिहार) को वर्ष 2002 में ही भेजा गया था, लेकिन बैंक ने खाता नंबर सुधारकर भेजने के लिए उसे संगठन के पास पुन: भेज दिया था. फिर वह मुझे अप्रैल 2010 में सूचना आवेदन निबंधित डाक द्वारा भेजा गया. प्रथम अपील के बाद उक्त संगठन द्वारा अशोक सिंघल की कुल बक़ाया राशि ब्याज सहित उपलब्ध करा दी गई.

गिरीश प्रसाद गुप्ता, *बरौनी (आरटीआई कार्यकर्ता)*

मेरे ससुर को आर्थिक लाभ नहीं मिला

आपका चौथी दुनिया साप्ताहिक पेपर पढ़कर मुझे सूचना अधिकार के विषय में जानकारी लेनी है. मेरे ससुर श्रीमान बीएल कौशल भिकन गांव की कृषि मंडी में सचिव पद पर 1954 से कार्यरत थे. उनकी कार्यप्रणाली देखकर उन्हें पदोन्नति मिली. 1994 में जब वह सेवानिवृत्त हुए थे, तब उनका पद प्रथम श्रेणी का था. उन्हें अपने कार्य की वजह से राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था. लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति तृतीय श्रेणी में क्यों की गई, इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए. इस विषय में मैंने सूचना अधिकार के माध्यम से भोपाल/कृषि मंडी समिति को प्रथम अपील भेजी है. यह प्रथम अपील मैंने 3 जनवरी 2011 को भेजी है.

शालीग्राम जवाहर लाल जी गुप्ता *अमरावती,महाराष्ट्र*

आप अपील के निर्णय का इंतज़ार करें. यदि अपील के बाद भी वांछित सूचना नहीं मिलती है, तब आप इस मामले में द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में कर सकते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन –201301
ई–मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

(विद्युतीकरण का विवरण)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,

ग्राम ..... में विद्युत व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

1. उपरोक्त गांव के कितने घरों में बिजली का कनेक्शन है? प्रत्येक कनेक्शनधारी का नाम एवं पता बताएं.
2. उपरोक्त गांव जिस ब्लॉक में आता है, उस ब्लॉक में पिछले 10 वर्षों के दौरान गांवों के विद्युतीकरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? वर्षवार विवरण प्रदान करें.
3. क्या उपरोक्त ब्लॉक में विद्युतीकरण एवं उसके रख-रखाव का कार्य किसी ठेकेदार/एजेंसी के माध्यम से कराया जा रहा है? यदि हां तो उससे संबंधित निम्न सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

क. कार्य का नाम
ख. कार्य का संक्षिप्त विवरण
ग. कार्य के लिए स्वीकृत राशि
घ. कार्य स्वीकृत होने की तिथि
ड. कार्य समाप्त होने की तिथि अथवा चालू कार्य की स्थिति
च. कार्य कराने वाली एजेंसी का नाम
छ. कार्य शुरू होने की तिथि
ज. कार्य समाप्त होने की तिथि
झ. कार्य के लिए ठेका किस दर पर दिया गया?
ण. कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है
ट. कार्य के रेखाचित्र की प्रमाणित प्रति
ठ. इस कार्य को कराने का निर्णय कब और किस आधार पर लिया गया? इससे संबंधित निर्णयों की प्रति भी उपलब्ध कराएं.
ड. उन सहायक तथा कार्यपालक अभियंताओं के नाम बताएं, जिन्होंने इन प्रत्येक कार्यों का निरीक्षण किया और भुगतान की स्वीकृति दी. इनके द्वारा कार्य के किस भाग का निरीक्षण किया गया?

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम:
पता:
फोन नं:

संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

नन्हें जज़्बों को सलाम

कहते हैं कि साहस की कोई उम्र नहीं होती, सिर्फ़ जिगर हो तो हिम्मतें आ ही जाती हैं. ऐसे ही कुछ जांबाज बच्चों को, जिन्होंने उम्र की सीमा पार करते हुए अपनी जान की बाज़ी लगा कर दूसरों की ज़िंदगी बचाई है, उन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया. इन वीर बच्चों को यह पुरस्कार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा प्रदान किया गया. राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों इन वीर बच्चों के सम्मान में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया. इसके अलावा कई अन्य राज्यों ने भी इनके सम्मान में राज्य स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है. राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चुने गए 23 वीर बच्चों में दो ऐसे बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्र मात्र छह वर्ष है, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी. उन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया. इसके पुरस्कार के लिए चयनित बच्चों में नौ लड़कियां और 14 लड़के हैं. इन सभी बच्चों ने राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में भी भाग लिया. हाल ही में भारतीय बाल कल्याण परिषद की अध्यक्ष गीता सिद्धार्थ ने एक प्रेस कांफ्रेंस में इन वीर बच्चों को यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की थी.

प्रतिष्ठित गीता चोपड़ा पुरस्कार के लिए केरल की 13 वर्षीय जिस्मी पी एम को चुना गया था, जिसने दो बच्चों को डूबने से बचाया था. वहीं संजय चोपड़ा पुरस्कार उत्तराखंड के 11 वर्षीय प्रियांशु जोशी को प्रदान किया गया, जिसने अपनी जान की बाज़ी लगाकर अपनी बहन को तेंदुए से बचाया था. इसके अलावा केरल

वीरता पुरस्कार के लिए इन बच्चों का चयन एक उच्च स्तरीय समिति ने किया है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, ग़ैर सरकारी संगठनों के साथ ही भारतीय बाल कल्याण परिषद के वरिष्ठ सदस्य शामिल थे. वैसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की शुरुआत भारतीय बाल कल्याण परिषद ने उन बच्चों को पहचान दिलाने केउद्देश्य से की थी, जो उत्कृष्ट वीरता का परिचय देकर दूसरों का जीवन बचाते हैं. सबसे पहले वर्ष 1957 में पहली बार दो बच्चों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया.

फोटो–*प्रभात पांडेय*

निवासी 16 वर्षीय विष्णुदास के., मध्य प्रदेश के मूनीस खान 15 और अरुणाचल प्रदेश की 16 वर्षीय कुमारी इपी बासर को बापू गैधानी पुरस्कार प्रदान किया गया है. जहां विष्णुदास ने दो बच्चों को डूबने से बचाया, वहीं मूनीस ने एक वृद्ध व्यक्ति को रेलवे दुर्घटना से बचाया जबकि इपी ने दो लोगों को आग से बचाया. लेकिन फलोदी तहसील के गांव आमला निवासी चम्पा कंवर दूसरों की तरह भाग्यशाली नहीं रही. जब अपने माता–पिता की ग़ैर मौजूदगी में चम्पा के घर पर आग लगी तो वह अपनी सात माह की बहन को आग से बचाने के लिए जलते हुए घर में कूद पड़ी. लेकिन उसका यह प्रयास सफल नहीं हुआ. अपनी बहन के साथ ख़ुद चम्पा भी इस अग्निकांड की भेंट चढ़ गई.

राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले अन्य बच्चों में असम की रेखामणि सोनोवाल 11, कल्पना सोनोवाल 12, छत्तीसगढ़ के राहुल कुर्रे 10 कुमारी पार्वती अमलेश 12, केरल के अनूप एम 12, महाराष्ट्र के रोहित मारुतिमुलिक 13, मणिपुर के मोहम्मद नारुल हुडा, मेघालय के फ्रीडी नांगगसिएज 09, लवलीस्टार के सोहफोह 10, मिजोरम की कुमारी लालमामेइजुआली 09, पंजाब के गुरुजीवन सिंह 11, राजस्थान की दिवंगत कुमारी चम्पा कंवर 06 और श्रवण कुमार 06, सिक्किम के विवेक शर्मा 11, उत्तर प्रदेश के उत्तम कुमार 14 उत्तराखंड की दिवंगत श्रुति लोधी 13 और पश्चिम बंगाल की सुनीता मुरमू 16 शामिल है.

ग़ौरतलब है कि वीरता पुरस्कार के लिए इन बच्चों का चयन एक उच्च स्तरीय समिति करती है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, ग़ैर सरकारी संगठनों के साथ ही भारतीय बाल कल्याण परिषद के वरिष्ठ सदस्य शामिल थे. वैसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की शुरुआत भारतीय बाल कल्याण परिषद ने उन बच्चों को पहचान दिलाने के उद्देश्य से की गई थी, जो उत्कृष्ट वीरता का परिचय देकर दूसरों का जीवन बचाते हैं. सबसे पहले वर्ष 1957 में पहली बार दो बच्चों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया. इसके बाद से प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिए जाने लगे. गीता ने कहा कि अभी तक ऐसे 800 बच्चों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं. जिसमें 568 बालक और 232 बालिकाएं शामिल हैं. हम तो यही कहेंगे कि इन बच्चों की बहादुरी पूरे देश के लिए सबक है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

मेष
21 मार्च से 20 अप्रैल

सप्ताह के आरंभ में पारिवारिक स्थिति में बदलाव आएगा. महत्वाकांक्षा बढ़ेगी परिवार की अशांति व विवादों से शीघ्र मुक्ति पा सकेंगे. लाभकारी समय है युक्ति और व्यवहार से बस कुछ पा सकते हैं. कोई शुभ समाचार आपके उत्साह को बढ़ाएगा.

वृष
21 अप्रैल से 20 मई

सप्ताह के शुरुआत में सुख और आराम एवं मनोरंजन के अवसर प्रबल होंगे. दूसरों से विवादों में उलझनें की भूल करने से विरोधी बढ़ेंगे. कुछ आर्थिक ओर पारिवारिक संकोच अभी दबाव में रखेंगे. परिवर्तन की आशंका भी रहेगी.

मिथुन
21 मई से 20 जून

इस सप्ताह शारीरिक कष्ट के कारण मन दुखी रहेगा. नए परिवारों और सामाजिक संबंधियों के प्रति मर्यादित रहेंगे. पारिवारिक विषमताएं सिर उठा सकती हैं. मान–सम्मान भी बढ़ेगा और अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति भी होगी. आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतें.

कर्क
21 जून से 20 जुलाई

इस सप्ताह के आरंभ में कुछ अस्थाई उद्यम तथा अर्थपूर्ण प्रयास से लाभ मार्ग प्रशस्त करेंगे. दौड़ भाग और परिश्रम के बाद वांछित लाभ होगा. कार्यक्षेत्र की प्रक्रियाओं में व्यस्तता रहेगी. दूर की यात्रा भी करनी पड़ सकती है. मानसिक परेशानी के चलते मन कुंठाग्रस्त रहेगा.

सिंह
21 जुलाई से 20 अगस्त

इस सप्ताह के आरंभ में सभी काम सरलता से बनते नज़र आएंगे. व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी परिवार में अशांति संभव है. सहज ही सभी काम समय पर बनते नज़र आएंगे. कार्य साधक गतिविधियां होंगी और वित्तीय लाभ भी यथेष्ट रूप में होगा.

कन्या
21 अगस्त से 20 सितंबर

सप्ताह के आरंभ में अचानक कार्यों में अवरोध आने से असंतोष बना रहेगा. कार्य की गति किसी रूकावट से धीमी होगी. उत्सव व त्यौहार में सम्मिलित होने के अवसर प्राप्त होंगे. अच्छे भोजन से स्वास्थ्य में वृद्धि होगी.

तुला
21 सितंबर से 20 अक्टूबर

इस सप्ताह निकट दूर की यात्राएं भी होंगी और मित्रों का समागम भी. किसी विषैली वस्तु अथवा भारी भोजन के कारण परेशानी होगी. कार्य क्षेत्र में आपकी धाक जमेगी व एक के बाद एक मामले सुलझते चले जाएंगे.

वृश्चिक
21 अक्टूबर से 20 नवंबर

सप्ताह के आरंभ से ही जटिल समस्याओं का धीरे धीरे निदान होने लगेगा. आर्थिक संकोच भी नष्ट होंगे. परिवार के सदस्यों की सेवा आवश्यक होगी. दांपत्य सुख में वृद्धि होगी. जटिल कार्यों का निष्पादन होगा और लाभदायक उपक्रमों का संचालन भी होगा.

धनु
21 नवंबर से 20 दिसंबर

इस सप्ताह ज्ञान की वृद्धि होगी. लाभदायक कार्यो में असुविधा अनुभव करेंगे. मन नहीं लगेगा. वाहन और आवास संबंधी समस्याएं सिर उठा सकती हैं. शुभ संदेश आने से उत्साह बढ़ेगा और मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा.

मकर
21 दिसंबर से 20 जनवरी

सप्ताह के आरंभ में लाभदायक कार्यो में असुविधा अनुभव करेंगे परंपरागत रोग के प्रति सावधानी रखें. परिश्रम करने से शरीर में चुस्ती बनी रहेगी. पराक्रम भाव और पुरुषार्थ की योजनाएं बनेंगी और मित्रों का सहयोग बना रहेगा.

कुंभ
21 जनवरी से 20 फरवरी

सप्ताह के आरंभ में स्वभाव की अपरिपक्वता अथवा चित्त की चंचलता के कारण कुछ अनावश्यक विवाद पैदा हो सकते हैं. किसी पर व्यर्थ के संदेह और तर्क–वितर्क में समय और धन की हानि होगी.

मीन
21 फरवरी से 20 मार्च

इस सप्ताह कामकाज की स्थिति लाभदायक सिद्ध होगी. नौकरी में स्थिति अनुकूल बनेगी. आपको पक्ष और विपक्ष के लोगों का सहयोग मिल सकता है. किसी महत्वाकांक्षा की शुरुआत होगी. अकारण पड़ने वाले व्यवधान से लाभ प्रभावित होगा.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

ट्यूनीशिया के हालात पर त्वरित टिप्पणी करते हुए जाने-माने कूटनीतिज्ञ एवं विदेशी मामलों के जानकार मृदुल त्यागी कहते हैं कि वहां जनाक्रोश की जीत हुई है.

यह कहीं नई ग़ुलामी तो नहीं

सिद्धार्थ राय

पिछले अंक में हमने अमेरिका और फ्रांस के साथ भारत की विदेश नीति पर चर्चा की थी. 2010 का आख़िरी महीना भारतीय विदेश नीति के वर्तमान और भविष्य के लिहाज़ से महत्वपूर्ण रहा. सबसे आख़िर में आए बेन जिआबाओ, चीनी प्रधानमंत्री. चीन तो बहुत पहले से भारत को परेशान और असंतुलित करने में लगा हुआ है. चीन हमेशा से भारत को दुश्मन की नज़र से देखता रहा है, क्योंकि वह जानता है कि भारत का बाज़ार ही दुनिया में इतना बड़ा है, जो उसे टक्कर दे सकता है. इसीलिए भारत-चीन संबंध हमेशा तनाव भरे रहे हैं. अच्छे संबंधों का अर्थ रहा है कम तनाव. तिब्बत, अरुणाचल और कश्मीर को लेकर दोनों में मनमुटाव चलता आ रहा है. ये सभी सीमा विवाद के अलग-अलग रूप हैं. चीन ने हाल में कश्मीर से जाने वाले यात्रियों को नत्थी वीजा देने की प्रथा शुरू की. जब जिआबाओ भारत आए तो यह बात उनके सामने रखी गई, लेकिन उन्होंने छोटा मामला बताते हुए इसे प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर होने वाली बातचीत पर छोड़ देने का काम किया. अभी उन्हें वापस गए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन सीमा पर मनरेगा के तहत काम करने वाले मज़दूरों को चीनी सेना ने आकर भगा दिया. ऊपर से जल्द ही आई रपट के अनुसार, चीन ने अरुणाचल से भी जाने वाले यात्रियों को नत्थी वीजा देना शुरू कर दिया है. यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि चीन से हमारे संबंध हमेशा तलवार की धार पर रहे हैं. शुरू से ही भारत चीन पर भरोसा नहीं कर पाया है, क्योंकि चीन हमेशा ही यह करता है कि एक ओर वह दोस्ती की बात करेगा और दूसरी ओर पीठ में छुरा घोंप देगा. पाकिस्तान के संबंध में भारत-चीन की प्रासंगिकता बढ़ जाती है. यहां से पाकिस्तान गए जिआबाओ ने पाकिस्तान को बहुत सारे पैसों, बहुत सारे प्रोजेक्ट और अपनी लंबी दूरी की दोस्ती का वादा भी किया. याद रखने वाली बात यह है कि भारत में संयुक्त ऐलान करने वाले जिआबाओ ने पाकिस्तान का नाम भी आतंकवाद के संदर्भ में लेने से इंकार कर दिया. तो जिआबाओ की यात्रा से भारत को मिला क्या? सरकार ने जनता को बताया कि चीन का आज तक का सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी बेन के साथ आया था. बहुत बिजनेस मिला. जबकि सच्चाई यह है कि चीन के साथ व्यापारिक संबंधों में भारत की मिट्टी पलीद हो गई. हमारा सबसे बड़ा नेगेटिव बैलेंस आफ पेमेंट चीन के साथ है. मतलब यह कि हम चीन को भेजते कम हैं और वहां से मंगाते ज़्यादा हैं. भारत का बहुत बड़ा बीपीओ बिजनेस चीन ने छीन लिया है. चीन भारत को महा घटिया सामान देता है, जिसका प्रमाण है भारत द्वारा बहुत सारे मामले डब्लूटीओ में ले जाना. हमारी सरकार ने इन बातों पर न तो कोई क़दम उठाए और न जिआबाओ के सामने ये सारी बातें रखीं. भारत-चीन संयुक्त ऐलान में ये सारी बातें नहीं हैं. कोई भी देख और पढ़ सकता है. लेकिन कांग्रेस इसी में ख़ुश है कि भारत आकर चीनी प्रमुख ने हमारी इज़्ज़त अफजाई तो कर दी.

पाकिस्तान के संदर्भ में बहुत कुछ कहना लाज़िमी नहीं. वह एक ख़त्म देश है. वहां कट्टरपंथियों का बोलबाला है. पाकिस्तानी सेना बस इसी बात पर पूरा खेल खेल रही है कि अमेरिका और चीन दोनों ही उसे अपने-अपने खेमे में रखना चाहते हैं. दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा रहा है और कांग्रेस सरकार अपना मुंह लेकर खड़ी है. पाकिस्तान के संबंध में हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी असफलता का राज़ तब खुला, जब ओबामा सरकार ने पाकिस्तान को डॉलरों की बहुत बड़ी किस्त और लड़ाकू विमान दे दिए. अब लड़ाकू विमानों और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई में क्या काम? यह बात हम अमेरिका से नहीं पूछ पाए. ओबामा ने एक तरफ़ कहा कि पाकिस्तान अपना आतंकी तंत्र बंद करे और वहीं ये सारे काम भी कर डाले. अब सरकार सोचे और बताए कि वह इसके बावजूद अमेरिका की पूंछ क्यों पकड़े हुए है? जो बचा-खुचा था, विकिलीक्स ने साल के अंत में वह भी पूरा कर दिया. वाशिंगटन से लीक हुए केबलों ने बताया कि किस शर्मनाक तरीक़े से हमारे गृहमंत्री अमेरिकियों से गिड़गिड़ा रहे थे कि कम से कम वे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को डेविड हेडली से मिलने भर दें, ताकि भारतीय जनता को बताया जा सके कि सरकार किस तरह अमेरिका से दोस्ती के फ़ायदे ले रही है. मतलब भारतीय जनता को इस सरकार ने बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. आज भी 26/11 का मास्टर माइंड हाफिज़ सईद पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है, भारत विरोधी काम कर रहा है और भाषण भी दे रहा है, लेकिन अमेरिका की दोस्ती से हम बाज़ नहीं आए, उसकी दोहरी नीति का शिकार बन गए. भारत को एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी होगी, अगर वह विश्व में अपनी एक अलग साख बनाए रखना चाहता है. कभी-कभी इतिहास के पन्नों में भी जाना गलत नहीं होता. नेहरू के पंचशील एवं गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों को याद करना चाहिए और इंदिरा गांधी की सशक्त विदेश नीति को, जिनके चलते आज हम वहां हैं, जहां इतनी जल्दी पहुंचना मुश्किल था. अगर इन दोनों में नव उदारवादी मानसिकता होती तो आज हम पाकिस्तान या ब्रिटेन की तरह अमेरिका की गुलामी कर रहे होते. राहुल गांधी और नेहरू में एक फ़र्क़ है. नेहरू भी एक समय भारत के मनोनीत प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय विचारों को पोषित किया और कभी उन्हें व्यक्त करने में डरे नहीं. आज़ादी से पहले ही नेहरू ने भारत को एक अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण दे दिया था. आज के राहुल गांधी में ऐसी कोई बात नहीं दिखती. उनका तो कोई दखल ही नहीं है विदेश नीति निर्धारण में. हैरानी की बात यह है कि आज तक उन्होंने किसी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर अपने विचार ही व्यक्त नहीं किए.

सरकार ने जनता को बताया कि चीन का आज तक का सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी बेन के साथ आया था. बहुत बिजनेस मिला. जबकि सच्चाई यह है कि चीन के साथ व्यापारिक संबंधों में भारत की मिट्टी पलीद हो गई.

फोटो- प्रभात पाण्डेय

feedback@chauthiduniya.com

ट्यूनीशिया की ट्यून समझें

राजीव रंजन तिवारी

अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में अफ़रातफरी का माहौल है. पूरे देश में आपातकाल लागू है. जनता के दबाव में कुर्सी छोड़ने के बाद राष्ट्रपति ज़ैनुल अबेदीन बेन अली अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भाग गए हैं. ट्यूनीशियाई जनता अभी भी संतुष्ट नहीं है. वहां ख़ूनख़राबा जारी है. देश की पूरी व्यवस्था सेना के हाथ में है. तक़रीबन तेईस साल तक सत्ता में बने रहे राष्ट्रपति बेन अली को इस्तीफ़ा तब देना पड़ा, जब देश में फैले भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी और महंगाई के ख़िलाफ़ हो रहे विरोध प्रदर्शन न सिर्फ़ हिंसक और उग्र होने लगे, बल्कि चारों ओर रैलियां होने लगीं. बेन अली की पहचान एक तानाशाह शासक के रूप में थी, उनके क्रियाकलाप आम जनता को दुखी कर रहे थे. उन्हें सत्ता से बेदखल करके ट्यूनीशिया के लोगों ने दुनिया भर के नेताओं को यह संदेश दिया है कि वे यदि नहीं सुधरे तो उन्हें बेन अली जैसी हालत से गुजरना पड़ सकता है.

ऐसे दुर्दिन से गुजरना होगा, इस बारे में बेन अली ने ख़ुद सपने में भी नहीं सोचा था. इस संकट के दौर में वह अकेले हैं. कोई भी मित्र देश उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है. बताते हैं कि देश छोड़कर भागने के बाद उन्होंने यूरोप के कई देशों में अपना विमान उतारने की अनुमति मांगी, पर कहीं से उन्हें इजाज़त नहीं मिली. फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोज़ी ने भी उनके विमान को उतरने की अनुमति नहीं दी. उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि फ्रांस में लाखों ट्यूनीशियाई अप्रवासी रहते हैं, जो बेन अली के ख़िलाफ़ हैं और हम उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहते. अंत में बेन और उनके परिवार को सउदी अरब में शरण मिली. अब स्थिति यह है कि मध्य पूर्व के देशों में ट्यूनीशिया के घटनाक्रम पर नज़र रखी जा रही है. मिस्र और दूसरे निरकुंश सत्ता वाले देशों में लोकतंत्र समर्थकों ने ट्यूनीशिया में हुए नाटकीय बदलाव का स्वागत किया है.

मिस्र की राजधानी काहिरा में कुछ लोगों ने ट्यूनीशियाई दूतावास के बाहर खड़े होकर राष्ट्रपति होस्नी मुबारक़ के ख़िलाफ़ नारे लगाए. बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और दशकों से चली आ रही तानाशाही से नौजवान निराश और हताश थे. माना जा रहा है कि ज़्यादातर अरब देशों की सरकारें इस मसले पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने में शायद इसीलिए घबरा रही हैं कि इनमें से कुछ देश बेन अली को अपना रोल मॉडल मानते हैं. अब उन राष्ट्राध्यक्षों को भी डर सता रहा है कि कहीं उनका भी हश्र बेन अली जैसा न हो जाए. कहा जा रहा है कि 23 वर्षों से अधिक के अपने कार्यकाल में बेन अली को शासन के सबसे खराब दौर से गुज़रना पड़ रहा है. वह अब तक के ट्यूनीशिया के दूसरे राष्ट्रपति हैं. कुछ दिनों पूर्व प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प के बाद उन्होंने टेलीविज़न पर एक भावुक भाषण के दौरान 2014 में अपने प्रस्थान की घोषणा की थी. फिर भी उनके विरोधी शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे. स्थिति अनियंत्रित होते देखकर बेन अली को टीवी पर लोगों के सामने आना पड़ा था. अपने भाषण के दौरान कई बार उनकी आंखें नम हुईं. उन्होंने पहली बार अरबी के बजाय स्थानीय बोली में भाषण दिया.

बेन अली के सबसे मुखर विरोधी नजीब चेबी ने कहा कि राष्ट्रपति ने सही किया. नजीब चेबी को पश्चिमी राजनयिकों द्वारा विपक्ष में सबसे विश्वसनीय आदमी के रूप में देखा जाता है. उन्होंने कहा कि अभी यह देखना बाक़ी है कि इसे व्यवहार में किस तरह लाया जाएगा. ग़ौरतलब है कि ट्यूनीशिया में अशांति उस वक़्त से ज़्यादा फैल गई, जब मध्य दिसंबर 2010 के दौरान एक बेरोज़गार स्नातक ने आत्मदाह कर लिया था. वह अपनी आजीविका सब्ज़ी बेचकर चलाता था. तबसे बेरोज़गारी और खाद्यान्न के दामों में वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी ट्यूनीशिया के लोगों की ही तारीफ़ की, न कि बेन अली की. उन्होंने लोगों के साहस की प्रशंसा करते हुए देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की अपील की है. ट्यूनीशिया के बदले घटनाक्रम के तहत संसद के स्पीकर फौआद मेबाज़ा ने अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है, लेकिन सड़कों पर ख़ूनख़राबा अब भी जारी है. यदि ट्यूनीशिया के हालात को भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहां भी सत्ता विरोधी अनेक सवाल पैदा होंगे. ट्यूनीशिया और भारत की कई समस्याएं एक समान हैं. जैसे भ्रष्टाचार, भूख एवं बेरोज़गारी. नेताओं में तानाशाही तो शायद बेन अली से भी ज़्यादा है.

ट्यूनीशिया के हालात पर त्वरित टिप्पणी करते हुए जाने-माने कूटनीतिज्ञ एवं विदेशी मामलों के जानकार मृदुल त्यागी कहते हैं कि वहां जनाक्रोश की जीत हुई है. बेन अली के तानाशाही रवैये ने ट्यूनीशिया में लोगों का जीना मुहाल कर दिया था. बेन अली से वहां की जनता कितनी तंग और परेशान थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सत्ता से हटने के बाद भी वहां बेन अली विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं. त्यागी ने भारतीय राजनयिकों एवं राजनीतिज्ञों को सलाह दी है कि वे ट्यूनीशिया की ट्यून को समझें, उसका आकलन करें और ख़ुद में सुधार लाएं. वह कहते हैं कि भारत में जन प्रतिनिधियों के बढ़ते अधिकार से जनता में समानता के भाव ख़त्म होते जा रहे हैं. हूटर और लालबत्ती लगी गाड़ियों में बैठते ही नेताओं के मन में तानाशाही पैदा होने लगती है. यही वजह है कि आएदिन सूचना मिलती है कि फरियाद लेकर नेता के दरवाजे पहुंचे किसी ग़रीब, दलित एवं पीड़ित को दुत्कार कर भगा दिया गया. इससे बचने की ज़रूरत है, वरना ट्यूनीशियाई कारनामे यहां भी हो सकते हैं. ख़ैर, अब देखना यह है कि बेन अली के बाद ट्यूनीशिया का कौन सा चेहरा विश्व के मानचित्र पर चमकता है. ट्यूनीशिया के लोगों को अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों का समर्थन प्राप्त है, यह देखते हुए कहा जा सकता है कि वहां स्थितियां जल्द ही सामान्य हो जाएंगी.

feedback@chauthiduniya.com

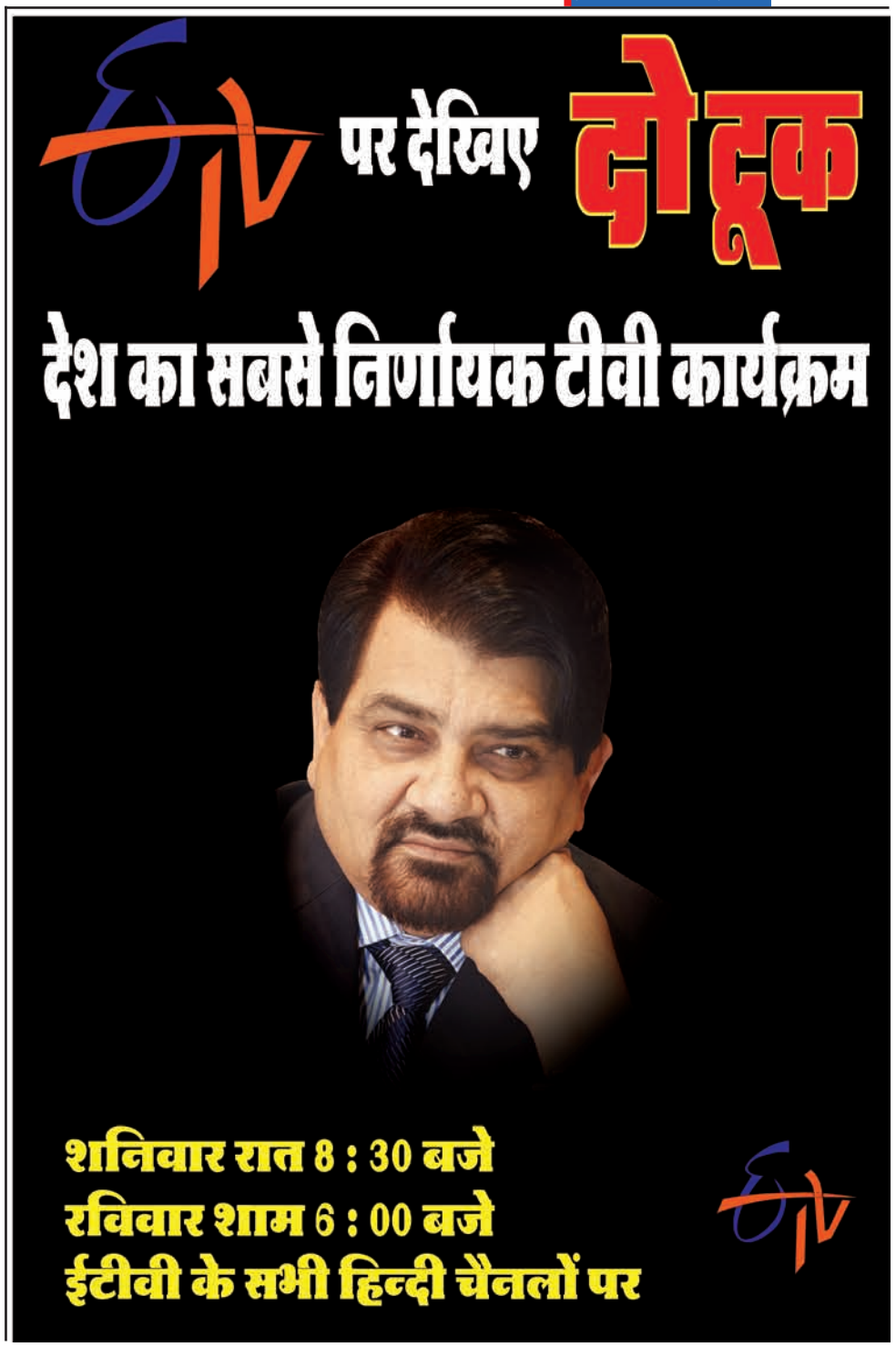

मुझे लगा क्या बाबा फिर मुझसे नाराज हैं. मैंने बाबा को फिर पुकारा, सपने में आ कर बाबा ने फिर कहा अपने जीवन का मक़सद, तुझे चुना गया है, मेरा प्रचार प्रसार कर.

साई के बिना जीवन

ऑसिम खेत्रपाल

मैंने जीवन में परमात्मा का अनुभव बहुत जल्द ही कर लिया, लेकिन साई बाबा का अनुभव 1998 में हुआ. इतनी कम उम्र में ही भारत की सबसे सफल स्पोर्टस प्रमोशन की कंपनी की सफलता का स्वाद चख मैं एक दम रसातल में था. अपनों से धोखा खाया. सब कुछ लुट चुका था. जीवन से हारकर किसी के कहने पर मैं परिवार समेत किसी चमत्कार की अपेक्षा से, शिरडी के द्वार पहुंचा. दुनिया से टूटा, बिखरा सा बाबा के दर पर जाकर बैठा था कि बाबा के साक्षात दर्शन हुए. इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था, इसलिए लगा सपना है कि शायद सपना होगा. अभी इसी अविश्वास में था कि अचानक बाबा बोले–क्या सोच रहा है? तू मेरा बेटा है, उठ और मेरा काम कर, मेरा प्रचार कर.....

मैं बोला– बाबा, आप मेरा परिवार संभालों और मुझे मुक्ति दे दो. मैं अब और नहीं बर्दाश्त कर सकता. मैं इन्हें आपके हवाले कर बस मुक्त जीवन जीना चाहता हूं. बाबा बहुत ही प्यार से बोले– बेटा, अभी से हार मान ली. अभी तो बहुत काम बाक़ी है. चल उठ जा और मेरा प्रचार कर, तू मेरा बेटा है, यही तेरा काम है. नींद खुली तो सामने कोई न था, लेकिन बाबा का अहसास बहुत गहरा था. उनकी आवाज़ मेरे कानों में अब भी गूंज रही थी. उनके होने का अुनभव काल्पनिक नहीं, बल्कि सच था. मैंने सोचा, चलो जैसा सुना था वैसा ही चमत्कार हुआ. बाबा के चरणों में आकर ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है. मेरे साथ भी चमत्कार होगा और मैं मुश्किलों से निकल जाऊंगा. चमत्कार हुआ, मुश्किल से बाहर भी निकला. लेकिन तब से शायद कुछ और ही तय हो गया मेरे जीवन के लिए. लगा कि जैसे मेरे जीवन का रास्ता कोई और तय कर रहा था. बिजनेस फिर शुरू हुआ. चूंकि बाबा के शब्द याद थे. मैंने बाबा के जीवन पर फिल्म बनाना की योजना बनाई. फिल्म बनी और ख़ूब चली. लेकिन मेरे जीवन के लिए कुछ और ही तय था. जब–जब भी मैंने बिजनेस पर काम किया, वह फेल होता गया. आज तक जिन प्रोजेक्टेस को करने में मुझे कभी भी फाइनेंसर या स्पॉन्सर्स की कमी नहीं रही थी, वो मुझ पर पूरा विश्वास करते थे. मैं न सिर्फ़ पूरा इवेंट करता था, बल्कि स्पॉन्सर्स और अपने लिए पैसे भी बनाता था और हर इवेंट बहुत सफल होता था. अचानक मेरे स्पॉन्सर्स मुझ पर अविश्वास करने लगे, बिजनेस फिर पिछड़ने लगा. मुझे लगा क्या बाबा फिर मुझसे नाराज़ हैं. मैंने बाबा को फिर पुकारा, सपने में आ कर बाबा ने फिर कहा अपने जीवन का मक़सद याद कर. तुझे उसी के लिए चुना गया है. मेरा प्रचार प्रसार कर. जबसे होश संभाला था, सिर्फ़ यही समझा था कि इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए या कोई भी मुक़ाम तय करने के लिए ख़ुद को प्रमोट करना पड़ता है. अब गुरु के प्रचार–प्रसार के लिए क्या करूं. शायद समझ ही नहीं पा रहा था, इसी बीच बाबा से जुड़े लोगों के जो अनुभव थे, उस पर आधारित एक धारावाहिक बनाने की सोची. मजे कि बात ये है कि इस प्रोजेक्ट के सारे काम आसानी से होते गए. चैनल भी मान गया. फाइनेंसर मिला और स्पॉन्सर भी. बाबा बार–बार कहते गए सब सब कुछ भूलकर सिर्फ़ मेरा काम कर. मैं, मुश्किलों में फंसा, समझ ही नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रहे थे. इसके बाद तो जब–जब उनसे जुड़ा काम किया, वह सफल रहा लेकिन अपना कोई काम शुरू किया तो वह असफल रहा. फिर मैं समझा कि जब आप अपनी सारी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं किसी काम से जोड़ लेते हो तो आपका कल्याण स्वयं ही हो जाता है. शायद आप जो अपनी योजना बनाते हैं, उससे भी बेहतर और बड़ी योजना उसकी होती है. धीरे–धीरे मैंने जब इस राज को समझा और अपने जीवन के इस सफ़र को जाना, मैं नतमस्तक होकर उसकी शरण में हो लिया. आज मेरा हर पल उससे जुड़ा है. मेरा हर काम उसके लिए हुआ. धीरे–धीरे मैं यह भी समझा कि क्या बाबा को प्रचार–प्रसार की ज़रूरत थी? असल में नहीं थी. ज़रूरत लाखों–करोड़ों दर्द में डूबी आत्माओं तक उनका संदेश पहुंचाने की थी. उनके अहसास को उन तक पहुंचाना था. मक़सद था बाबा का ऐसा परिवार बनाना, जिसमें हर पल एक ऊर्जा और एक शक्ति बल दे कि बाबा का साथ हमारे साथ है और उनका हाथ हमारे सिर पर हमेशा रहेगा. ओम साई राम.

feedback@chauthiduniya.com

साई की महिमा के इस अंक में हम आपके लिए एक प्रतियोगिता लेकर आए हैं. इसमें हम आपसे बाबा के जीवन से जुड़ी पहेली पूछेंगे.

इस बार की पहेली साई सच्चरित्र से जुड़ी है. आपको हमें बताना है कि साई सच्चरित्र में बाबा का चक्की पर गेहूं पीसने का प्रसंग किस चैप्टर में है और बाबा गेहूं किस प्रयोजन से पीस रहे थे.

सही जवाब भेजने वाले तीन विजेता पाठकों को फाउंडेशन की ओर से आकर्षक ईनाम मिलेंगे. आप अपने जवाब हमें भेज सकते हैं इस पते पर

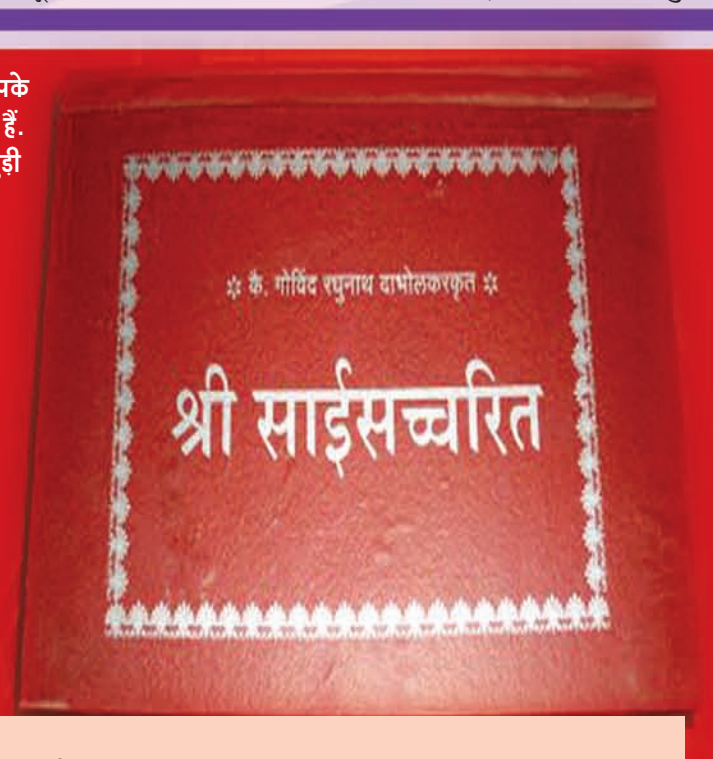

शिरडी साई बाबा फाउंडेशन,
एच 252, कैलाश प्लाजा, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश
नई दिल्ली- 110065
आप अपने जवाब info@ssbf.in भी पर भी भेज सकते हैं.
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें. 011-46567351, 46567352

ग्यारह वचन

१. जो शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा।
२. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर। पैर तले दुःख की पीढ़ी पर।
३. त्याग शरीर चला जाऊँगा। भक्त हेतु दौडा आऊँगा।
४. मन में रखना दृढ़ विश्वास। करे समाधी पूरी आस।
५. मुझे सदा जीवित ही जानो। अनुभव करो सत्य पहचानो।
६. मेरी शरण आ खाली जाए। हो कोई तो मुझे बताए।
७. जैसा भाव रहा जिस मन का। वैसा रुप हुआ मेरे मन का।
८. भार तुम्हारा मुझ पर होगा। वचन न मेरा झूठा होगा।
९. आ सहायता लो भरपूर। जो माँगा वह नही है दूर।
१०. मुझ में लीन वचन मन काया। उसका ऋण न कभी चुकाया।
११. धन्य धन्य व भक्त अनन्य। मेरी शरण तज जिसे न अन्य।

संपर्क करें:
शिरडी साईं बाबा फाउन्डेशन
252-H, LGF कैलाश प्लाज़ा, सन्तनगर, ईस्ट अफ़ कैलाश, मेन रोड, नई दिल्ली–110065.
Tel./Fax: 91-11-46567351/52
web: www.ssbf.in

आरती श्री शिरडी के साईबाबा की

आरती श्री साई गुरूवर की, परमानंद सदा सुरवर की
जाकी कृपा विपुल सुखकारी, दुख, शोक, संकट, भयहारी
शिरडी में अवतार रचाया, चमत्कार से तत्व दिखाया
कितने भक्त चरण पर आए, वे सुख शांति चिरतंन पाए
भाव धरे मन में जैसा, पावत अनुभव वो ही वैसा
गुरू की लगावे तन को, समाधान लाभत उस मन को
साई नाम सदा जा गावे, सो फल जग में शाश्वत पावे
गुरूबारसर करि पूजा सेवा, उस पर कृपा करत गुरुदेवा
राम, कृष्ण, हनुमान रूप में, दे दर्शन जानत जो मन में
विविध धर्म के सेवक आते,
दर्शन से इच्छित फल पाते
जय बोलो साई बाबा की,
जय बोलो अवधूत गुरू की
साईदास आरती को गावे, घर
में बसि सुख मंगल पावे.

कृष्ण की नगरी में आपका अपना घर!

Giriraj Sai Hills

Sai Vihar Township
Spiritual home... away from home

- Fully Furnished and Spacious studio Apartments.
- One Bedroom Apartments.
- Two bedroom Apartments.
- Fully Furnished Villas.

STARTING FROM RS. 9.65 LAKHS*

AUM Infrastructure & Developers
Aum Infrastructure & Developers
Email: info@ssbf.in
Website: www.girirajsaihills.in

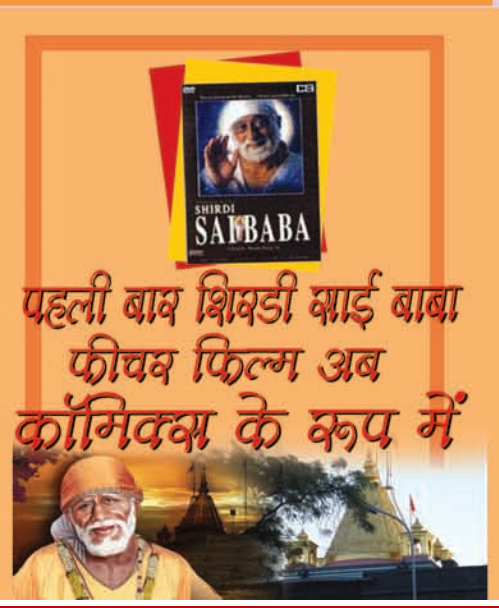

बाऊ जी 1950 से 1952 तक देश की संसद के अस्थायी सदस्य रहे. जब 1952 में देश के पहले आम चुनाव हुए तो उन्हें रोहतक से लोकसभा सदस्य चुना गया.

वर्धा में दो दिन

अनंत विजय

बेहद सर्द सुबह थी, कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था. मैं बात कर रहा हूं जनवरी के पहले हफ्ते की, जब अचानक दिल्ली में सर्दी कम हुई थी और कोहरा घना हो गया था. मुझे वर्धा जाना था और उसके लिए नागपुर की फ्लाइट लेनी थी, जो दिल्ली एयरपोर्ट से सुबह सवा पांच बजे थी. ज़ाहिर तौर पर मुझे घर से तड़के साढ़े तीन बजे निकलना था. टैक्सी लेकर घर से निकला तो कार की लाइट और कोहरे के बीच संघर्ष में कोहरा जीतता नज़र आ रहा था. इंदिरापुरम का इलाक़ा कुछ खुला होने की वजह से कोहरा और भी ज़्यादा था. एक जगह तो हमारी गाड़ी डिवाइडर से टकराते-टकराते बची. सामने कुछ दिख नहीं रहा था, अंदाज़ से गाड़ी चल रही थी, लेकिन वर्धा का गांधी आश्रम और महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय देखने की इच्छा मन में इतनी ज़्यादा थी कि वह कोहरे पर भारी पड़ रही थी. किसी तरह चलते-चलाते हम हवाई अड्डे तक पहुंचने वाले थे, लेकिन ड्राइवर के सुझाव पर हम हवाई अड्डे के ठीक पहले चाहरदीवारी से घिरे गांव मेहरमपुर में घुस गए. हवाई अड्डे के पहले इतनी बड़ी बस्ती, जिसका हमें आज तक एहसास भी नहीं था. वह पूरी बस्ती तो सुबह चार-सवा चार बजे पूरी तरह से जगमगा रही थी. चाय की दुकानें खुली थीं और कुरियर कंपनी के कर्मचारी अपने काम में तन्मयता से लगे थे. उन्हें देखकर लग रहा था कि न तो उन्हें ठंड का एहसास था और न ही कोहरे का भय. हमने भी वहां रुककर चाय पी. उस हाड़ कंपा देने वाली ठंड में चाय पीने का आनंद ही कुछ और था. इच्छा थी उस बस्ती में घूमकर वहां की ज़िंदगी को देखता, लेकिन फ्लाइट छूटने से घंटे भर पहले पहुंचने की मजबूरी की वजह से यह संभव नहीं हो पाया.

लगभग सवा घंटे की उड़ान के बाद जब सुबह सवा सात बजे नागपुर पहुंचा तो बेहद शांत हवाई अड्डा शहर के मिजाज़ का भी एहसास करा रहा था. थोड़ी देर वहां रुकने के बाद मैं वर्धा के लिए रवाना हो गया, क्योंकि सुबह ग्यारह बजे से वहां दो दिनों का राष्ट्रीय सेमिनार होना था, जिसमें भाग लेने के लिए वक़्त पर पहुंचना ज़रूरी था. नागपुर से तक़रीबन डेढ़ घंटे में वर्धा पहुंचा. विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करते ही सामने फादर कामिल बुल्के अंतरराष्ट्रीय छात्रावास दिखा. वहीं हमारे रुकने का इंतज़ाम था और पत्रकारिता के उत्साही छात्र हमारे स्वागत के लिए खड़े थे. वहीं हमारी मुलाक़ात जनमोर्चा के संपादक एवं बुज़ुर्ग पत्रकार शीतला सिंह और वरिष्ठ लेखक गंगा प्रसाद विमल से हुई. विमल जी सुबह की सैर से लौटकर आए थे और शीतला सिंह छात्रावास के बाहर धूप सेंक रहे थे. सुबह वहां भी ठीकठाक ठंड थी, लेकिन लोग बता रहे थे कि दिन में मौसम गर्म हो जाता है. शीतला सिंह से गपशप करते हुए पुराने हिंदुस्तानी प्रदीप सौरभ से मुलाक़ात हो गई. खुले आकाश के नीचे बैठकर ठंड में धूप का आनंद लेना दिल्ली में तो कभी नसीब नहीं हुआ, इसलिए छात्रों के बार-बार कमरे में जाकर आराम करने की सलाह को नज़रअंदाज़ करते हुए वहीं बैठा रहा. कुछ देर बाद पत्रकारिता विभाग के युवा एवं उत्साही प्रोफेसर और अध्यक्ष अनिल के राय अंकित भी आ गए, जो इस कार्यक्रम के संयोजक थे. उनसे गपशप करने के बाद विश्वविद्यालय के दिल्ली केंद्र प्रभारी मनोज राय के साथ मैं कैंपस घूमने निकल गया. हम वहां भी गए, जहां बैरकनुमा चार कमरों से विश्वविद्यालय शुरू हुआ था. सड़क के आमने-सामने विश्वविद्यालय के दो कैंपस हैं, लेकिन अभी मुख्य कैंपस में ही ज़्यादा हलचल और चहलपहल थी, क्योंकि विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारियों के दफ्तर और आवास इसी कैंपस में हैं. पूरे विश्वविद्यालय कैंपस के चारों ओर रिंग रोड बनाकर उसे सुरुचिपूर्ण तरीक़े से एक आकार दिया जा रहा है. ऊपर एक जगह गांधी हिल है, जहां पहाड़ी के हिस्से को एक छोटे पार्क के तौर पर विकसित किया गया है, जिसमें तीन बंदरों की मूर्तियों के अलावा गांधी जी की घड़ी और उनका चश्मा भी है. पहाड़ी के ऊपर पानी की कमी के बावजूद गांधी हिल पर तमाम फूल-पौधे लहलहा रहे थे. छात्रों ने बताया कि कुलपति की व्यक्तिगत रुचि की वजह से ही यह हो पाया.

नियत समय पर हम लोग विश्वविद्यालय के हबीब तनवीर सभागार में पहुंचे और बाबू विष्णुराव पराड़कर को नमन कर कार्यक्रम शुरू हुआ. बनारस से आए विद्वान प्रोफेसर राममोहन पाठक और कोलकाता विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग की प्रोफेसर ताप्ती बसु का भाषण हुआ. बोझिल से कार्यक्रम में गर्मी आई, जब हरिभूमि के संपादक हिमांशु द्विवेदी ने जोशीले अंदाज़ में यह साबित करने की कोशिश की कि पत्रकारिता भी कारोबार है और पत्रकारिता के गिरते

स्तर के लिए पाठक भी ज़िम्मेदार हैं. हिमांशु ने कहानियां, चुटकुले और शेर सुनाकर ख़ूब तालियां बटोरीं, लेकिन बाद में जब गंगा प्रसाद विमल और कुलपति विभूति नारायण राय बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने हिमांशु के भाषण की धज्जियां उड़ा दीं. जोश में विमल जी ने तो सारे संपादकों और पत्रकारों को बिचौलिया क़रार दे दिया. कुलपति ने भी डंके की चोट पर कहा कि पत्रकारिता और किसी व्यवसाय की तरह नहीं है. जब भी मीडिया की आज़ादी पर हमला हुआ तो पूरा समाज उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो गया. इस वजह से मीडिया से समाज की अपेक्षा भी है. लेकिन जोश में कुलपति ने भी मीडिया संपादकों को भ्रष्ट क़रार दे दिया. जिस पर बाद में उन्होंने अगले दिन, जब यह मुद्दा उठा तो सफाई देते हुए कहा कि उन्हें मिसकोट किया गया. दो सत्रों में यह विमर्श हुआ. दोनों सत्रों में बुज़ुर्ग प्रोफेसरों और पत्रकारों ने विमर्श किया, जिनकी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा निराश हुआ. पत्रकारिता कहां से कहां चली गई, लेकिन वे लोग अब भी मिशन की लकीर पीट रहे हैं. मुझे लगता है कि पत्रकारिता पर बात हो तो युवा पत्रकारों को ज़्यादा मौक़ा मिलना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय के बुज़ुर्ग प्रोफेसर न तो नई तकनीक से अवगत हैं और न मीडिया में पिछले दशक में आए बदलाव से. ऐसे में पत्रकारिता के छात्रों को हम नैतिकता और मिशन की घुट्टी तो पिला देते हैं, लेकिन व्यवहारिकता छूट जाती है. अनिल के राय अंकित युवा विभागाध्यक्ष हैं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इस तरह के सेमिनार में वह युवाओं को भी बराबरी का मौक़ा देंगे. इससे छात्रों को नई तकनीक और माहौल में काम करने का तरीक़ा और दबाव दोनों का पता चलेगा.

अगले दिन टीवी पर केंद्रित सत्र था, जिसकी अध्यक्ष कोलकाता विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग की अध्यक्ष ताप्ती बसु थीं और वक्ता थे वरिष्ठ पत्रकार एवं ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के महासचिव एन के सिंह, जी न्यूज़ के एंकर एवं राजनीतिक संपादक पुण्य प्रसून वाजपेयी, आगरा विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष गिरिजा शंकर शर्मा और मैं. एन के सिंह ने बीज वक्तव्य में जोर देकर इस बात को कहा कि आज समाज के हर क्षेत्र में मूल्यों में गिरावट देखी जा सकती है, चाहे वह राजनीति हो, कार्यपालिका हो या फिर विधायिका. उन्होंने तर्कपूर्ण तरीक़े से अपनी बात रखते हुए कहा कि मूल्यों के क्षरण की समस्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में खामी की वजह से है. मैंने पूर्ववर्ती वक्ताओं द्वारा पूरे मीडिया को भ्रष्ट और संपादकों को बिचौलिया कहे जाने पर गहरी आपत्ति जताते हुए कहा कि विभूति नारायण राय और गंगा प्रसाद विमल की समाज में एक अहमियत है और जब वे बोलते हैं तो समाज पर असर डालते हैं. इस वजह से उन्हें इस तरह के स्वीपिंग रिमार्क से बचना चाहिए. प्रसून ने अपने अंदाज़ में बोलते हुए गूगल को पत्रकारिता का पर्याय न मानने की सलाह दी. इसके बाद भी एक सत्र हुआ, जिसमें प्रकाश दूबे एवं विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति अरविंदाक्षन ने अपनी बात रखी. कुल मिलाकर दो दिनों तक चला यह कार्यक्रम बेहद सफल रहा. लेकिन जैसा कि मैं ऊपर भी कह चुका हूं कि ऐसे कार्यक्रमों में युवा पत्रकारों की भागीदारी इस विमर्श को एक अलग स्तर पर लेकर जाएगी, क्योंकि विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की राय पुरानी पड़ चुकी है और वे अपनी विद्वता के बोझ तले इतने दब चुके होते हैं कि उन्हें जो कुछ नया हो रहा है, उसे जानने में रुचि नहीं रहती. दो दिनों तक वर्धा प्रवास के दौरान मैं गांधी आश्रम भी गया, मैंने उनके कमरे की हर चीज को देखा-छुआ. मैं इस स्तंभ में आश्रम के अपने अनुभवों को भी लिखूंगा.

(लेखक आईबीएन-7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

पुस्तक अंश मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे

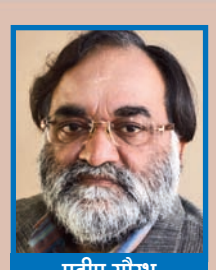

प्रदीप सौरभ

अचानक ख़ामोशी टूटी-मामा, मैं लव मैरिज करने जा रही हूं, अस्मिता ने बड़े दृढ़ स्वर में कहा.

तो इसमें समस्या क्या है? आनंद भारती बिना सोचे बोल पड़े. लेकिन उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था. उन्हें इस तरह के सवाल की अस्मिता से अपेक्षा नहीं थी.

मम्मी, कुछ अनमने भाव से बोलते हुए उसने कहा, वह इस शादी के ख़िलाफ़ हैं. पापा को तो मैंने पटा लिया है.

न मानने की वजह क्या है? आनंद भारती विस्तार से जानना चाहते थे.

लड़का अपनी जाति का नहीं है, बस मेरे साथ ही काम करता है. आपने देखा होगा, कई बार वह मेरे साथ आपके ऑफिस आया है.

ठीक है, मैं तुम्हारी मम्मी से बात करूंगा, आनंद भारती ने अस्मिता को आश्वासन सौंप दिया. इस आश्वासन के बाद अस्मिता एक उम्मीद के साथ चली गई थी. उसे विश्वास था कि मामा उसकी मदद ज़रूर करेंगे. पर स्वयं आनंद भारती अतीत के दरवाजे पर खड़े सोच रहे थे कि बचपन में बहिन जी छाप इमेज रखने वाली अस्मिता ने इतना बोल्ड फ़ैसला कैसे ले लिया. कॉल सेंटर के माहौल का असर है शायद. आनंद भारती अपने परिवार को पहचानते थे. जाति-बिरादरी उसके लिए हमेशा प्रमुख रही है. लव मैरिज और वह भी जाति के बाहर, ऐसा होने की कोई आसान गुंजाइश उसमें नहीं थी. समय के इतने सालों बाद भी वह आज मानसी से शादी न करने के लिए पछता रहे थे. हालांकि जिद्दी और अपनी बात पर अड़ने वाले आनंद भारती यदि ऐसा फ़ैसला करते तो भी उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था.

पर आनंद भारती ऐसा नहीं कर पाए थे, जिसके लिए उनके मन के एक कोने में मलाल था. अपने लिए छोड़ दिए गए उस प्रस्ताव को नियति ने उनके सामने दोबारा अस्मिता के रूप में ला खड़ा किया था. अस्मिता के तेवर देखकर लग रहा था कि यदि रजामंदी से शादी

नहीं हुई तो वह कोर्ट में शादी कर लेगी. उनके सामने मानसी का चेहरा घूम गया. यदि मानसी को ऐसा निर्णय लेना होता तो वह परिवार के विरुद्ध विवाह नहीं करती. पर हां, वह कहीं और भी विवाह न करती. उसकी पसंद नहीं तो माता-पिता की पसंद को भी वह अपने पर न थोपती. बोल्डनेस का यह अंतर बदलते मूल्यों का अंतर था, आनंद भारती समझ रहे थे. ख़ैर, उन्होंने उसी दिन फोन पर अपनी बहन से बात की. सारे घटनाक्रम को सुना. समय की नज़ाकत समझाते हुए समझाया भी कि यदि तुम नहीं मानोगी तो भी अस्मिता शादी का फ़ैसला नहीं बदलेगी. बहन को उनकी बातें समझ आ गई थीं. उसके बाद रीति-रिवाज से दोनों की शादी हो गई थी.

संडे का दिन था. अस्मिता अपने पति राहुल के साथ आनंद भारती के घर पर थी. सबने मिलजुल कर खाना खाया. फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ. अस्मिता ने राहुल से कहा, तुम ही बताओ.

तुम्हें बताते शर्म आ रही है क्या? राहुल ने अस्मिता से कहा.

अरे, जो बात हो बताओ, इसमें पहले आप, पहले आप करने की क्या ज़रूरत है? आनंद भारती दोनों की बात सुनकर बोले.

मामा, हम लोग एक समस्या में फंस गए हैं, अस्मिता बोली.

क्या समस्या है, साफ-साफ बताओ. पहेली बुझाने से समस्या हल तो हो नहीं जाएगी.

मामा, हम पर काफी क़र्ज़ हो गया है. मकान, गाड़ी और दूसरी चीज़ों की ईएमआई हमारे ऊपर भारी पड़ रही है. मुझे नौकरी से हटाने का नोटिस भी मिल चुका है.

आनंद भारती का अंदेशा सही निकला था कि आर्थिक मंदी ने ज़रूर अस्मिता की नौकरी पर ख़तरा खड़ा किया है. मामला पैसों का था. वह अस्मिता को पैसों से मदद करने के मूड में नहीं थे. और दूसरी बात यह भी थी कि इतने पैसे उनके पास भी नहीं थे कि वह उसे दे सकते. अस्मिता की बात सुनकर उन्होंने उसकी इतनी हौसला अफजाई ज़रूर की कि बैंक में किसी बड़े अधिकारी से बात कर वह वसूली करने वालों को थोड़े समय के लिए रुकवा देंगे. इस बीच तुम दूसरा कोई काम तलाश लेना. तब सब ठीक हो जाएगा. अस्मिता को थोड़ा ढांढस बंधा. अन्यथा कार लोन वाले तो साफ-साफ कह गए थे कि हफ्ते भर के अंदर ईएमआई नहीं जमा हुई तो कार उठा ले जाएंगे.

शेष उपन्यास में पढ़ें...

रणबीर सिंह हुड्डा सच्चे देशभक्त थे

रमेश सैनी

सिर पर पगड़ी, आंखों में चश्मा, तन पर खादी और निराला स्वभाव. यही पहचान थी प्रखर गांधीवादी नेता रणबीर सिंह हुड्डा की. लोग उन्हें सम्मान से बाऊ जी कहकर पुकारते थे. वह आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत बने हुए हैं. रणबीर सिंह का जन्म 26 नवंबर, 1914 को ज़िला रोहतक (हरियाणा) के गांव सांघी में किसान, स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजसेवी चौधरी मातू राम हुड्डा के यहां हुआ था. पिता मातू राम आर्य समाजी विचारधारा से जुड़े थे और सामाजिक कार्यों को महत्व देते थे. वह स्वतंत्रता संग्राम की अग्रिम पंक्ति के क्रांतिकारी योद्धा थे. उनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के स्कूल और गुरुकुल भैंसवाल में हुई. मैट्रिक उन्होंने रोहतक से किया. इस स्कूल की आधारशिला महात्मा गांधी द्वारा रखी गई थी. उच्च शिक्षा के लिए रणबीर सिंह ने गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक में दाख़िला लिया. वहां से उन्होंने 1933 में एसएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1937 में दिल्ली के रामजस कॉलेज से बीए किया. विद्यार्थी जीवन से बाऊ जी ने सत्यार्थ प्रकाश के उपदेशों को अपना लक्ष्य माना और कर्मों पर विश्वास करना ही उनके व्यक्तित्व की पहचान बन गया. स्वामी दयानंद का प्रभाव उनके मन में अमिट था, इसलिए वह उनके प्रेरणास्रोत थे. उन्होंने स्वामी दयानंद के नारे-वेदों की ओर चलो को अपने जीवन का मूलमंत्र माना और जीवनपर्यन्त आर्य संस्कृति के संवाहक बने रहे.

14 जुलाई, 1942 को बाऊ जी के पिता चौधरी मातू राम हुड्डा का स्वर्गवास हो गया और स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख स्तंभ ढह गया. बाऊ जी को पिता की मौत से गहरा सदमा लगा, सारी ज़िम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गईं. पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए वह गांधी जी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े. 1942 में उन्हें गिरफ़्तार कर मुल्तान जेल भेज दिया गया. वहां उन्हें बड़ी यातनाएं झेलनी

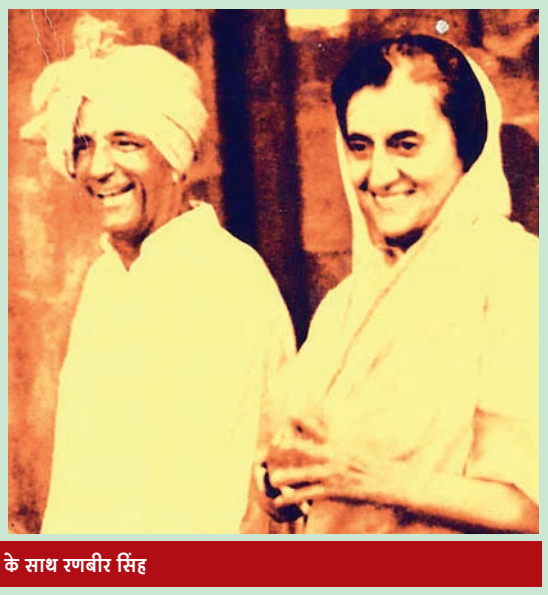

पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं इंदिरा गांधी के साथ रणबीर सिंह

पड़ीं. 24 जुलाई, 1944 को वह अन्य सत्याग्रही साथियों के साथ जेल से रिहा हुए. उनकी धारणा थी कि जल्द से जल्द प्रजातंत्र स्थापित हो और इसे पूरा करने के लिए वह कोई भी क़ुर्बानी देने को तैयार रहते थे. उनमें अभूतपूर्व संगठन क्षमता थी. वह रिहा होकर अपने घर रोहतक पहुंचे ही थे, तभी पुलिस ने झूठा मुक़दमा बनाकर उन्हें फिर गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया. 14 फरवरी, 1945 को वह जेल से रिहा हुए तो उन्हें घर में ही नज़रबंद करके रखा गया. नज़रबंदी के दौरान वह फरार होकर झज्जर के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार में जुट गए. इस पर पुलिस ने उन्हें फिर गिरफ़्तार करके एक साल के लिए जेल भेज दिया.

18 दिसंबर, 1945 को रिहा हुए बाऊ जी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साढ़े तीन साल की कठोर और दो साल नज़रबंदी की सज़ा काटी. वक़्त बदला, भाग्य बदला और 15 अगस्त, 1947 को भारत में आज़ादी का सूर्योदय हो गया. बाऊ जी की ख़ुशियों का ठिकाना न रहा. गम था तो देश के बंटवारे का. बंटवारे के समय हिंदू-मुस्लिम दंगे ने उन्हें और भी दुखी कर दिया. समय की मांग के अनुरूप डॉ. राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में संविधान निर्माण समिति का गठन हुआ. बाऊ जी को पंजाब प्रांत से संविधान सभा का सदस्य बनाया गया. संविधान की रचना में बाऊ जी ने अपना अहम योगदान दिया. किसानों, गांवों, ग़रीबों एवं सभी वर्गों के लोगों को ध्यान में रखते हुए संविधान की रचना की गई. बाऊ जी 1950 से 1952 तक देश की संसद के अस्थायी सदस्य रहे. जब 1952 में देश के पहले आम चुनाव हुए तो उन्हें रोहतक से लोकसभा सदस्य चुना गया. 1957 में वह दोबारा सांसद बने. 1962 में वह कलानोर इलाक़े से विधायक निर्वाचित हुए और प्रताप सिंह कैरो मंत्रिमंडल में बिजली एवं सिंचाई मंत्री बने. उन्होंने अपने भाखड़ा बांध का निर्माण कराया, ताकि गांव-शहर बिजली से अछूते न रहें. उन्होंने नहरों द्वारा किसानों के सूखे खेतों में पानी पहुंचाने का उल्लेखनीय काम किया. 1966 में उन्होंने संयुक्त पंजाब में उपेक्षित हरियाणा के विकास के लिए आवाज़ उठाई. 1966 में बाऊ जी के अथक प्रयासों से पृथक हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया. 1966 से 1967 तक वह पीडब्ल्यूडी एवं स्वास्थ्य विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे. उन्होंने प्रांत में सड़कों का जाल बिछा दिया और अस्पतालों का भी निर्माण कराया. 1967 में वह किलोई से विधायक बने, 1968 में पुन: यहीं से विधायक चुने गए. 4 अप्रैल, 1972 को वह राज्यसभा के लिए चुने गए. 1977 से 1980 तक वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे. इन्हीं दिनों वह कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य रहे और राज्यसभा के उप सभापति बने. 2007 में उन्हें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की.

हर पद पर बाऊ जी का कार्यकाल सराहनीय रहा. वह समय-समय पर किसानों, पिछड़ों, मज़दूरों एवं समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याएं राजनीतिक पटल पर रखते रहे. उन्होंने अपने चिंतन-दर्शन को कभी किसी पर थोपने की कोशिश नहीं की. वह सामाजिक ज्ञान के आधार पर व्यवहारिकता में विश्वास रखते थे. 1978 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया. इसके बाद वह सामाजिक उत्थान के कार्यों से जुड़ गए. बाऊ जी हरिजन सेवक संघ, पिछड़ा वर्ग संग, भारत कृषक समाज एवं अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के अध्यक्ष भी रहे. उनके अथक प्रयासों से ही स्वतंत्रता सेनानियों को 1972 में इंदिरा गांधी द्वारा पेंशन देने की योजना प्रारंभ की गई. राजीव गांधी एवं इंद्र कुमार गुजराल के प्रधानमंत्रित्वकाल में उन्होंने पेंशन राशि बढ़वाई और अनेक नई योजनाएं लागू कराईं. एक फरवरी, 2009 को बाऊ जी ने इस नश्वर संसार से विदा ले ली और छोड़ गए अपने कार्यों की महक. उन्हें जितना याद किया जाए, कम है.

feedback@chauthiduniya.com

इस नए सिस्टम के तहत नोकिया के हैंडसेट्स में डबल चार्जिंग ऑप्शन रहेगा.

मोबाइल आपका दिमाग़ पढ़ लेगा

जी हां, यह सच है. मोबाइल फोन्स की दुनिया रोज़ नए होते आकर्षक प्रयोगों के कारण आज यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं रह गई है. इसके लिए एक से बढ़कर एक ऐप्लीकेशन बाज़ार में आ गए हैं. ऐप्पल के आईफोन के ज़रिए ऐसा करना संभव हुआ है. इसके लिए एक खास ऐप्लीकेशन इस्तेमाल करना होता है जो सिर्फ़ आईफोन में ही फिट होता है. इसे एक्सवेव कहते हैं और इसे डेवलप किया है, पीएलएक्स डिवाइसेज ने. इसके लिए इसे माथे पर बांधना पड़ता है तथा इसे आईफोन के जैक से प्लग के ज़रिए जोड़ दिया जाता है. इसमें एक आधुनिक सेंसर होता है जो दिमाग़ यानी मस्तिष्क की तरंगों को पढ़ लेता है और उन्हें डिजिटल सिग्नलों में तब्दील कर देता है. इसके बाद यह आईफोन के स्क्रीन पर विभिन्न रंगों में दिखने लगता है. जैसे–जैसे व्यक्ति की सोच बदलती है, वैसे–वैसे स्क्रीन पर ग्राफिक बदलता जाता है. इसके ज़रिए पता चल जाएगा कि दिमाग़ कितना सक्रिय है या रिलैक्स. पीएलएक्स डिवाइसेज के संस्थापक और सीईओ पॉल लोकेयर ओंकुल ने लंदन के अखबार डेली मेल को बताया कि अब थोड़े समय की बात है कि यह डिवाइस आम उपयोग में आने लगेगी.

धमाल मचाएगी मारुति किजाशी

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुज़ुकी इंडिया की निग़ाह लग्ज़री कार बाज़ार में अपनी स्थिति मज़बूत करने पर है. कार मार्केट की प्रीमियम सेग्मेंट में मारुति ज़बरदस्त धमाल मचाने जा रही है. कंपनी अगले महीने नया मॉडल किजाशी लांच करने जा रही है, जो कार बाज़ार में धमाका करेगी. इस कार की स्पोर्टी लुक आपको ड्राइविंग का नया अहसास देगी. किजाशी का 2.4 लीटर पेट्रोल इंजन है. इसमें मैनुअल और आटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों के विकल्प है. इसमें फोर वील ड्राइव ऑप्शन भी मौजूद है. इस कार की अनुमानित क़ीमत 15–17 लाख रुपए होगी. कंपनी इस वाहन का आयात अपनी मूल कंपनी सुज़ुकी के जापान के संयंत्र से करेगी. मारुति की किजाशी ऊपरी वर्ग में होंडा की अकॉर्ड और टोयोटा की कैमरी तथा निचले स्तर पर होंडा सिविक, फॉक्स वैगन की जेट्टा और टोयोटा कोरोला से मुक़ाबला करेगी. इन कारों का दाम 12 से 20 लाख रुपए के बीच है. कंपनी भविष्य में किजाशी की भारत में असेंबलिंग पर विचार करेगी, पर यह तभी होगा जब मांग होगी. हालांकि, उन्होंने इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बताई. कंपनी द्वारा किजाशी को पेश करने का मक़सद सिर्फ़ बिक्री बढ़ाना ही नहीं है बल्कि कंपनी उपभोक्ताओं को लग्जरी वर्ग में विकल्प उपलब्ध कराने के मक़सद से इस कार को बाज़ार में उतार रही है.

सभी नोकिया मोबाइल में डबल चार्जिंग सिस्टम

कहीं भी निकलते वक़्त दूसरे गैजेटस के साथ मोबाइल चार्जर भी रखना पड़ता है, लेकिन मोबाइल रोज़मर्रा की ऐसी ज़रूरत बन गई है कि हर चार–पांच घंटे बाद इसे चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है. ऐसे में चार्जिंग प्वाइंट हर जगह ढूंढना मुश्किल हो जाता है. लोगों की इस समस्या को नोकिया ने बख़ूबी समझा और इसका हल भी निकाला है. नोकिया मोबाइल फोन बनाने वाली फिनलैंड की जानी मानी कंपनी नोकिया ने ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में उसके मोबाइल फोन्स में नया चार्जिंग सिस्टम लगाया जाएगा. इस नए सिस्टम के तहत हैंडसेट्स में डबल चार्जिंग ऑप्शन रहेगा. पहला ऑप्शन हैंडसेट्स में उपलब्ध होगा. दूसरे ऑप्शन में आपको बता दें कि यूएसबी के ज़रिए मोबाइल फोन को पर्सनल कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके भी चार्ज किया जा सकता है. अब तक इस तरह का सिस्टम ख़ास तौर पर एप्पल कंपनी के मोबाइल फोन के अलावा कुछ और चुनिंदा कंपनियों के हैंडसेट में ही उपलब्ध था. पर यह आकर्षक ऑफर नोकिया भी अपने उपभोक्ताओं अगले सीरीज के फोन में देने जा रही है.

सोनी एरिक्सन का यैंडो

म्यूज़िक के शौक़ीनों के लिए सोनी एरिक्सन ने ख़ास तरह का म्यूज़िकल गैजेट बाज़ार में उतारा है. ग्राहकों की उम्मीदें इस कंपनी से बढ़ गई हैं. क्योंकि पिछले कुछ वक़्त से सोनी एरिक्सन अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ बाज़ार में धूम मचा रहा है. सोनी एरिक्सन ने भी ग्राहकों के प्रेम को स्वीकाते हुए पिछले कुछ समय से कई अच्छे मोबाइल फोन की सीरीज पेश कर रही है. सोनी का मॉडल एक्सपेरिया आर्क दर्शकों के बीच आज छाए हुए है. कंपनी के बेहतर परफॉरमेंस की वजह से सोनी एरिक्सन ने नया टचस्क्रीन फोन बाज़ार में उतारा है, जो म्यूज़िक के लिहाज़ से ख़ास है. कंपनी का नया येंडो एक टचस्क्रीन फोन है और यह ख़ूबसूरत रंगों में उपलब्ध है. इसके साथ वॉकमैन का टैक जुड़ जाने से यह फोन म्यूज़िक के शौकीनों के लिए ख़ास हो गया है. इस फोन की ख़ासियत है कि यह पूरी तरह से कॉम्पैक्ट है और यह टच करते ही काम करता है. इसका स्टीरियो ब्लूटूथ काफी अच्छा है और इसमें माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट है, जिसमें 16 जीबी सपोर्ट है. इतनी सारी ख़ूबियों के बाद इस फोन की कमी की बात करें तो इसमें 3 जी और वाई फाई नहीं है जो आजकल सभी फोनों में होता है. वॉकमैन फोन होने के बावजूद इसमें बेसिक म्यूज़िक प्लेयर है. इसका कैमरा महज़ 2 मेगापिक्सल का है. यह मल्टी टास्किंग फोन है और इसका टचस्क्रीन छोटा है तो रिज़ॉल्यूशन भी कम है.

साई के बंदे

अभिनय के बाद असीम खेत्रपाल अब पार्श्वगायन के क्षेत्र में हाथ आज़मा रहे हैं. जल्द ही उनका साई के बंदे नाम का म्यूज़िक एलबम रिलीज हो रहा है. इस एलबम में असीम बतौर गायक तो हैं ही, लेकिन उनके साथ संगीत के कई बड़े दिग्गज भी उनके सुर में सुर मिला रहे हैं. इस एलबम में आपको आशा भोंसले, उषा मंगेशकर, अलका याज्ञनिक, रवींद्र जैन, सुरेश वाडेकर, विकास कपूर और हमसर हयात की आवाज़ें सुनने को मिलेंगी.

जैसा कि नाम से पता चलता है कि एलबम के गीत साई बाबा की महिमा गान करते हैं. इसलिए संगीतप्रेमियों को काफी कुछ नया मिलेगा. संगीत सूर्यराज कमल का है, जबकि गीत लिखे हैं गूफी पेंटल ने. वीडियों कॉन्सेप्ट विपिन और कनुप्रिया का है. कुल मिलाकर साई भक्तों के लिए साई के बंदे एक सौगात की तरह है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

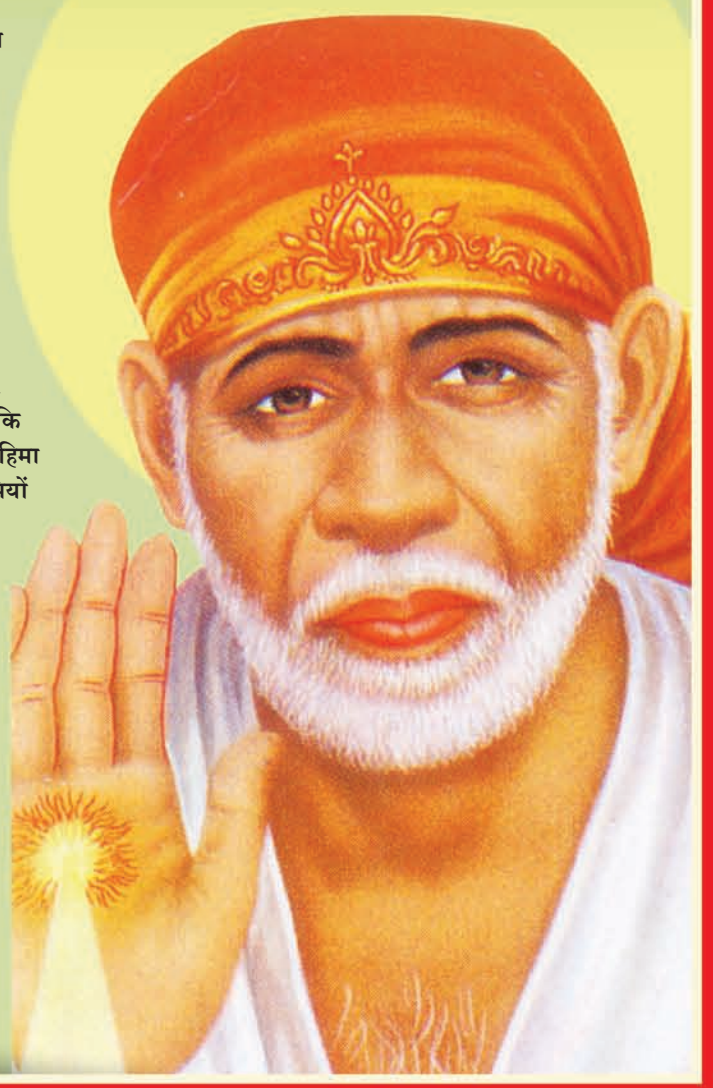

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

जानकारों की मानें तो 37 वर्षीय सचिन तेंदुलकर का यह आख़िरी विश्वकप मैच है, क्योंकि इसके बाद 2015 में होने वाले विश्वकप में सचिन के खेलने की उम्मीद काफी कम है.

यह ऐतिहासिक मौक़ा है

फिटनेस की समस्या से निजात ज़रूरी

फिटनेस की समस्या किसी भी टीम के लिए परेशानी का सबब है, लेकिन भारतीय टीम इससे कुछ ज़्यादा ग्रस्त है. विश्वकप के लिए बीसीसीआई ने 15 खिलाड़ियों का चयन तो किया है, लेकिन उनमें से 4 ऐसे हैं, जो चोटिल होने की वजह से कुछ ज़्यादा परेशान हैं. सचिन तेंदुलकर हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण दक्षिण अफ्रीका के ख़िलाफ़ दो वन डे ही खेल पाए. विस्फोटक बल्लेबाज़ वीरेंद्र सहवाग कंधे की चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के ख़िलाफ़ वन डे सीरीज से पहले ही बाहर हो गए. गौतम गंभीर हाथ पर और तेज़ गेंदबाज़ प्रवीण कुमार कोहनी पर चोट की वजह से दक्षिण अफ्रीका के ख़िलाफ़ वन डे मैच नहीं खेल पाए थे. युवराज सिंह, ज़हीर खान एवं आशीष नेहरा भी चोट से परेशान रहे हैं. ऐसे में टीम इंडिया के सामने चुनौती होगी कि वह इस समस्या से निजात पाए, ख़िलाड़ी अपनी फिटनेस पर ध्यान दें और मिशन विश्वकप में बेहतर प्रदर्शन करें.

वर्ष 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारत ने पहला विश्वकप अपने नाम किया था. उसके बाद 2003 में भारत विश्वकप के सेमी फाइनल तक पहुंचा, लेकिन फाइनल मैच में वह सफल नहीं हो सका और ऑस्ट्रेलियाई टीम विजेता बनी. 2007 में भारत सुपर-8 में भी पहुंचने में असफल रहा. इसके बाद लंबे समय से क्रिकेट प्रेमियों को विश्वकप 2011 का इंतज़ार था. वह वक़्त आ गया. 19 फरवरी से विश्वकप 2011 का आगाज़ हो रहा है. विश्वकप के लिए 15 भारतीय खिलाड़ियों की सेना भी तैयार है. भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर मैच उसके घरेलू मैदानों पर हो रहे हैं. भारतीय टीम के लिए मौक़ा है कि वह घरेलू पिच पर विपक्षियों को मात दे. वहीं टीम के खिलाड़ियों की कुछ परेशानियां भी हैं. ज़्यादातर खिलाड़ी फिटनेस की समस्या से परेशान हैं. चयनित 15 खिलाड़ियों में से 8 को ही विश्वकप में खेलने का अनुभव है. इन समस्याओं के लिए दोषी चयनकर्ता हैं, जिन्होंने खिलाड़ियों का चयन करते वक़्त इन बिंदुओं को नज़रअंदाज़ किया. इस विश्वकप में सबसे अहम खिलाड़ी होंगे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर. माना जा रहा है कि सचिन का यह आख़िरी विश्वकप होगा. ऐसे में सबकी निगाहें सचिन के बल्ले पर होंगी. भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए भी यह परीक्षा की घड़ी होगी, क्योंकि यह पहला मौक़ा है, जब धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया विश्वकप ट्रॉफी के लिए संघर्ष करेगी.

जानकारों की मानें तो 37 वर्षीय सचिन तेंदुलकर का यह आख़िरी विश्वकप मैच है, क्योंकि इसके बाद 2015 में होने वाले विश्वकप में सचिन के खेलने की उम्मीद काफी कम है. वेस्टइंडीज के क्रिकेटर सर विवियन रिचर्ड्स के मुताबिक़, सचिन तेंदुलकर का एक सपना है कि वह विश्वकप जीतने में अहम भूमिका निभाएं और जीत के बाद ट्रॉफी को अपने हाथों में उठाएं. रिचर्ड्स कहते हैं कि सचिन विश्व क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में से हैं और उनके नाम लगभग सभी रिकॉर्ड्स हैं. अगर सचिन का यह सपना पूरा हो जाए तो मुझे काफी ख़ुशी होगी. वहीं 1983 के विश्वकप की विजेता भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव ने कहा कि सचिन ने ग्वालियर में जब दोहरा शतक जमाया, तभी से मुझे उम्मीद है कि सचिन इस बार भारत को दूसरा विश्वकप दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे. कपिल देव के मुताबिक़, यह सचिन का आख़िरी विश्वकप हो सकता है, लेकिन वह जिस शिद्दत के साथ बल्लेबाज़ी कर रहे हैं, उसे देखते हुए अगले विश्वकप में भी उनके खेलने की उम्मीद करनी चाहिए.

चयनित 15 खिलाड़ियों का विश्वकप में प्रदर्शन

खिलाड़ी	वर्ष	मैच	रन	स्कोर	गेंदबाज़ी (ओवर)	विकेट	रन
एमएस धोनी (कप्तान)	2007	3	29	29	-	-	-
हरभजन सिंह	2003-2007	12	75	28	105.2	11	418
ज़हीर ख़ान	2003-2007	14	34	15*	117.2	23	496
आशीष नेहरा	2003	9	8	8*	69.1	15	289
वीरेंद्र सहवाग	2003-2007	14	463	114	32.0	4	120
सचिन तेंदुलकर	1992-2007	36	1796	152	116.0	8	518
युवराज सिंह	2003-2007	14	376	83	17.3	5	85
मुनाफ पटेल	2007	3	25	15	26.3	4	105

आंकड़ों से साफ है कि 15 खिलाड़ियों में से 8 ने ही इससे पहले विश्वकप में प्रदर्शन किया है. शेष 7 खिलाड़ी पहली बार विश्वकप में मैदान पर उतरेंगे. चयनकर्ताओं ने विश्वकप में अनुभवी खिलाड़ियों की अनदेखी कर नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है. ऐसे में इन सात नए खिलाड़ियों को टीम में मौक़ा दिया जाना विश्वकप में नया प्रयोग करने जैसा है.

भारत के लिए सकारात्मक पहलू यह है कि विश्वकप में होने वाले 49 मैचों में 30 मैच भारत में खेले जाने हैं. इसके अलावा 11 मैच श्रीलंका और 8 मैच बांग्लादेश में होने हैं. यानी भारतीय खिलाड़ियों को ज़्यादातर मैच घरेलू मैदानों पर ही खेलने हैं. ऐसे में भारत के सामने एक मौक़ा है कि वह घरेलू पिचों पर विदेशियों को पटखनी देकर एक और विश्वकप भारत के नाम करे. विश्वकप शुरू होने में अब कुछ दिन शेष रह गए हैं. ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों को हर परेशानी भूलकर विपक्षी खिलाड़ियों को मात देने की मंशा से मैदान पर उतरना होगा. भारतीय खिलाड़ियों के पास एक अवसर है. इतिहास रचने का. 1983 का इतिहास दुहराने का.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चयन की अजूबी प्रक्रिया

विश्वकप के लिए भारतीय खिलाड़ियों का चयन वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिए किया गया. भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और चयनकर्ताओं की हां-ना में ही चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई. चयनकर्ताओं ने सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, युवराज सिंह, सुरेश रैना एवं विराट कोहली के नाम पर आसानी से हां में हां मिला दी. इसके बाद जब आशीष नेहरा का नाम श्रीकांत ने लिया तो चेन्नई में बैठे नरेंद्र हिरवानी ने उनकी फिटनेस को लेकर धोनी से सवाल पूछे. हिरवानी ने पूछा कि क्या पूरे विश्वकप में नेहरा फिट रहकर खेल सकते हैं. इस पर धोनी ने कोच गैरी कर्स्टन से सलाह ली और फिर नेहरा के फिट रहने पर हामी भर दी. इस तरह नेहरा को टीम में शामिल कर लिया गया. इससे पहले ज़हीर ख़ान, मुनाफ पटेल एवं प्रवीण कुमार के नामों पर भी चयनकर्ता हां में हां मिलाते चले गए. इसके बाद नाम आया यूसुफ पठान का. 7वें नंबर पर बल्लेबाज़ी के लिए धोनी ने यूसुफ के नाम पर सहमति जताई. कोच गैरी ने भी यूसुफ के नाम पर हामी भरी. स्पिनर्स में हरभजन सिंह और पीयूष चावला के नाम पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई. पीयूष के टीम में शामिल करने पर सवाल उठ रहे हैं. जानकारों की मानें तो चावला के नाम पर कोच गैरी और कप्तान धोनी ने पहले ही सहमति बना ली थी. चावला के नाम पर लगी मुहर ने सबको चौंका दिया. वजह यह है कि भले ही चावला हाल में दक्षिण अफ्रीका दौरे में शामिल रहे हों, लेकिन एक सच यह भी है कि चावला ने जुलाई 2008 के एशिया कप के बाद कोई वन डे मैच नहीं खेला. ऐसे में पीयूष चावला को विश्वकप टीम में शामिल करना हैरान करने वाली बात है. चयनकर्ताओं ने तक़रीबन 45 मिनट में ही 14 खिलाड़ियों का चयन कर लिया. इसके बाद चयनकर्ताओं को एक और खिलाड़ी के नाम पर सहमति बनानी थी. राजा वेंकट ने रोहित शर्मा को दूसरा आलराउंडर खिलाड़ी रखने की बात कही. इस पर अफ्रीका में बैठे चयनकर्ता यशपाल शर्मा ने भी सकारात्मक हामी भरी. इतने में कप्तान धोनी ने यशपाल शर्मा की बात काटते हुए रोहित शर्मा का नाम ले लिया. धोनी का तर्क था कि स्पिनर हरभजन सिंह के चोटिल होने की स्थिति में आर अश्विन मोर्चा संभाल सकते हैं. इस पर मुख्य चयनकर्ता श्रीकांत ने धोनी की बात पर सहमति जता दी. इसके बाद किसी चयनकर्ता ने अश्विन के नाम का विरोध नहीं किया. इसके तुरंत बाद मीडिया को 15 खिलाड़ियों की सूची दे दी गई. चावला का टीम में आसानी से जगह पाना और इतने कम समय में हां-ना में ही चयन प्रक्रिया का पूरा होना यह साबित करता है कि खिलाड़ियों का चयन पहले ही कर लिया गया था.

देश का पहला इंटरनेट टीवी
हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक
दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
स्पेशल रिपोर्ट
नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

फोटोग्राफर किसी भी हीरोइन को सेक्सी बना सकते हैं. सेक्सी होना कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन असली चीज आपके काम की तारीफ़ है.

ग़लतियों से सीखा है

नेहा अपनी ख़ूबसूरती का राज क्या बताती है ये जानकर आपको थोड़ा आश्चर्य हो सकता है...वह कहती हैं कि इसका राज कम काम करना है. दरअसल, काम कम करने से चेहरे पर नूर आ ही जाता है. अब वह अपने आप को लेकर काफ़ी स्वार्थी हो गई हैं. वह ख़ुद को ज़्यादा वक़्त देती है और जी भरकर सोती है. इसलिए उनके चेहरे पर काफ़ी चमक आ गई है. आजकल वह रोज एक्सरसाइज करती हैं. बचपन से ही उनके मम्मी-पापा सलाह देते थे कि आठ घंटे की नींद पूरी करो. वह सलाह उन्होंने अब माननी शुरू कर दी है. वह कहती हैं कि इसके अलावा लगभग एक घंटा वह जिम में बिताती हैं और चालीस मिनट योगा करती हैं. उन्हें शुरू से ही खेल का शौक रहा है, इसलिए कभी-कभी स्क्वैश खेलने भी जाती हैं. उन्हें यह मानने से कतई गुरेज नहीं है कि वह अपने करियर में बहुत सी ग़लतियां कर चुकी हैं. वो कहती हैं कि उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में भी की हैं, जिन्हें देखने के बाद उन्हें यह अहसास होता था कि यह फिल्म क्यों की. कुछ फिल्मों की वजह से पब्लिक ने उन्हें सेक्सी और बोल्ड कैटेगरी में डाल दिया. हालांकि, बाद में वह संभल गई. वह मानती हैं कि फिल्म एक चालीस की लास्ट लोकल उनकी इमेज का टर्निंग प्वाइंट साबित हुई. और ग़लतियां होने के बाद ही उन्हें सुधारने की समझ आती है. वह कहती हैं कि मुझे अब यह बात समझ में आ गई है कि सेक्सी बनना कोई मुश्किल नहीं है. फोटॉग्राफर किसी भी हीरोइन को सेक्सी बना सकते हैं. सेक्सी होना कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन असली चीज आपके काम की तारीफ़ ही है. इसलिए अब वह ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रही हैं. वह मानती हैं कि उनकी फिल्मों की लिस्ट में मिथ्या और दसविदानिया जैसी फिल्में शामिल होने की वजह से वह इस स्टेज पर हैं, जहां विपुल शाह और प्रियदर्शन जैसे डायरेक्टर कहते हैं कि नेहा यह रोल सिर्फ़ तुम ही कर सकती हो और यह रोल तुम्हें ध्यान में रखकर लिखा गया है. एक हीरोइन को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए. वह ख़ुद को एक आम लड़की की तरह मानती है.

एक फौजी फैमिली से ताल्लुक होने की वजह से वह काफ़ी अनुशासन में रही है. वैसे, उन्हें दुनियादारी से ज़्यादा लेनादेना नहीं है और न ही वह रोमांटिक हैं. बस वह अपने आप में रहने वाली लड़की हैं.

लाइफ में ट्विस्ट है

बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी हो या प्रीति जिंटा, बिजनेस टायकून नीता अंबानी या फिर विजय माल्या, सभी का अलग अंदाज़ इस आईपीएल में देखने को मिला. पति राज कुंद्रा के साथ पहुंची शिल्पा ने माना है कि उन्होंने क़ानूनी वजह से इस बार आईपीएल में ज़्यादा पैसा नहीं लगाया. बॉलीवुड अभिनेत्री व राजस्थान रॉयल्स की सह मालकिन शिल्पा शेट्टी को इस बात का दुख है कि वे क़ानूनी अड़चनों के कारण महंगी बोली नहीं लगा सकीं. सिर्फ़ यही नहीं बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का फिल्मों और स्पा के बिजनेस पर भी संकट के बादल छाए हुए हैं. उनका स्पा का बिजनेस बंद होने की कगार पर है. इनकी लोखंडवाला स्थित दुकान में पहले ही ताला लग चुका है और अब खार व घाटकोपर में स्थित दुकान में भी ताला लगने वाला है. शिल्पा ने 2009 में आईपीएल से जुड़ने के बाद राजस्थान रॉयल्स के साथ स्पा व्यापार की शुरुआत की थी जिसमें उनके मित्र किरण बावा ने भी मदद की थी. व्यवसाय बंद होने के पीछे दुकानों के किराए को शिल्पा ने मुख्य कारण बताया है. बहरहाल उनके पति राज कुंद्रा करोड़पति आदमी हैं, ऐसे में स्पा के बंद होने की बात लोगों को हज़म नहीं हो रही है. इसके अलावा शिल्पा को अजीब सी स्थिति का सामना भी करना पड़ा. जब मुंबई मैराथन में अपनी उपस्थिती दर्ज़ कराने शिल्पा वहां पहुंची तो एक बुज़ुर्गवार भिखारी के वेश में रेस शुरू होने से पहले मंच पर जा पहुंचे. और शिल्पा शेट्टी से कहा कि मुझे भीख चाहिए. प्याज की भीख. मुझे भीख में कुछ प्याज दे दो. और कहकर ज़ोर से हंस दिए. प्याज की बढ़ती क़ीमतों पर कटाक्ष कर गए. शिल्पा वैसे तो पहले आश्चर्य में पड़ गईं फिर उनके और पास खड़ी अन्य हस्तियों के चेहरों पर भी मुस्कान खिल गई. खैर जो भी हो, उनकी हालत में ज़बरदस्त ट्विस्ट तो आ ही गया है. कुछ दिन पहले तक रानी की तरह रहने वाली शिल्पा को एक बार फिर से अपने दिन सुधारने के लिए कुछ जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो इस मायानगरी में लोग किसी को बहुत दिनों तक याद नहीं रखते. इसलिए शिल्पा के लिए यही सलाह है कि वह फिर से तैयार हो जाएं.

सीरत की अमीर है करीना

बेबो न सिर्फ़ सूरत की बल्कि सीरत की भी अमीर हैं. दरअसल उनके लिए बीता हुआ साल अच्छा रहा इस वजह से इंडस्ट्री की दूसरी तारिकाओं की तरह बेबो को ज़्यादा परेशानी महसूस नहीं हो रही है. साल की शुरुआत थ्री इडियट्स की बेहतरीन सफ़लता से हुई थी और साल जाते जाते फिल्म गोलमाल थ्री भी हिट हो गई. लेकिन इसके अलावा उनके लिए ख़ुश होने की और भी वजहें हैं. दरअसल सलमान और आमिर ख़ान के साथ तो वह पहले ही फिल्मों में काम करके हिट साबित हो चुकी हैं, लेकिन अब शाहरूख ख़ान के साथ भी स्क्रीन शेयर करने वाली हैं. अपने ब्वॉयफ्रेंड सैफ के साथ छुट्टियां मनाकर लौटी करीना अपने टीम के स्टाफ पर काफ़ी मेहरबान हैं. वह अपनी टीम के लोगों के लिए आकर्षक गिफ्ट्स और गैजेट्स बतौर उपहार लेकर आईं हैं. अपनी हेयरस्टाइलिस्ट पॉम्पी, मनीष मल्होत्रा की असिस्टेंट राधिका और मेकअप मैन रितेश के लिए गैजेट्स का तोहफ़ा लाई हैं. पॉम्पी कहती हैं कि करीना न सिर्फ़ काम के मामलों में बल्कि आम या साधारण जीवन में भी बहुत वंडरफुल हैं. वह इंडस्ट्री के कुछ बड़े सितारों में से एक हैं, जिनके साथ काम करना अच्छा अनुभव दे जाता है. इस वंडरफुल एक्ट्रेस ने अपनी पूरी टीम को नए साल के तोहफ़े में वॉकी टॉकी दिया है. इससे वह अपने स्टाफ को कभी भी कहीं भी ट्रैक कर सकती हैं. चूंकि वह काफ़ी व्यस्त रहती हैं, इसलिए सेट्स पर काम करते हुए या मीटिंग में या खाने पर कभी भी इन्हें अपने स्टाफ़ की ज़रूरत महसूस हो तो वह उन्हें तुरंत बुला सकती है. करीना देश के कई ब्रांड से जुड़ कर उनकी शान भी बढ़ा रही हैं, लेकिन पिछले दिनों वह एक किताब प्रत्यर्पण समारोह में नज़र आईं. यह कोई आम किताब नहीं बल्कि महिलाओं के ऊपर लिखी गई रूजुता ढ्विवेदी की वुमेन एंड द वेट लॉस तमाशा थी. पिछले दिनों अपना वज़न कम कर करीना ने इंडस्ट्री में बवाल मचा दिया था, तो इस किताब को लांच करने के लिए इनके बेहतर चेहरा कौन हो सकता है.

दिल आया ब्रांड पर

अभिनेता और अभिनेत्रियां एक तरह से ट्रेंड सेटर का काम करते हैं. फिल्मों के ज़रिए जो भी नयापन उनके कपड़ों, बालों और अन्य चीजों में दिखाई पड़ता है यंग जनरेशन भी उसी की शौक़ीन हो जाती है. अभिनेत्रियों के कपड़ों के अलावा महंगी एसेसरीज जैसे बैग्स, जूते और घड़ियां भी युवाओं को ख़ूब लुभाते हैं और वह वैसी चीज पाने के लिए ख़ूब पैसा ख़र्च करते हैं. इससे सामान बेचने वाली कंपनियों को तो फ़ायदा होता ही है साथ ही इस प्रोडक्ट का प्रचार करने वाले अभिनेता या अभिनेत्री को भी ख़ूब पापुलैरिटी मिलती है. मगर अनुष्का शर्मा का कहना हैं कि वह कभी कोई ब्रांडेड बैग लेकर न कहीं शामिल होती हैं और न ही ऐसे प्रोडक्ट का प्रचार करती हैं. उनका मानना है ब्रांडेड बैग्स जैसी मंहगी चीजें युवाओं ख़ासकर लड़कियों को बग़ैर सोचे समझे फैशन फॉलो करने को उकसाती हैं. वह ऐसी चीजों पर बेकार में ज़्यादा पैसे ख़र्च करती हैं. अनुष्का ने यह भी बताया कि उन्होंने पटियाला हाइस की शूटिंग के दौरान लंदन में एक ब्रांडेड बैग ख़रीदा है. अनुष्का बताती है कि उन्होंने यह बैग ख़रीदने से पहले तीन दिन सोचा और इस बारे में कई बार अपनी मम्मी को भी फोन करके पूछा कि वह बैग ख़रीदें या न ख़रीदें. पिछले दिनों अनुष्का शर्मा को वायरल फीवर हो गया था. उन्होंने तीन दिन का ब्रेक लिया और अपने माता-पिता के साथ वक़्त बिताया. अनुष्का अब ठीक हो गई हैं और अब दोबारा काम शुरू कर दिया है. अनुष्का को उनकी फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली हैं. अब वह फिल्म पटियाला हाइस में अक्षय कुमार के साथ नज़र आ रही हैं. इस फिल्म से भी अनुष्का की काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हैं.

फिर भी ख़ुश है बिपाशा

बिपाशा बासु उन अभिनेत्रियों में से है जिन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में सफ़लता के झंडे गाड़ने के बाद बॉलीवुड में भी धमाकेदार एंट्री से सबको चकित कर दिया था. बिपाशा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत अब्बास मस्तान की फिल्म अजनबी से की थी. बॉलीवुड की हॉट अभिनेत्रियों में से एक बिपाशा ने अब तक कई फिल्मों में गर्मा-गर्म सींस दिए हैं. मगर इस बार बिपाशा ने बोल्डनेस की सारी हदें पार की दी हैं. बिपाशा एक ऐड में टॉपलेस नज़र आईं. 90 के दशक में पूजा भट्ट ने एक फैशन मैगज़ीन के कवर के लिए बॉडी क्या एक्सपोज किया. तब से बॉलीवुड में यह फैशन ट्रेंड बन गया. इसके बाद एक के बाद एक बॉलीवुड हसीना किसी न किसी मैगज़ीन के लिए बोल्ड फोटो सूट करवा रहीं हैं. बिपाशा के इस फोटो पर किसी ने ऐतराज जताया है. शिक़ायतकर्ता सुधीर कुमार ओझा ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अभिनेत्री पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया है. इस पर मुज़फ्फरपुर सीजेएम की अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री बिपाशा बसु के ख़िलाफ़ एक फैशन पत्रिका में नग्न तस्वीरें प्रकाशित करने पर मामला दर्ज़ किया है. हालांकि इससे उन्हें कितना फ़र्क़ पड़ता है यह तो देखा जाएगा, बहरहाल बिपाशा के इस सेक्सी फिगर के फैंस काफ़ी हैं, जिन्हें उनके इस रूप से कोई नाराज़गी नहीं है. बिपाशा अपने दिन की शुरुआत पाकिस्तानी गायक आतिफ के संगीत से करती हैं और जब शूट के लिए जाती हैं तो कार में भी इसी गाने को सुनती हैं. यह तो हुआ शौक, पर बिपाशा को डर किस चीज से लगता है. दरअसल बिपाशा ऊंचाई से बहुत डरती है. एक और बात उनकी ज़िंदगी से जुड़ी है कि वह डॉक्टर बनना चाहती थीं लेकिन 17 वर्ष की उम्र में गोदरेज सिंथाल प्रतियोगिता जीतने के बाद उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में क़दम बढ़ा दिए थे. बिपाशा सोशल वर्क में भी रुचि रखती हैं, उन्होंने चैरिटी के लिए सेक्स वर्करों के साथ भी डांस किया है.

फ़िलहाल, उनके लिए सबसे बड़ी ख़ुशख़बरी लेकर आया है एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट. इस फिल्म में बिपाशा एक मराठा वॉरियर के किरदार में जांबाज स्टंट करती नज़र आएंगी. उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि इस हॉलीवुड प्रोजेक्ट से उनके लिए नए रास्ते खुल जाएंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ये साली ज़िंदगी

निर्माता निर्देशक प्रकाश झा द्वारा निर्देशित फ़िल्म राजनीति ने टिकट खिड़की पर तो कमाल किया ही साथ ही फ़िल्म समीक्षकों की प्रशंसा भी बटोरी. अब उनकी अगली फ़िल्म है, ये साली ज़िंदगी. लेकिन वह इससे सिर्फ़ निर्माता के तौर पर ही जुड़े हैं. फ़िल्म के निर्देशन की ज़िम्मेदारी संभाली है सुधीर मिश्रा ने. फ़िल्म की पहली झलक पेश करते हुए प्रकाश कहते हैं कि उनके अनुसार ये एक शानदार फ़िल्म है. और इस फिल्म के ज़रिए उन्होंने दर्शकों को बेहतरीन कहानी और मनोरंजन देने की कोशिश की है.

प्रकाश के मुताबिक़ फ़िल्म का कथानक बहुत दिलचस्प है. उन्हें यक़ीन है कि ये फ़िल्म दर्शकों को ज़रूर पसंद आएगी. फ़िल्म की कहानी एक रोमांटिक थ्रिलर पर आधारित है. फ़िल्म में इरफ़ान ख़ान और चित्रांगदा सिंह मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. पहले फ़िल्म का शीर्षक दिल दर बदर रखा गया था, लेकिन जब गीतकार स्वानंद किरकिरे ने फ़िल्म के लिए ये साली ज़िंदगी लिरिक्स का गाना लिखा तब निर्देशक सुधीर मिश्रा ने फ़िल्म के लिए भी इसी शीर्षक का चुनाव कर लिया. फ़िल्म के मुख्य अभिनेता इरफ़ान ख़ान को अपनी इस फ़िल्म से ऐसी उम्मीद है कि उन्हें लगता है कि इस बार वह ख़ुद को प्रूफ साबित करते हुए अपने प्रशंसकों को अपने काम से चकित कर देंगे. चित्रांगदा सिंह ने कुछ ही फ़िल्मों में काम किया है, लेकिन वे अपने करियर से ख़ुश हैं. लेकिन वे ये साली ज़िंदगी को लेकर ख़ासी एक्साइटेड हैं. इसमें चित्रांगदा एक ऐसी लड़की का रोल प्ले कर रही हैं, जो एक लड़के से बहुत प्यार करती है. हालांकि वह यह जानने की ज़रूरत नहीं समझती कि वह लड़का उसे प्यार करता भी है या नहीं. युवाओं के लिए खास मैसेज लिए यह फ़िल्म लड़की के प्रेम की अलग ही पराकाष्ठा पेश करती है. चित्रांगदा का अगला प्रोजेक्ट फ़िल्म देसी बॉयज़ भी जल्द ही आने वाला है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
बिहार झारखंड

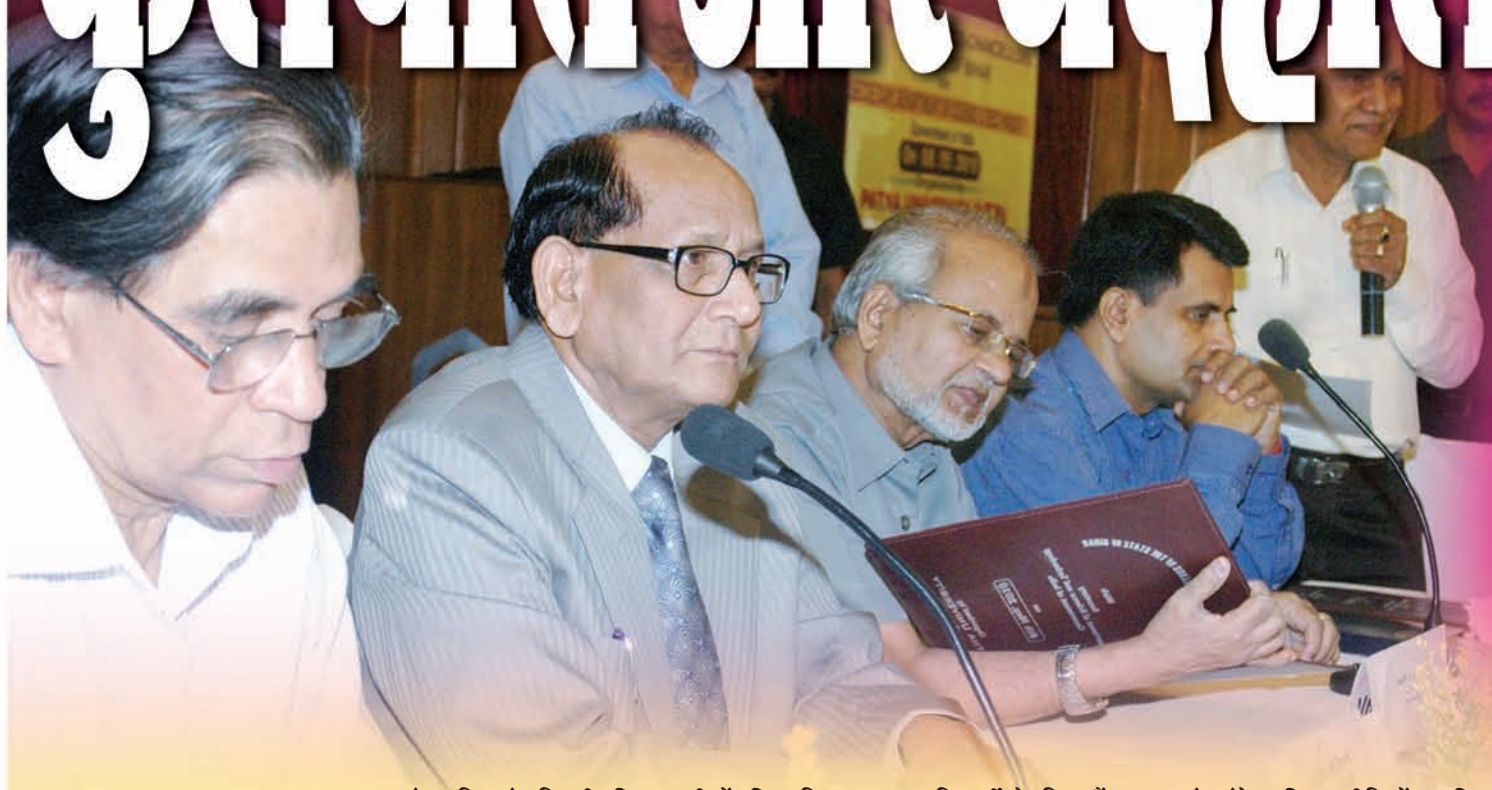

दिल्ली, 31 जनवरी-06 फरवरी 2011 www.chauthiduniya.com

कुलपति और बदहाल उच्च शिक्षा

"बिहार में कुलपतियों की नियुक्तियां संदेह के घेरे में रही हैं. विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में सुधार के लिए कुलपतियों की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता आवश्यक है."

शिवानंद तिवारी, सांसद, जदयू

फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

सरोज सिंह

जदयू सांसद शिवानंद तिवारी की हाल ही में की गई टिप्पणी, जिसमें वह कहते हैं कि बिहार में कुलपतियों की नियुक्तियां संदेह के घेरे में रही हैं. इसलिए विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल को सुधारने के लिए कुलपतियों की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता आवश्यक है, बताती है कि उच्च शिक्षा की वर्तमान हालत क्या है. उधर, मानव संसाधन विकास मंत्री पीके शाही के जनता दरबार में एक कॉलेज शिक्षक मौलाना मज़हरूल हक़ अरबी फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए जाने के आवेदन के साथ पहुंच गए. इरादा था कि मंत्री उनके नाम की सिफ़ारिश कर दें. मंत्री महोदय सार्वजनिक तौर पर ऐसे व्यवहार पर भड़क उठे.

सत्ताधारी ज़मात के शूरमाओं के ये चंद अल्फाज़ और सत्ता के गलियारों के उपरोक्त दृश्य बिहार में कुलपतियों के चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह पैदा करते हैं. बिहार के नौ विश्वविद्यालयों में से पांच में नए कुलपति नियुक्त किए जाने हैं. इस परिस्थिति में संदेह और भी गहरा जाता है. पटना विश्वविद्यालय, बीआर अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा एवं मौलाना मज़हरूल हक़ अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय में कुलपति के पदों पर नई नियुक्ति होने वाली है. कुलपति का चयन राज्य के कुलाधिपति अर्थात राज्यपाल करते हैं. हालांकि, राज्य सरकार के द्वारा कुलपति पद के योग्य उम्मीदवारों का पैनल उनके पास भेजा जाता है. कुलाधिपति अपने स्वविवेक से इस पर निर्णय करते हैं. लिहाज़ा, इन शैक्षणिक संस्थाओं या यूं कहें तथाकथित तौर पर स्वायतशासी निकाय करार दिये जाने वाले इन विश्वविद्यालयों के कुलपति के पद को भी राजनीतिक नियुक्ति के दायरे में मान लिए जाने के बाद से ही इसका अवमूल्यन शुरू हो गया. चयन का कोई निर्धारित मापदंड न होने एवं नियुक्ति प्रक्रिया व्यक्ति विशेष के विवेक पर निर्भर होने के कारण इसमें स्वेच्छाचारिता को बढ़ावा मिला. दिलचस्प है कि इससे पहले बने कुलपतियों के नामों पर ग़ौर करने पर उसमें भी भाई-भतीजावाद एवं भ्रष्टाचार की गहराई का अहसास होता है.

पिछली बार नियुक्त अधिकांश कुलपतियों में यह योग्यता थी. जदयू के विधान पार्षद व पूर्व मंत्री देवेश चंद्र ठाकुर की बहन प्रेमा झा तिलकामांझी विश्वविद्यालय भागलपुर की वीसी थीं. वहीं बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के कुलपति आरपी श्रीवास्तव राज्य सरकार की आंख के तारे आईएएस अधिकारी प्रत्यय अमृत के पिता हैं. जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के कुलपति डॉ. आरपी शर्मा भाजपा नेत्री एंव पालीगंज की नवनिर्वाचित विधायक ऊषा विधार्थी के पिता हैं. वह स्वयं कांग्रेस की राजनीति में काफ़ी रसूख रखते हैं. कुलपति पद पर रहने के दौरान उन पर वित्तीय अनिमितता एवं नियुक्तियों में हेराफेरी के आरोप उछलते रहे हैं. वहीं ललित नारायण मिश्रा मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की प्रतिकुलपति पदमाशा झा कांग्रेस की विधान पार्षद रह चुकी हैं. वह वहां प्रभारी कुलपति भी रहीं. कुलपति की नियुक्तियों को लेकर अटकलों का बाज़ार गर्म है. इन पदों के लिए कई नाम काफ़ी चर्चा में हैं. पटना विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति वाई एस अहसन, इसके अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व अध्यक्ष नवलकिशोर चौधरी, खुदाबख्श लाइब्रेरी के प्रमुख इम्तेयाज अहमद, कांग्रेसी नेता एवं शिक्षाविद् डॉ. अनिल सुलभ आदि कई नाम इसमें शुमार हैं. लेकिन बिहार में उच्च शिक्षा की निरंतर गिरती सेहत पर विचार तो दूर सही मायने में इस की ओर नज़र डालना भी बिहार के सियासी भाग्यविधाताओं को गंवारा नहीं है. शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मियों की हड़ताल, कुलपति बनाम प्रशासनिक अधिकारियों की भिड़ंत, शिक्षकों का वरीयता विवाद, विभिन्न शैक्षणिक संगठनों के आपसी स्वार्थ के टकराव तथा विधार्थियों के बेवजह के झमेलों के कारण ही बिहार के विश्वविधालय सुर्खियों में रहते हैं. डिग्रियों के फ़र्ज़ीवाड़े, अवैध नियुक्ति-प्रोन्नति, घपले-घोटाले आदि ग़ैरक़ानूनी गोरखधंधे यहां गहरी पैठ बना चुके हैं. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने तो संबद्धता प्राप्त दर्जन से अधिक कालेजों को इस गोरखधंधे की गंगोत्री के रूप में चिन्हित किया था. बिहार के कुछ राजनीतिज्ञ एवं शिक्षा माफियाओं ने अपने नाम पर कालेज स्थापित कर अपना कारोबार फैला रखा है. राजद के बाहुबली विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव ने सुरेंद्र यादव कालेज, महेश सिंह यादव ने महेश सिंह यादव महाविद्यालय, गया के ही लालू यादव ने तत्कालीन कुलपति का नाम जोड़कर अपने नाम से डेल्हा गया में लालू मंडल कॉलेज, अंग्रेजी के प्राध्यापक कामता प्रसाद सिंह ने भी अपने नाम पर कॉलेज स्थापित कर रखा है. इससे पूर्व आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता की पत्नी शिखा गुप्ता का सर्वोच्च श्रेणी से स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल करने का मामला काफ़ी सुर्खियों में रहा था. तभी डिग्री घोटाला प्रकाश में आया था. तुर्रा यह कि शिखा गुप्ता गया के एएम कॉलेज के लॉ विभाग में व्याख्याता भी नियुक्त हो गईं थी. उसी समय व्याख्याता नियुक्ति घोटाला उजागर हुआ था. तब उसकी आंच तत्कालीन विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी के दामन तक पहुंच गई थी. यही वजह थी कि विभिन्न मुद्दों पर बिहार विधानसभा में गरजने वाले सुशील कुमार मोदी को सांप सूंघ गया था. आज तक वह मामला ठंडे बस्ते में ही पड़ा हुआ है. उस वक़्त सत्ताधारी जमात के चूड़ी गली के बादशाह पर भी उंगली उठी थी. फ़िलवक़्त वह सुशासन के पैरोकार बने हुए हैं. विपक्ष एवं सत्ता पक्ष की मिलीभगत से हुए उक्त घोटाले से स्पष्ट हो गया था कि बिहार में उच्चशिक्षा भगवान भरोसे ही चल रही है.

बिहार में उच्च शिक्षा भगवान भरोसे चल रही है. कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर उठते संदेह और इससे फैली बदनामी के कारण बिहार से डिग्री हासिल कर देश के अन्य राज्यों में रोज़गार की तलाश में जाने वाले युवाओं को भी ज़लालत झेलनी पड़ती है. उनकी डिग्रियों को अमान्य तक करार दे दिया जाता है.

इन बदनामियों के कारण बिहार से डिग्री हासिल कर देश के अन्य राज्यों में रोज़गार की तलाश में जाने वाले युवाओं को ज़लालत झेलनी पड़ती है. लिहाज़ा उनकी डिग्रियों को अमान्य तक करार दे दिया जाता है. एक वर्ग की राय तो कुछ अधिक ही तल्ख है. इनके अनुसार बिहार के कतिपय विश्वविधालयों में पठन-पाठन के अलावा सब कुछ होता है. यहां जुगाड़ टेक्नोलॉजी के बूते विवादित चेहरे भी इन अकादमिक संस्थानों के कुलपति पद पर क़ाबिज हो जाते हैं तभी तो नौकरशाह केके पाठक एवं पूर्व कुलाधिपति आर एस गवई के विशेष कार्य पदाधिकारी डॉ. आर कृष्ण कुमार के समक्ष ऐसे कुलपतियों की घिग्घी बंध जाती थी. कुलपतियों की मनोदशा के दो उदाहरण देखिए. पटना विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी येडला सी सिमाद्री पदभार संभालने से पहले कुर्सी पर कथित तौर गंगाजल छिड़कवाया था, क्योंकि उनसे पहले मुस्लिम समुदाय के कुलपति उस कुर्सी पर बैठते थे. बीएन मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. आरपी श्रीवास्तव शैक्षणिक माहौल सुधारने के बजाए विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के लिए वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पत्नी कविता वर्मा के साथ तन्मयता से भूमिपूजन में तल्लीन रहे. पहले कुलपतियों के चेहरे से शिक्षा, सच्चाई और कर्तव्यपरायणता का नूर झलकता रहता था. लेकिन अब यह इतिहास हो गया. शिवानंद तिवारी के पत्र का लब्बोलुआब यह था कि कुलपतियों की नियुक्ति में पहले की ग़लतियों को न दोहराया जाए और एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि पाक़ साफ़ चेहरे ही उस कुर्सी पर बैठ सकें. उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार कुलपतियों की नियुक्ति में उनकी योग्यता को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि शिक्षा के मंदिर को मंडी बनने से बचाया जा सके.

feedback@chauthiduniya.com

मोतिहारी में लगातार हो रही मोरों की मौत देश के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन इन दुर्घटनाओं से प्रशासन कोई भी सबक नहीं ले रहा है.

पहले झारखंड से अजमेर शरीफ़ जाने वाले श्रद्धालु ही शेरशाह के मक़बरे का भ्रमण करते थे, लेकिन अब पश्चिमी देशों के सैलानी भी यहां आ रहे हैं.

एक नज़र इधर भी

सेल का मुनाफ़ा 1107 करोड़

सेल की अनशंगी इकाई आरडीसीआइएस के मानव संसाधन विभाग द्वारा आयोजित सुझाव मेले में सेलकर्मियों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए और अनुभवों को शेयर किया. सेल के कार्यपालक निदेशक प्रभारी आदित्य स्वरूप माथुर सहित महाप्रबंधक, उपमहाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों ने भी सुझाव मेले में खासी रुचि दिखाई और कार्मिकों का उत्साह बढ़ाया. आरडीसीआइएस को सेल का थिंक टैंक माना जाता है. उल्लेखनीय है कि सेल ने चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में 1107 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है.

5 सौ करोड़ के आइपीओ लाएगा अभिजीत ग्रुप

अभिजीत पावर लि. की आगामी वित्तीय वर्ष में 1500 करोड़ के आइपीओ लाने की योजना है. जानकारी के मुताबिक कंपनी ने झारखंड और बिहार में निर्माणाधीन दो परियोजनाओं के लिए खुले बाज़ार से पूंजी जुटाने के उद्देश्य से सार्वजनिक निर्गम जारी करने का निर्णय लिया है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आइपीओ के लिए संबंधित विभागों की स्वीकृति का मामला अंतिम चरण में है. सारी प्रक्रियाएं फरवरी के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है. आइपीओ के ज़रिए करीब 1500 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके पूर्व कंपनी प्राइवेट इक्विटी के जरिए भी लगभग 500 करोड़ रुपये जुटाएगी.

अशरफ अस्थानवी सम्मानित

वरिष्ठ उर्दू पत्रकार और अल्पसंख्यक मामलों के विशेषज्ञ अशरफ अस्थानवी को प्रतिष्ठित गुलाम सरवर पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है. गत 10 जनवरी को बिहार में उर्दू आंदोलन के नायक और वरिष्ठ पत्रकार गुलाम सरवर एवं पूर्व अध्यक्ष बिहार विधान सभा की 85वीं जयंती के अवसर पर पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित भव्य उर्दू दिवस समारोह में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अशरफ अस्थानवी को गुलाम सरवर पत्राकारिता मोमेन्टा, नगद राशि तथा अंग वस्त्रा देकर सम्मानित किया. गुलाम सरवर मेमोरियल सोसायटी बिहार के संयोजक तथा बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता गुलाम गौस ने इस अवार्ड के लिए अशरफ अस्थानवी के नाम की घोषणा करते हुए कहा कि पत्रकारिता जगत में अशरफ अस्थानवी का योगदान सर्वविदित है. वह दो दशकों से पूरी निर्भीकता के साथ उर्दू तथा राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के पक्ष में आवाज़ उठाते आ रहे हैं. *–चौथी दुनिया ब्यूरो*

इडेन एक्सप्रेस मील का पत्थर

वर्षों से मृतप्राय हो चुकी राज्य पथ परिवहन निगम की सेवा में इडेन एक्सप्रेस के माध्यम से संचालित आधुनिक सुविधाओं से लैस बसों का बिहार की सड़कों पर दौड़ना आम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है. छपरा बस डिपो में इडेन एक्सप्रेस द्वारा शुरू की गई नई बस सेवा का शुभारंभ करते हुए पथ परिवहन एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री वृषिण पटेल ने ऐसी संभावना भी व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड के साथ यह सेवा बहाल करने के लिए प्रयत्नशील है तथा जल्द ही ज़िले के हर प्रखंड से भी राज्य पथ परिवहन निगम की बसें संचालित करने की योजना है. पटेल ने इडेन एक्सप्रेस के एमडी डॉ. सच्चिदानन्द राय को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके प्रयास से ही छपरा को नववर्ष का तोहफा मिला है. अब लोगों को काफी राहत मिलेगी. *–विजयेंद्र कुमार*

जाम से परेशान छपरा शहर

सारण ज़िला मुख्यालय होने के कारण प्रतिदिन लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है. इसका कारण सड़क के किनारे बने मकान और दुकान से सड़क की चौड़ाई का कम पड़ जाना है. सरकार ने छपरा शहर को सौंदर्यीकरण करने के उद्देश्य से सड़क का चौड़ीकरण करने का आदेश पथ निर्माण विभाग को दिया है, लेकिन पथ निर्माण विभाग को इसकी कोई फिक्र नहीं है. ज़िला पदाधिकारी के कार्यालय के सामने छोटे-मोटे दुकानदार सड़क के किनारे अपनी दुकान सजा लेते हैं. शहर में सुबह से ही लोगों की भीड़ रहती है, जिससे आने-जाने वाले लोगों को काफी असुविधा होती है. नगरपालिका चौक से लेकर भिखारी चौक के बीच भी होने वाले जाम से लोगों को जूझना पड़ता है. *–मनोज प्रसाद*

बेकार है फुटओवर ब्रिज

सुपौल के रेलवे स्टेशन पर लाखों की लागत से बना फुटओवर ब्रिज विभागीय उदासीनता के कारण औचित्यहीन साबित हो रहा है. ब्रिज के पश्चिमी भाग जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है, वहीं इसके पूर्वी भाग का पायदान क्षतिग्रस्त हो रहा है. जिसके कारण आम लोग व रेल यात्री इस ब्रिज का उपयोग न के बराबर ही करते हैं. विभाग न तो गंदगी को साफ कराना मुनासिब समझ रहा है और न ही पायदान को सही कराना. निर्माण के समय लोग खुश थे कि स्टेशन के इस पार से उस पार जाने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ब्रिज बनने के बाद भी चकला निर्मली से बाज़ार आने के लिए लोगों को रेलवे पटरी से ही गुजरना पड़ रहा है. *–अजय यादव*

क़द कमज़ोरी नहीं है

महनार प्रखंड के लावापुर नारायण गांव निवासी शमीम अख्तर खान के 35 वर्षीय पुत्र वसीम अख्तर खान उर्फ़ राजा बाबू की लंबाई मात्र साढ़े तीन फिट है, किंतु अपने ठिगने कद को उसने कभी अभिशाप नहीं बनने दिया. जबकि इसी के सहारे वह बड़े-बड़े कार्य चुटकी में करवा लेता है. अधिकारी भी उसके कद को सहानुभूति की दृष्टि से देखते हैं. पेशे से गल्ला दुकानदार राजा बाबू के इसी कद के कारण उनकी दुकान ज़्यादा चलती है. राजा बाबू अपने हाव-भाव व बोलचाल से ग्राहक को भी आकर्षित कर लेता *–अंजूम परवेज*

उपेक्षित है भुरहा धाम

गया जिले के गुरुआ प्रखंड के अंतर्गत अति प्राचीन धर्म स्थल भुरहा धाम सरकारी एवं पर्यटन विभाग की उपेक्षा का शिकार है. भगवान बुद्ध तथा हिंदू देवी-देवताओं से जुड़ा यह स्थल प्राचीन काल से ही लोगों की आस्था का केंद्र रहा है . आज भी विभिन्न अवसरों पर यहां धार्मिक मेले का आयोजन होता है. लेकिन प्रशासन को इसकी सुध नहीं है. *– डॉ. प्रमोद कुमार वर्मा*

फिर खिल उठी मुरझाई सिंदरी

सिंदरी एक बार फिर खुश है. वर्षों बाद पीडीआइएल ने देश के कैटलिस्ट बाज़ार पर क़ब्ज़ा जमाया है. अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता एवं कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद कंपनी को 11.5 करोड़ की कैटलिस्ट आपूर्ति का आदेश मिला है. इससे कंपनी सहित पूरा शहर भी उत्साहित है. इससे संस्थान की आर्थिक स्थिति में सुधार की आस जगी है. 2003 के बाद कंपनी को कैटलिस्ट आपूर्ति का भारी भरकम आदेश प्राप्त हुआ है. प्रबंधन प्लांटों को उत्पादन के लिए तैयार कर रहा है. कच्चे माल की व्यवस्था की जा रही है. *–राजीव रंजन*

बेगूसराय नगर निगम चुनाव

असल दावेदार महिलाएं हैं

सुनीता सोनी

राजेश सिन्हा

बेगूसराय ज़िले में पहली बार हो रहे नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी अपने अपने चुनावी मोहरे सजाने लगे हैं. कई दिग्गज प्रत्याशी लक्ष्मीनारायण के बल पर जीत का दावा ठोंक रहे हैं तो कई अपने सौम्य व्यवहार और कुशल नेतृत्व की बात कहकर जीत का दावा कर रहे हैं. सभी वॉर्ड में जीत किसकी होगी और किसकी हार, यह कहना तो शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि इस बार कई नए चेहरे वॉर्ड पार्षद की कुर्सी पर विराजमान होंगे और कई दिग्गजों को हार का ग़म सालेगा. कई वार्ड पार्षदों ने इस बार चुनाव लड़ने से ही तौबा कर लिया है तो कई नए चेहरों ने चुनाव लड़ने का मन बनाया है. इस बार नगर परिषद की तत्कालीन मुख्य पार्शद पुष्पा शर्मा, उपमुख्य पार्षद जवाहर भारद्वाज, वॉर्ड पार्षद चंद्रभूषण दास, अभय कुमार शर्मा सहित कई दिग्गज चुनावी अखाड़े में नहीं कूदे जबकि कई पंचायतों के नगर निगम में शामिल किए जाने के कारण कई मुखिया और उनकर पत्नियां नगर निगम चुनाव में ताल ठोंक रही हैं. वैसे तो सभी 45 वॉर्डों में दिलचस्प मुक़ाबला होने की संभावना दिख रही है, लेकिन सबसे दिलचस्प मुक़ाबला वॉर्ड नंबर 32 में होने की संभावना बताई जा रही है. इस वॉर्ड से पहली बार चुनावी अखाड़े में कूदने वाली सुनीता सोनी अन्य प्रत्याशियों के मुक़ाबले काफ़ी सबल दिख रही हैं. बिनोद कुमार सोनी की कार्यकुलता और सौम्य व्यवहार के कारण इस वॉर्ड के मतदाताओं के बीच उनकी पत्नी सुनीता की छवि काफ़ी अच्छी है. इस वॉर्ड के उमेश मिश्र और रंजीत झा की अगर मानें तो इस बार सुनीता सोनी का जीतना तय है, क्योंकि उनके पति स्वर्ण व्यवसायी बिनोद कुमार सोनी ने ग़रीब तबके के लोगों के हक–हकूक के लिए जी–जान से लड़ाई लड़ी. तत्कालीन वॉर्ड पार्षद ने इस वार्ड के लिए कुछ भी नहीं किया. न ही साफ–सफाई की व्यवस्था कराई और न ही गरीबों के लिए कुछ किया. बाल गोविंद अग्रवाल, अरुण अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, शिवराम महतो सहित अन्य का कहना था कि सुनीता को न केवल लोग वॉर्ड पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं, बल्कि मेयर के पद पर विराजमान भी इसलिए देखना चाहते हैं, क्योंकि किसी पद पर नहीं रहने के बाद भी इनका ग़रीबों के प्रति प्रेम जगज़ाहिर है. इंद्रदेव पासवान, महेंद्र भगत, अरविंद पटेल सहित अन्य का कहना था कि अगर सुनीता वॉर्ड पार्शद बनने के बाद मेयर बन जाती हैं तो बेगूसराय का कायापलट हो जाएगा. सुनीता या उनके पति चुनावी अखाड़े में कूदना नहीं चाहते थे, लेकिन जनता की मांग पर सुनीता चुनावी अखाड़े में कूदी हैं. इधर नगर निगम के चुनाव से संदर्भित सवालों का जवाब देते हुए वॉर्ड नंबर 32 की प्रत्याशी सुनीता सोनी के मुताबिक़ वह जनता जनार्दन की सेवा करने के ख्याल से ही वह चुनावी अखाड़े में कूदी हैं. अगर वह जनता मालिक की कृपा से जीत हासिल करती हैं तो आने वाले समय में बेगूसराय की तस्वीर बदल देंगी. वैसे इस वॉर्ड से सारिका भाष्कर, शिवरानी अग्रवाल, राजकुमारी देवी सहित अन्य दिग्गज भी चुनावी अखाड़े में हैं. सुनीता के द्वारा नामांकन के दिन चलाए गए जनसंपर्क अभियान के दौरान जनता के द्वारा मिला समर्थन भी इस बात को स्पष्ट कर गया कि जनता उनके पक्ष में गोलबंद है. दस जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद से अंतिम तिथि अर्थात 17 जनवरी तक सभी 45 वॉर्डों के लिए कुल 480 उम्मीदवारों ने नामांकन किया. वॉर्ड नंबर–1 से प्रदीप कुमार, वॉर्ड नंबर–2 से रेखा चंद्रा, धनिकलाल दास, अनिता सिन्हा, राजीव कुमार, कुंदन कुमार सिंटू सिंह, वॉर्ड नंबर–3 से गुलशन खातून, वॉर्ड नंबर–7 से मो. शोएब, वॉर्ड नंबर 31 से देवानंद पासवान, वॉर्ड नंबर 23 से आशा कुमारी, वॉर्ड नंबर 21 से कमला देवी, वॉर्ड नंबर 36 से रेणु कुमारी, वॉर्ड नम्बर 38 से राजेश सिन्हा, वार्ड नंबर 17 से सीमा देवी, वार्ड नंबर 11 से यदुनंदन प्रसाद, वॉर्ड नंबर 25 से रवि रौशन, वॉर्ड नंबर 38 से ब्रजमोहन प्रसाद, वॉर्ड नंबर 44 से सुनीता सिन्हा, वॉर्ड नंबर 24 से संध्या देवी, वॉर्ड नंबर 24 से रामानंद पासवान, वॉर्ड नंबर 20 से वीणा देवी, वॉर्ड नंबर 42 से राजकिशोर प्रसाद, वॉर्ड नंबर 42 से त्रिपुरारी पंडित, वॉर्ड नंबर 24 से राजीव पंडित, वॉर्ड नंबर 6 से सुरेंद्र कुमार, वॉर्ड नंबर 38 से सुबोध झा, वॉर्ड नंबर 20 से वीणा देवी, वॉर्ड नंबर 22 से नीलम प्रकाश, वॉर्ड नंबर 10 से संगीता देवी, वॉर्ड नंबर 24 से जितेंद्र कुमार जीबू, वॉर्ड नंबर 23 से शीला देवी, वॉर्ड नंबर 12 से सोनू सिद्धार्थ, वॉर्ड नंबर 42 से गौतम राम, वॉर्ड नंबर 21 से रितेश कुमार, वॉर्ड नंबर 40 से कमला देवी, वॉर्ड नंबर 13 से वीणा देवी, वॉर्ड नंबर 35 से भाजपा जिला प्रवक्ता नीरज कुमार, वॉर्ड नंबर 23 से सुनैना देवी, वॉर्ड नंबर 36 से दासो पासवान, वॉर्ड नंबर 18 से रामभूशण सिंह, वॉर्ड नंबर 42 से रेणु देवी, वॉर्ड नंबर 45 से बबीता सिंह, वॉर्ड नंबर 33 से पवन कुमार, वॉर्ड नंबर 13 से अफसाना नाज, 30 से गोरख महतो, 7 से विद्यान प्रियरंजन, 26 से विजय सिंह, 7 से शमीम अहमद, 34 से जामुन महतो, 36 से अरविन्द चंद्र वर्मा, 27 से सुरेश सौरभ, 6 से प्रतिभा देवी, श्यामसुंदर गुप्ता, 27 से हरिकिशोर प्रसाद सिन्हा, 33 से राकेश चौधरी, 14 से रंजू कुमारी, 9 से गणेश राम, 11 से राजकुमार महतो सहित कुल 480 प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन किया गया है.

अर्चना कुमारी | सारिका भास्कर | वीना सिंह | नीरज कुमार | एमडी मुख्तार | बबन सिंह | रितेश कुमार | गौतम राम

बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक बाद होने वाले लोकतंत्र की सबसे ज़मीनी जंग में महिलाओं की बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण मिलने के बाद से महिलाएं पुरुषों को पीछे छोड़ने के लिए अमादा हैं. हालांकि, यह सब 13 फरवरी के बाद स्पष्ट हो जाएगा. लेकिन इतना तय है कि नगर परिषद चुनाव के बनिस्पत पहली बार हो रहे नगर निगम चुनाव के नतीजे बेहद चौंकाने वाले होंगे.

feedback@chauthiduniya.com

आ रहे हैं विदेशी सैलानी

सासाराम का मक़बरा

वर्ष 2011 की शुरुआत होते ही जर्मनी एवं स्विटजरलैंड के सैलानियों का दल सासाराम पहुंच गया है. सभी पर्यटक इस ऐतिहासिक धरोहर की ख़ूबसूरती और कारीगरी से बहुत प्रभावित हुए. 42 सदस्यीय वाले विदेशी सैलानियों का यह दल जब मक़बरे के समीप पहुंचा तो बोल उठा कि हम बार-बार यहां आएंगे.

साढ़े चार सौ वर्षों से ज़्यादा का इतिहास संजोए सासाराम की धरती पर खड़ा शेरशाह सूरी का मक़बरा अब सात समंदर पार बैठे सैलानियों को भी लुभाने लगा है. तभी तो वर्ष 2011 की शुरुआत होते ही जर्मनी एवं स्विटजरलैंड के सैलानियों का दल आ पहुंचा, जिसने विश्व के ऐतिहासिक धरोहरों में नामित इस पुरातात्विक खंड की चर्चा देखी व सुनी थी. 42 सदस्यों वाले विदेशी सैलानियों का यह दल जब मक़बरे के समीप पहुंचा तो वहां की व्यवस्था पर थोड़ी झिझक ज़रूर दिखाई, लेकिन अंदर पहुंचते ही सारी झिझक दूर हो गई और वहां की कला के नमूने को देखकर उनकी आंखे विस्मृत रह गईं. पर्यटकों के दल में सबसे उम्रदराज जूलिया अल्वा ने टूटी–फूटी हिंदी में बात करते हुए बताया कि यह टो फैंटास्टिक हैं, आई नेवर सीन दैट टाइप ऑफ टॉम्ब. उनके पति अलवर्ट अल्वा के विचार भी कुछ ऐसे ही हैं. हालत यह थी कि 42 सदस्यीय इस दल में से सबसे ज़्यादा युवा फोटोग्राफ लेने में जुटे हुए थे तो कुछ सबसे निचले हिस्से तालाब में जाकर मछलियों को लुभाने व देखने में जुटे हुए थे. इससे पहले वर्ष में इक्का–दुक्का सात समंदर पार के सैलानी कभी–कभार यहां देखने को मिल जाते थे, परंतु अब तो हर दो दिन पर इनके वाहन सासाराम आ पहुंचते हैं. पूर्व में तिब्बत, थाईलैंड, चीन, हांगकांग एवं जापान सहित अन्य वैसे देश के पर्यटक ज़रूर सासाराम पहुंच जाते थे जो बौद्ध धर्म में आस्था रखने के कारण सारनाथ से बौद्ध गया की यात्रा पर होते थे. जी.टी. रोड से जाने के क्रम में सासाराम का यह मकबरा उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता था और वे इसकी एक झलक पाकर आगे बढ़ते थे. इसके अलावा बंगाल एवं उड़ीसा समेत झारखंड से अजमेर शरीफ जाने वाले श्रद्धालु शेरशाह मकबरा का भ्रमण ज़रूर करते थे, लेकिन अब जिस तरह से पश्चिमी देशों से सैलानी सासाराम के शेरशाह मकबरे की ओर आकर्षित हुए हैं, इसे देख यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि यहां के पर्यटन उद्योग के दिन बहुरने वाले हैं. 1540–45 के बीच दिल्ली की सल्तनत पर क़ब्ज़ा जमाने वाले सासाराम के सपूत शेरशाह द्वारा महज़ पांच वर्ष की अवधि में लगभग 52 एकड़ के भूखंड पर जिस तरह से इस मकबरे का निर्माण किया गया है. इसके अंदर जाने पर पता चल जाता है कि उस समय के कारीगरों का अभियांत्रिक दृष्टिकोण कैसा था. जिस तरह से बड़े–बड़े पत्थरों को तरासकर ऊंचाई पर सजाया गया है, इसको लेकर तरह–तरह के विचार व उपाय मन में हिलोरे लेते हैं. मकबरे के चारों तरफ फैले तालाब की हालत आज चाहे जैसी भी हो, लेकिन इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी यहां के स्वच्छ जल एवं उसमें उठने वाली तरंगे सुबह की लालिमा लिए किरणों एवं शाम की गोधूली बेला में चंचल मन के साथ पहुंचे लोगों को किस तरह सुकून देती होंगी. बाद के दिनों में मकबरा परिसर में बना शिव मंदिर सासाराम के सांप्रदायिक सौहार्द का अनूठा नमूना बन चुका है. मकबरे के गोलाकार गुंबद आज भी देश के गिने चुने बड़े एवं ऊंचे गुंबदों में से एक हैं. कई न्यायिक एवं वैधानिक अड़चनों को झेल रहे शेरशाह की इस अनूठी कृति की तरफ स्वत: ही सात समंदर पार के सैलानी आकर्षित हुए हैं. बस ज़रूरत है यहां आने पर्यटकों को लुभाने एवं संतुष्ट करने वाली व्यवस्था देने की. अगर ऐसा हुआ तो समझो सासाराम के पर्यटन के दिन बहुरने वाले हैं. इसलिए कि यहां से थोड़ी ही दूरी पर गुप्ताधाम, शेरगढ़, रोहतासगढ़, तुतला भवानी, भलूनी भवानी जैसे बिहंगम दृश्य वाले धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, जो भविष्य में सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं. यही नहीं, सासाराम में मौजूद शक्ति पीठ ताराचंडी धाम, कैमूर पहाड़ की छाती पर अल्हड़ बाला की तरह सरपट दौड़ रही कांव नदी द्वारा मांझर कुंड में बनाया गया जलप्रपात, शेरशाह के सपूत सलीम शाह का आधा अधूरा मकबरा एवं हसन साह का मकबरा सहित कई दर्शनीय स्थल भी यहां मौजूद हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

पूर्वी चंपारण

अब महफ़ूज़ नहीं हैं मोर

मनोज कुमार राव

ज़िला मुख्यालय से 40 किमी दूर कल्याणपुर प्रखंड के मनी छपरा पंचायत का माधोपुर गोविंद गांव. क़रीब पांच दशक पहले यहां के किसान स्वर्गीय चंद्रिका सिंह सोनपुर मेले से मोर के दो जोड़े ख़रीदकर लाए थे. तब से आज तक इस गांव में लगभग 500 मोरों की बोली गूंज रही है. इस क्षेत्र में कोई जंगल तो नहीं है, लेकिन मोरों के लिए यहां का वातावरण इतना अनुकूल है कि महज़ 50 साल में यहां मोरों की संख्या 500 का आंकड़ा पार कर चुकी है. दिन भर इधर–उधर खेतों में भटकने के बाद माकूल जगह न मिलने पर ये मोर रात्रि विश्राम के लिए यहां के बोधी पेड़ के पास जमा हो जाते हैं, जिससे यहां का नज़ारा अति मनोरम हो जाता है. लेकिन दुख की बात यह है कि इतनी संख्या में राष्ट्रीय पक्षी के होने के बावजूद भी इनके रख रखाव के लिए अभी तक सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है और शायद वह दिन दूर नहीं, जब इस क्षेत्र में भी मोरों की आवाज़ाही के लिए लोगों को तरसना पड़ेगा. यहां के स्थानीय लोग इन मोरों को वरदान मानते हैं, क्योंकि ज्यों–ज्यों इस क्षेत्र में इनकी आबादी बढ़ रही है, उसी अनुपात में यहां के किसानों की पैदावार भी बढ़ रही है. दुख की बात तो यह है कि बिना सरकारी देखरेख के इन पर दुख के बादल मंडराने लगे हैं. इसका ताज़ा उदाहरण है जनवरी माह में महज़ तीन दिनों के अंदर पांच मोरों की मौत. यहां के मुखिया गुड्डू सिंह ने पांच मोरों की मौत की पुष्टि की और इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को भी दी गई, लेकिन सरकार इस हादसे को किस रूप में ले रही है यह अब तक सार्वजनिक नहीं हो पाया है. हालांकि, अधिकारियों ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. कल्याणपुर के पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. आर एन सिन्हा ने इन मरे मोरों का पोस्टमार्टम गांव में ही किया और उनका सैम्पल लेकर जांच के लिए मोतिहारी भेज दिया. इधर मोरों की मौत की ख़बर पाकर मौक़े पर पहुंचे वनपाल विजय कुमार शर्मा ने भी अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है. उनके अनुसार गांव की स्थिति से संबंधित एक प्रतिवेदन तैयार कर पूरी जानकारी वनों के क्षेत्र पदाधिकारी एस अहमद को भेज दी जाएगी. यहां के ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले इस क्षेत्र में दो संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया था और संभव है कि तस्करी के लिए इनलोगों के द्वारा ही मोरों को अधिक मात्रा में बेहोशी की दवा दे दी गई होगी, जिससे इन पांच मोरों की मौत हो गई. लेकिन इसके बारे में किसी के पास कोई साक्ष्य नहीं है, साथ ही कोई भी ग्रामीण मुंह खोलने को तैयार नहीं है. कम से कम लगभग 6 फीट लंबे व 8 फीट चौड़ाई वाली जगह पर सही तरीके से रहने वाले ये राष्ट्रीय पक्षी रात होते ही यहां के बोधी पेड के नीचे किसी तरह से अपना जीवन यापन करके एक–एक कर मरने को विवश हो रहे हैं. तीन से पांच अंडे देने वाले व लगभग झुंड में रहने वाले ये मोर जगह के अभाव में इधर–उधर भटक रहे हैं और मरने को विवश हैं. लगभग 40 से 50 साल तक जिंदा रहने वाले मोर कम से कम बिहार प्रांत के इस क्षेत्र मे अपनी आबादी तो बढ़ा चुके हैं, लेकिन सरकारी देख–रेख के अभाव में ये मरने को विवश हैं. ऐसे में राष्ट्रीय पक्षियों की इस दुदर्शा को सरकार कितनी गंभीरता से लेती है, यह तो आनेवाला वक़्त ही बताएगा. प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर ने इस मसले को गंभीरता से लेते हुए ज़िला प्रशासन से मांग की है कि शीघ्र ही इन ख़ूबसूरत पक्षियों की देख रेख के मुतल्लिक माकूल उपाय किए जाएं. उधर मधुबन विधायक शिवजी राय से जब बातचीत की गई तो उन्होंने मामले को गंभीर बताया व शीघ्र ही सरकारी स्तर पर उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया. ज़िलाधिकारी नर्मदेश्वर लाल ने भी बताया कि मामला गंभीर है. इस हादसे को लेकर पूरी जांच पड़ताल की जा रही है और दोषी व्यक्तियों को सज़ा ज़रूर मिलेगी. बहरहाल, अधिकारियों ने तो अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है, लेकिन मयूर विहार के नाम से जाने जाना वाला यह माधोपुर गोविंद गांव फ़िलहाल मोरों के लिए असुरक्षित साबित हो रहा है. और महज़ तीन दिन में पांच मोरों की मौत से यहां के ग्रामीण भी ग़मगीन हैं.

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र इधर भी

विश्वविद्यालय में मूर्तियां

शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार एवं प्रशासनिक स्तर पर चुस्ती के लिए मगध विश्वविद्यालय देश भर में चर्चित है. वर्तमान कुलपति डॉ. अरबिंद कुमार के नेतृत्व में मगध विश्वविद्यालय बिहार हीं नहीं देश में अपनी शैक्षणिक व्यवस्था में व्यापक सुधार एवं अन्य विकासात्मक गतिविधियों के कारण चर्चा में है. बौद्धों के महान धर्मगुरु 17वें करमापा का मगध विश्वविद्यालय में जाकर कुलपति से मिलना बौद्ध धर्मावलंवियों का मविवि के प्रति बढ़ती आस्था को दिखाता. एक महत्वपूर्ण बैठक में विश्वविद्यालय परिसर में देश के महापुरुषों की प्रतिमाओं को लगाने का निर्णय लिया गया है.

मेयर को सहयोग नहीं कर रहे हैं अधिकारी

विवादों में रहनेवाला गया नगर निगम का वर्तमान कार्यकाल चार साल का पुरा कर चुका है. नगर के विकास की बजाय इसके वार्ड पार्षद आपस की गुटबाजी में ज्यादा व्यस्त रहे. इसी का नतीजा है कि अधिकारी भी पार्षदों की फूट का फायदा उठाते रहे. यहां तक कि प्रत्येक सोमवार को नगर निगम में मेयर शगुता प्रवीण के द्धारा लगाये जाने वाले जनता दरबार में भी अधिकारी नही आते. इससे महिला मेयर को सहयोग नहीं मिल पा रहा है. *–सुनील सौरभ*

मेंहदार में भागवत ज्ञान महायज्ञ

उत्तर बिहार के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल महेन्द्र नाथ मंदिर के प्रांगण में आगामी 8 मार्च से सात दिवसीय भागवत ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा. कैमूर घाटी स्थित गुप्त धाम के संत श्री जलेश्वर जी महाराज की देखरेख में आयोजित उक्त महायज्ञ 8 मार्च से 16 मार्च तक पूरे विधि–विधान संचालित होगा. महायज्ञ समिति के सह–संयोजक देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बाबा महेन्द्र नाथ धाम के विकास के लिए धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष किशोर कुणाल को सौंदर्यीकरण का प्रारूप सौंप दिया गया है. महायज्ञ की तैयारी हेतु श्री जलेश्वर महाराज ने समिति सदस्यों के साथ क्षेत्र के 101 गांव का भ्रमण कर लोगों से सहयोग प्रदान करने की कामना की है. *–प्रेम प्रकाश शर्मा*

पर्यावरण की ख़ातिर शादी नहीं करेगा गजेंद्र

विश्व के धरातल पर पर्यावरण को स्वच्छ और निर्मल बनाना है तो पेड़ों को संतान मानना होगा, तभी पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है. जीवन में शादी नहीं करूंगा. सिर्फ़ पेड़ लगाउंगा. प्रकृति कि संरचना ही परिवार है. प्रकृति ठीक होगी तो उेश भी विकास करेगा. यह कना है एक पर्यावरण प्रेमी का है. पश्चिम चंपारण ज़िला के बगहा अनुमंडल स्थित पीपरा गांव के रहने वाले गजेंद्र यादव ने अपना जीवन पर्यावरण को समर्पित कर दिया है. 28 साल का यह शख्स पैंतीस हज़ार से ज़्यादा पेड़ लगा चुका है.

दो दिन ही खुलता है पथ निर्माण विभाग

महनार स्थित पथ निर्माण विभाग का कार्यालय मात्र 26 जनवरी व 15 अगस्त को ही खुलता है और झंडोतोलन कर पुन: बन्द हो जाता है. यहां के बड़े अधिकारियों व स्थानीय विधायकों को भी मालूम नहीं है कि इसका कार्यालय कहां है. जबकि इस कार्यालय में सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, दोनों कार्यालय के लिपिक, चपरासी व अन्य कर्मी पदस्थापित हैं. सूत्र बताते हैं कि ये लोग हाजीपुर में ही बैठ कर अपना कार्य निष्पादन करते हैं व जरूरी काम पर ही महनार आते हैं. कई कर्मचारी बिना कार्य किए ही वेतन उठा रहे हैं.

किसानों को हक़ मिले: अनिल सुलभ

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉ अनिल सुलभ ने कहा है कि नीतीश सरकार को किसानों को उनका वाज़िब हक़ देना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने किसानों से भी अपील की, कि वे अपने आंदोलन को हिंसक न बनाएं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं. नवीननगर की घटना से चिंतित सुलभ के मुताबिक़ अगर सरकार किसानों से लगातार संवाद कायम रखती तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती. साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार को काबू करने के लिए सरकार को घोषणाओं की बजाय ठोस कदम उठाने चाहिए.

सिपाही टोला में सड़क नहीं है

महनार के सिपाही टोले में सड़क का संकट बढ़ता जा रहा है. तेरह वर्ष पूर्व यहां की सड़क का मरम्मत हुई थी, तब से आज तक सड़क बदहाली में है. समाजसेवी डॉ. अनवर आलम के नेतृत्व में लोगों ने कई दरवाजों को खटखटाया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला. लोगों ने विधानसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार का सामूहिक निर्णय लिया था, पर अनुमंडल पदाधिकारी के आश्वासन पर इन लोगों ने इसे वापस ले लिया था. *–चौथी दुनिया ब्यूरो*

नववर्ष 2011 के साथ-साथ गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, सभी मंत्रीगण, विधायक और खगड़िया की जनता को
हार्दिक बधाईयां!
निवेदक
अरुण कुमार यादव
प्रदेश महासचिव, जदयू, बिहार

नवीन वर्ष 2011 और गणतंत्र दिवस के मौके पर खगड़ियावासियों सहित वार्ड नम्बर 16 की जनता को
ढेर सारी शुभकामनाएं!
निवेदक
विजय कुमार यादव
वार्ड पार्षद
वार्ड नम्बर-16
नगर परिषद, खगड़िया

नया साल 2011 के मौके पर और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी किसान भाईयों के साथ-साथ खगड़िया की जनता और प्रशासनिक पदाधिकारियों को
हार्दिक बधाईयां!
निवेदक
आशुतोष कुमार
प्रो.- कुशवाहा सीड्स
एसडीओ रोड, खगड़िया, मो.-9431418255

नूतन वर्ष 2011 और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, सभी मंत्रीगण, विधायक और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ खगड़िया सहित बिहार की जनता को
हार्दिक बधाईयां
निवेदक
शशि भूषण प्रसाद
जिला अध्यक्ष, भाजपा, खगड़िया

नववर्ष 2011 तथा गणतंत्र दिवस के मौके पर खगड़िया जिले के उत्तर माड़र पंचायत की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं!
सीता देवी
पंचायत समिति सदस्य, उत्तर माड़र, ग्राम- बलैठ, खगड़िया

गणतंत्र दिवस पर समस्त झारखंडवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं
सुबोधकान्त सहाय
केन्द्रीय पर्यटन मंत्री
सह सांसद
रांची लोकसभा क्षेत्र

समस्त झारखंडवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
राजेन्द्र प्रसाद सिंह
नेता प्रतिपक्ष
झारखंड विधानसभा
सह
राष्ट्रीय महामंत्री
इंटक

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 31 जनवरी-06 फरवरी 2011

कोयला चोरी को रोकने की बात हर सरकार करती है. इसके लिये तरह-तरह के उपाय भी किए जाते हैं. कभी टास्क फोर्स का गठन होता है तो कभी लगातार छापेमारी की जाती है.

काले हीरे का काला बाज़ार

नवल किशोर सिंह

झारखंड की सत्ता संस्कृति कमोबेश कोयले और लोहे के अवैध धंधे से ही ऊर्जा प्राप्त करती है. यह धंधा राज्य के ताक़तवर नेताओं और आला अधिकारियों के संरक्षण में बड़े ही संगठित रूप से संचालित होता है. कोल इंडिया की दो अनुशंगी कंपनियां भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की खदानें पूर्ण रूप से और ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की कुछेक खदानें झारखंड की सीमा के अंदर आती हैं. इन इलाक़ों में एक प्रचलित शब्द है डिस्को पेपर. इसका इस्तेमाल चोरी के कोयले को सड़क मार्ग से मंडी तक पहुंचाने के ग़ैर सरकारी परमिट के रूप में किया जाता है. रास्ते में पड़ने वाले पुलिस थानों से लेकर तमाम सरकारी महकमे को इसकी जानकारी रहती है. यह एक सांकेतिक टोकन होता है, जिसे कोयला माफिया हर दिन बदल देता है. प्राय: दस या बीस रुपये के नोटों की गड्डी से एक-एक नोट को निकालकर आधा फाड़ दिया जाता है और चोरी का कोयला ले जाने वाले ट्रक को निर्धारित फीस के एवज में दिया जाता है. किस इलाक़े से किस सीरीज़ के नोट जारी किए गए हैं, सुबह माफिया के गुर्गे रास्ते के तमाम थानों को सूचित कर देते हैं. ट्रक वालों को सिर्फ़ इसे दिखाना होता है. उन्हें हर थाना क्षेत्र में वीआइपी ट्रीटमेंट मिलता है. वैध कोयले से लदी गाड़ी भले ही रोक ली जाए, लेकिन अवैध कोयले की गाड़ियों को कोई नहीं रोकता. कारण, हर सप्ताह माफिया की तरफ़ से बंधी बंधाई रकम का पैकेट उन तक पहुंच जाता है. पुलिस की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिये कभी-कभी मैच फिक्सिंग के अंदाज़ में कोयले की बरामदगी भी करा दी जाती है.

झारखंड के कोयला खदान क्षेत्रों से लेकर हाइवे तक कार्य विभाजन के आधार पर धंधे का संचालन होता है. माफिया, पुलिस, औद्योगिक सुरक्षा बल और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में कुछ दबंग किस्म के अपराधकर्मी बंद खदानों में अवैध उत्खनन कराते हैं. इसमें प्राय: स्थानीय ग़रीब बेरोज़गारों को दैनिक मज़दूर के रूप में लगाया जाता है. असुरक्षित और अवैज्ञानिक खनन कार्य के कारण दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं, जिसमें मौतें भी हो जाती हैं, लेकिन प्राय: स्थानीय ग्रामीण शवों को हटा लेते हैं और चुपके से अंतिम संस्कार कर देते हैं. अवैध उत्खनन में लिप्त होने की बात कोई स्वीकार नहीं करता. प्रतिदिन अवैध उत्खनन से उत्पादित कोयले को अवैध डिपो में एकत्र किया जाता है. जंगल, पहाड़ और आबादी से ज़रा हटकर बने इन डिपो का संचालन भी माफिया के गुर्गों की टीम के ज़िम्मे रहता है. स्थानीय ग्रामीण कोयला खदानों से कोयला चुराकर साइकिलों पर लादकर इन्हीं डिपो में लाकर बेचते हैं. इसके एवज में उन्हें भरण-पोषण भर रकम मिल जाती है. पुलिस वाले भी इन्हीं को परेशान करते हैं और अवैध वसूली करते हैं. रोज़गार के अभाव में ग्रामीण इस अवैध धंधे में शामिल हो जाते हैं. स्थानीय थाने को प्रति ट्रक एक हज़ार से तीन हज़ार तक नज़राना दिया जाता है. हाइवे के पहले पड़ने वाले थानों को भी प्रति ट्रक की दर से नज़राना तय रहता है. डिस्को पेपर हाइवे में प्रभावी होता है. कोयलांचल के पुलिस थानों की प्रतिदिन की कमाई लाखों में होती है, इसीलिये इन थानों में पोस्टिंग के लिए पुलिस अधिकारी मुंहमांगी रकम देने को तैयार रहते हैं. इस धंधे में पुलिस, पत्रकार, नेता और यहां तक की नक्सलियों का भी हिस्सा रहता है, जिसे पूरी ईमानदारी के साथ निर्धारित अवधि में बांट दिया जाता है. पुलिस थानों के प्रभारी अपने आला अधिकारियों को इसका हिस्सा पहुंचाते हैं. माफिया की तरफ से पुलिस, प्रशासन और राजधानी के आकाओं को अलग से पैकेट भेजा जाता है. शायद ही कोई ऐसा राजनीतिक दल हो जिसके शीर्ष नेताओं को उनकी हैसियत के मुताबिक़ थैली न पहुंचाई जाती हो. ऐसा नहीं कि यह धंधा अनवरत रूप से चलता हो. चुनाव के पूर्व या केंद्र के ज़्यादा दबाव बढ़ने पर कुछ समय के लिए इसका पैमाना घटा दिया जाता है. ऐसे मौक़ों पर सरकार की छवि सुधारने के लिए ईमानदार और कड़े प्रशासकों का पदस्थापन कोयलांचल के इलाकों में किया जाता है. फिर माहिर अधिकारियों को भेजकर धंधे का दायरा बढ़ा दिया जाता है.

चोरी के कोयले को मंडी तक पहुंचाने का काम भी कुछ ख़ास ट्रक मालिक करते हैं. उन्हें सामान्य से अधिक भाड़ा मिलता है और रास्ते में कोई परेशानी नहीं होती. कोयला माफिया के पास ऐसे ट्रकों की लिस्ट रहती है. वे हर ट्रिप के बाद माफिया के यहां उपस्थिति दर्ज करा देते हैं. उन्हें दिन के वक़्त ही बता दिया जाता है कि किस डिपो से लोड लेना है. शाम ढलने के बाद इनपर कोयले की लदाई होती है और देर रात वे हाइवे पकड़ लेते हैं. अधिकांश कोयला डिहरी और बनारस की मंडियों में खपाया जाता है, जहां से इसे देश के दूसरे इलाक़ों के कोयला व्यापारी ख़रीद ले जाते हैं.

कोयला चोरी को रोकने की बात हर सरकार करती है. इसके लिये तरह-तरह के उपाय भी किए जाते हैं. कभी टास्क फोर्स बनाई जाती है तो कभी लगातार छापेमारी की जाती है. कभी चिन्हित कोयला तस्करों को गिरफ्तार कर जेल में भी डाला जाता है. लेकिन सब सिर्फ़ दिखावे के लिये. सत्ता में बैठे लोगों के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग रहते हैं. एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष क़रीब 1000 करोड़ का कोयला चोरी से मंडियों तक पहुंचाया जाता है. कुछ बड़े तस्करों का जाल तो नेपाल और चीन तक बिछा हुआ है. चोरी का कोयला स्थानीय स्तर पर भी रोलिंग मिलों, ईंट भट्ठों आदि में धड़ल्ले से खपाया जाता है. उन्हें यह कोयला सस्ता पड़ता है. चोरी का कोयला खपाने वाले कल-कारखानों का नज़राना भी स्थानीय स्तर से राजधानी तक पहुंचता है. बहरहाल, काले हीरे के काले धंधे में कई सफ़ेदपोश लाल हो रहे हैं. इसे कोई स्वीकार करे न करे, लेकिन कोयले की दलाली में अच्छे-अच्छों के हाथ काले हो रहे हैं, जिसे वे तरह-तरह के दास्तानों के पीछे छिपाए रहते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

इंडियन इंस्टीच्युट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एण्ड रिसर्च
हेल्थ इंस्टीच्युट रोड, बेउर, पटना-२
(बिहार सरकार, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार तथा आइ.ए.पी.से मान्यता प्राप्त)
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया से संबंधन प्राप्त
हम निम्नलिखित में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं:
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
मास्टर ऑफ फिजियोथेरापी
मास्टर ऑफ अकुपेशनल थेरापी
मास्टर ऑफ प्रॉस्थेटिक एण्ड ऑर्थोटिक*
मास्टर ऑफ ऑडियोलॉजी एण्ड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी*
एम. एड. (स्पेशल एजुकेशन)*
स्नातक स्तरीय पाठ्क्रम
बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी
बैचलर ऑफ अकुपेशनल थेरापी
बैचलर ऑफ प्रॉस्थेटिक एण्ड ऑर्थोटिक
बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एण्ड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी
बी.एड. (स्पेशल एजुकेशन)
बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी
बैचलर ऑफ रेडियोइमेजिंग टेक्नोलॉजी
बैचलर ऑफ बायो-टेक्नोलॉजी
बैचलर ऑफ ऑफ्थालमोलॉजी
डिप्लोमा पाठ्यक्रम
डिप्लोमा इन फिजियोथेरापी
डिपलोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी
डिप्लोमा इन एक्स-रे टेक्नोलॉजी
डिप्लोमा इन प्रॉस्थेटिक एण्ड ऑर्थोटिक
डिप्लोमा इन हॉस्पीटल मैनेजमेन्ट
डिप्लोमा इन ओ.टी.असिस्टेन्ट
डिप्लोमा इन इ. सी. जी.
सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसींग
डी.पी.टी./डी.ओ.टी. के लिये १ वर्षीय अब्रीज्ड डिग्री इन
फोन न. : 0612-2253290, 2252999, फैक्स: 0612-2253290, www.iiher.ac.in

Anil Sulabh
Director-in-Chief

बेगूसराय सहित समस्त बिहारवासियों को
नववर्ष एवं गणतंत्र दिवस की
हार्दिक शुभकामनायें

D'damas
आकर्षक व मनपसन्द गहनों का
आपका अपना शो रूम

विनोद सोनी ज्वेलर्स
डमरूलाल दुर्गास्थान, देव मार्केट, मुंगेरीगंज, बेगूसराय
9031113944, 9835258815 06243-240664

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

दिल्ली, 31 जनवरी–06 फरवरी 2011

www.chauthiduniya.com

भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़

बुंदेलखंड के किसान लामबंद

सुरेंद्र अग्निहोत्री

यह सिर्फ़ संयोग नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ उठती आवाज़ें आर–पार की लड़ाई में तब्दील हो रही हैं. अधिग्रहण क्षेत्र से किसानों का हालचाल लेकर लौटे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघु ठाकुर कहते हैं कि कॉरपोरेट पूंजीवाद ने ज़मीन हड़पने और इसे अधिक से अधिक पैसा कमाने का एक शॉर्टकट रास्ता खोज लिया है. यह तो शुरुआत है. जब किसानों के लिए भूमि रखने की सीमा तय है तो फिर ये नए ज़मींदार क्यों पैदा किए जा रहें हैं. अंग्रेजी राज्य के जमींदारों से मुक्ति के लिए लड़ी गई आज़ादी की लड़ाई व्यर्थ साबित हो जाएगी. डूब क्षेत्र में आई ज़मीनों के मुआवज़े के मामले व अन्य मांगों को लेकर किसानों में ज़बरदस्त गुस्सा है. मांगों को मनवाने के लिए किसानों ने लाठी–डंडों और जानवरों के साथ बेतवा भवन पर डेरा डाल दिया.

किसानों के गुस्से को देखते हुए चप्पे–चप्पे पर पुलिस का पहरा बिठाना पड़ा था. किसानों का कहना है कि बार–बार शिकायत करने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, जब तक सुनवाई नहीं होती है वह हिलने वाले नहीं. किसानों ने बेतवा भवन परिसर में ही जानवरों को बांधने के लिए खूंटे गाड़ दिए. मुठ्ठी भर मुआवज़ा देकर किसानों की ज़मीन अधिग्रहित करने से बौखलाए किसानों ने बुंदेलखंड किसान पंचायत के अध्यक्ष गौरी शंकर विदुआ के नेतृत्व में चौधरी चरण सिंह बेतवा भवन में डेरा डाल दिया. सैंकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों ने न सिर्फ़ सरकार के ख़िलाफ़ जोरदार नारेबाज़ी की, बल्कि चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वह आमरण अनशन की राह पकड़ लेंगे. सिंचाई विभाग में धरना दिए किसानों को संबोधित करते हुए विदुआ ने कहा कि सरकारी योजनाओं के लिए सरकार द्वारा उपजाऊ ज़मीन अधिग्रहित की जा रही है, लेकिन किसान इसका विरोध नहीं कर रहे है. विरोध है अधिकारियों द्वारा किए जा रहे शोषण का. उन्होंने कहा कि किसान के लिए ज़मीन ही भविष्य होती है. किसानों का कहना है कि सरकार ज़मीन का कम से कम इतना मुआवज़ा तो दे कि वह पुर्नस्थापित हो सके. उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो मुआवज़े के स्थान पर अन्य जगह किसान को अधिग्रहित ज़मीन के बराबर भूमि उपलब्ध करा दें, जिससे किसान का जीवन बसर हो सके और उसे बेघर होकर दर–दर की ठोकर न खानी पड़े. उन्होंने कहा कि अधिग्रहण क़ानून एक साल पुराना है. अंग्रेजों ने किसानों के उत्पीड़न के लिए इसे बनाया था. आज़ादी के 63 साल बाद भी वही दमनकारी क़ानून किसानों पर थोपा जाना न्याय संगत नहीं है. जानवरों और परिवार पर आई समस्याओं को लेकर आंदोलन करने वाले किसानों ने बेतवा भवन परिसर में न सिर्फ़ डेरा डाला बल्कि अपने साथ लाए जानवरों को भी बांध दिया. अपने साथ परिवार को लेकर पहुंचे किसानों की पत्नियां ढोल मजीरों के साथ गाना–गाने लगीं. किसानों का कहना है कि अब वह तभी हटेंगे जब उनकी मांगे मान ली जाएंगी. इसके लिए चाहे आमरण अनशन तक क्यों न करना पड़ जाए. किसानों का आरोप था कि वह सवा साल से इन मांगों को अधिकारियों के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही थी, इसलिए उन्हें ऐसा क़दम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा.

उन किसानों की प्रमुख मांगों में डूब क्षेत्र में आए जरवई गांव को विस्थापित किया जाए. पहूज बांध में प्रभावित सभी किसानों को समान व उचित मुआवज़ा दिया जाए. बुड़ाई व बचेरा गांव के विस्थापित किसानों को पुनर्वास नीति 27 के तहत सुविधाएं दी जाएं. लखेरी बांध में प्रभावित किसानों को राज्य सरकार द्वारा घोषित लाभ दिए जाएं. बलपूर्वक कराई रजिस्ट्रियां अभी कराई जा रहीं रजिस्ट्रियों के भूमिधरों को 25 लाख रुपये हेक्टेयर के हिसाब से मुआवज़ा दिया जाए. गिरारी पंप कैनाल का निर्माण किया जाए. बुंदेलखंड में मौजूद खनिज संपदा और यहां की भूमि को माटीमोल क़ीमत में हड़पने की साज़िश रच रहे उद्योगपतियों के लिए बुंदेलखंड अब सबसे अच्छा क्षेत्र लगने लगा है. वर्षों से सूखे के कारण बरबाद हो चुके किसानों में संघर्ष करने की हिम्मत अब जवाब दे गई है. ललितपुर जनपद में लगे विशाल बारूद कारखाने भारत एक्सप्लोसिव लिमिटेड की फैक्ट्री से निकलने वाली ज़हरीली गैसों और दूषित पानी का उचित प्रबंध न करने के कारण आसपास के इलाक़े के खेतों की फ़सल की लंबाई औसत से अधिक बढ़ जाने और दाने न होने की शिकायत के साथ शुरू हुआ था.

हद तो तब हो गई जब कचनौंदा बांध के कारण डूब रही किसानों की भूमि के लिए किसानों द्वारा सही मुआवज़ा लेने की मांग को लेकर वर्ष 2008 में आंदोलन शुरू किया. इस आंदोलन को धार न मिले, इसके लिए ठेकेदारों और सरकारी मशीनरी ने मिलकर इस आंदोलन की गति को रोकने की साज़िश रची. इस साजिश से डूब क्षेत्र के किसानों को भारी नुकसान हुआ. सरकारी परियोजना होने के कारण किसानों को थोड़ा बहुत हक़ फिर भी मिल ही गया. ललितपुर में लगने वाले पावर प्रोजेक्ट में एक नए तरह का सिस्टम सामने आया, जिसने सोचने को विवश कर दिया है कि जनपदों में रहने वाले लोग कितने संवदेनहीन होकर चांदी के चंद चमकते सिक्कों के लालच में अपनों के हक़ों पर डाका डलवा रहे हैं. बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड द्वारा ललितपुर जनपद के बार ब्लॉक के अंर्तगत आने वाले बुरा गांव में 317.26 हेक्टेयर तथा मिर्चवारा ग्राम में 114.37 हेक्टेयर किसानों की भूमि अधिग्रहण करके तापीय विद्युत कारखाने की स्थापना हेतु धारा 4 और 6 के प्रकाशन के बाद धारा 17 के तहत कंपनी द्वारा क़ब्ज़े की कोशिश की गई. इसमें किसानों के कंपनियों से संघर्ष के बाद अधिग्रहीत भूमि क्षेत्र में कंपनी द्वारा गाड़े गए सीमांकन चिन्हों को किसानों द्वारा उखाड़ फेंकने की घटना के बाद कुछ समाचार पत्रों ने अपनी भूमिका अजीब तरह से इंगित की. उनके द्वारा भेजे गए समाचारों के शीर्षक में इस बात को विशेष रूप से इंगित किया गया कि किसान एनटीपीसी के कारखाने का विरोध कर रहें हैं. जबकि जनपद में कोई परियोजना एनटीपीसी द्वारा संचालित नहीं की जा रही है. इस तरह के दुष्चक्र के माध्यम से 4000 हज़ार जनसंख्या वाले सहरिया आदिवासी, बुनकर, अहिरवार, पाल गड़रिया, ब्राह्मण, और यादवों के इस गांव के लोग नाराज़ है. ज़िलाधिकारी को लिखित में अपनी ज़मीन न देने का ज्ञापन देकर सरकार के निर्णय की प्रतिक्षा कर रहें हैं. ज़मीन अधिग्रहण से विस्थापित होने वाले 300 परिवारों को प्रशासन द्वारा अभी तक अधिग्रहण नीति के तहत मिलने वाले परिणामों के तहत होने वाले पुर्नवास से अवगत नहीं कराया गया.

यही हालात बुंदेलखंड से लगे इलाहाबाद मंडल में भी हैं. वहां के किसान किसी भी हालत में अपनी ज़मीन देने को तैयार नहीं हैं. कुछ–कुछ यही हालत शिवराजपुर (इलाहाबाद), शंकरगढ़ क्षेत्र के पावर प्लांट की स्थापना को लेकर अक्सर ही किसानों व निर्माण में लगी कंपनी जेपी समूह के बीच तकरार का माहौल बना रहता है. भारतीय किसान दलित मज़दूर किवास मंच शंकरगढ़ के तत्वाधान में किसानों ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर हड़ताल की. उक्त निर्माण को लेकर अक्सर ही बवाल होता आया है, मुआवज़ा, किसानों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी, चिकित्सा व शिक्षा की सुविधाएं समेत तमाम मांगों को लेकर ग्राम प्रधान बेमरा के नेतृत्व में भारी संख्या में किसान उक्त मंदिर पर पहुंचे इस बार यही आरोप था कि किसानों को उनके हक़ से वंचित रखा जा रहा है. केवल आश्वासन देकर उन्हें गुमराह किया जा रहा है. ललितपुर में कृषि भूमि को विभिन्न परियोजनाओं के नाम पर लूट का खुला खेल जारी है. कभी उद्योगों के नाम पर कभी बांध के नाम पर तो कभी वनों के नाम पर लाखों परिवारों को उजाड़ने का अनवरत सिलसिला जारी है. इस मामले में सबसे दुर्भाग्यशाली जनपद के रूप में ललितपुर का नाम आता है. सरकार डूब क्षेत्र को बीसियों साल पहले डूबा हुआ मानकर सो जाती है. दो तिहाई से ज़्यादा ज़मीन गंवा चुके इस जनपद के वाशिंदों की लड़ाई लड़ने के लिए कोई मेधा पाटकर और अरुंधति राय सामने नही आ रहीं हैं. इस जनपद के 180 गांव में 1 सैकड़ों गावों का अस्तित्व डूब और भूमि अधिग्रहण के चलते समाप्त हो गया है. जिसके कारण इस क्षेत्र में रहने वाली आदिवासी, सहेरिया जनजाति के समाप्त होने का ख़तरा उत्पन्न हो गया है. सिर्फ़ यादों में बसे गांव आतंक, संत्रास और ख़ौफ का रूप रह गए हैं. औद्योगिक विकास के इस अमानवीय खलनायक के ख़िलाफ़ जिसने भी जंग में भाग लेने की कोशिश की उसे सरकारी मशीनरी ने तहस–नहस कर डाला. जिसके कारण खामोश ललितपुर के जंगलों, गांव और समाजों की बलि विकास के नाम पर लगातार हो रही है. नदियों पर बनने वाले बांधों के विरोध में 20वीं सदी में विरोध की घटनाओं में एक बेतवा नदी पर बने राजघाट बांध (लक्ष्मीबाई सागर) पर इस अंचल में जन्मे बीरेंद्र जैन ने डूब उपन्यास लिखकर इस दु:ख गाथा को दुनिया भर में उजागर भले ही कर दिया हो, लेकिन डुबोने का षडयंत्र आज भी जारी है.

feedback@chauthiduniya.com

हद तो तब हो गई जब कचनौंदा बांध के कारण डूब रही भूमि के लिए सही मुआवज़े की मांग को लेकर वर्ष 2008 में किसानों ने आंदोलन शुरू किया. यह आंदोलन आगे न बढ़ सके, इसलिए ठेकेदारों और सरकारी मशीनरी ने मिलकर इस आंदोलन की धार को कुंद करने की साज़िश रची.

भारत के आरिफ ख़ान ने 2 मीनट 21 सेकेंड 60 फ्रेक्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता. इस खेल की सफ़लता के बाद लोग मानने लगे हैं कि सैफ विंटर गेम्स का सफ़र ओलंपिक तक जाएगा.

चूड़ियां बनाने के लिए कांच सोडा ऐश, सिलिका सेंट आदि के मिश्रण को 1450 डिग्री सेंटीग्रेट पर पिघलाकर बनाया जाता है और इस गर्म कांच से महीन व हल्की चूड़ियां बनती हैं.

सैफ गेम्स में भारत का जलवा क़ायम

राजकुमार शर्मा

औली में आयोजित सैफ विंटर गेम्स की स्कीइंग प्रतिस्पर्धाओं में भी भारतीय खिलाड़ियों का जलवा कायम रहा. भारत के भाल हिमालय की कोख में बसे औली की बर्फीली ढलानों पर पहले दक्षिण एशियाई शीत कालीन खेलों के दूसरे चरण की शानदार शुरुआत हुई.

कार्यक्रम में ख़राब मौसम के बावजूद बर्फ की चादर पर दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ा. इस कार्यक्रम में जनता की बड़ी संख्या में भागीदारी के लिए खेल के आकर्षण के साथ ही पौड़ा नृत्य की बहार और सूफी गायक कैलाश खेर की शानदार गायकी को सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी. कार्यक्रम की ख़ास बात यह रही की इस पूरे कार्यक्रम पर नारायण की मेहरबानी को लोग सराहते दिखे. इस खेल को लोग उत्तराखंड का पर्याय साहसिक खेल मान रहे हैं. सैफ खेल के पहले दिन ही भारत–पाक के मध्य कड़ा मुक़ाबला रहा. इस मुक़ाबले में ज्वाइंट सलालम की स्पर्धा में भारत को गोल्ड और सिल्वर लेने में क़ामयाबी मिली. इस साहसिक खेल में महिलाएं भी किसी से कम नहीं रहीं. महिलाओं की क्रॉस कंट्री स्पर्धा में सभी पदक भारत की झोली में आए. पाकिस्तान की सगी बहनें इरफावली व अमीन वली ने ज्वाइंट सलालम में स्वर्ण और रजत पदक पर क़ब्ज़ा कर लिया. पुरुषों के ज्वाइंट सलालम में भारत के आरिफ ख़ान ने 2 मिनट 21 सेकेंड 60 फ्रेक्शन के साथ स्वर्ण पद जीतने का इतिहास रचा. इस खेल की सफ़लता के बाद लोग मानने लगे हैं कि सैफ विंटर गेम्स का सफ़र ओलंपिक तक जाएगा. इस सैफ गेम में भारत के साथ पाक ने भी अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज़ कराई. पाक की महिला खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को देख कर लोग दंग रह गए. शानदार प्रदर्शन के साथ पाकिस्तान की उकरावली ने सोना और उसकी बहन अमीनावली ने चांदी के तमगे पर अपना क़ब्ज़ा जमाया. श्रीलंका की कुमुदनी महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीत कर अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज़ कराई.

औली के बर्फीले घुमावों पर पहले सैफ विंटर गेम की स्कीइंग प्रतिस्पर्धाओं की शुरुआत हुई. भारत के खिलाड़ी आरिफ ख़ान ने स्वर्ण पदक जीता तो जामीनयांग नांग्याल को रजत पद मिला. पाक के मीर नवाज जूनियर को कांस्य पदक मिला. 5 किलोमीटर की वीमेन नाडिक इवेंट में तीनों पदक भारतीय महिला खिलाड़ियों ने जीते. उत्तराखंड की प्रीति डिमरी के प्रदर्शन से दर्शकों को भारी निराशा हाथ लगी. पांच सेकेंड के अंतर से डिमरी पीछे रह कर कांस्य पदक तक ही अपनी पहुंच बना पाई. इस अवसर पर मुदस्सर भट्ट को स्वर्ण, जहूर ख़ान को रजत और साबिर ख़ान को कांस्य पदक मिले. इस खेल में अपने संगीत से शमा बांधने में सूफी गायकी के बादशाह गायक कैलाश खेर ने कोई कोर कसर नही छोड़ी. इस अवसर पर भारत के साथ पाक, नेपाल, भूटान, मालदीप, श्रीलंका, बांग्लादेश, आदि देशों के खिलाड़ियों में भारी उत्साह दिखा. औली के नाली नुमा खेतों में किसान जहां आलू–बंडा मूंगफली की खेती किया करते थे, वहां इस अवसर पर सात–सात देशों के खिलाड़ियों ने अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ कुर्बान होने का जज़्बा दिखाया. आदि जगतगुरू शंकराचार्य की ज्ञान ज्योर्तिस्थली के कारण जोर्तिमठ के रूप में विख्यात जोशीमठ इन दिनों भारी चहल पहल के मध्य हिमालय का गौरव बढ़ा रहा है. इस अवसर पर पाक की दोनों बहनों की शानदार सफ़लता के लिए सैकड़ों लोग जो भारतीय थे, उन्हें बधाईयां दे रहे थे. वहीं पाक की दोनों महिला खिलाड़ियों ने भी दोनों मुल्कों में अमन–चैन की दुआ मांगी. इस खेल में पाक के 22 सदस्य दल भारत में आयोजित इस साहसिक खेल में भाग लेने आया हुआ है. कार्यक्रम में स्कीइंग प्रतियोगिता का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री डॉ.रमेश पोखरियाल निशंक ने किया.

feedback@chauthidunya.com

उत्तराखंड की प्रीति डिमरी के प्रदर्शन से दर्शकों को भारी निराशा हाथ लगी. पांच सेकेंड के अंतर से डिमरी पीछे रह कर कांस्य पदक तक ही अपनी पहुंच बना पाई. इस अवसर पर मुदस्सर भट्ट को स्वर्ण, जहूर ख़ान को रजत और साबिर ख़ान को कांस्य पदक मिले. इस खेल में अपने संगीत से शमां बांधने में सूफ़ी गायकी के बादशाह गायक कैलाश खेर ने कोई कोर कसर नही छोड़ी. कार्यक्रम में स्कीइंग प्रतियोगिता का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री डॉ.रमेश पोखरियाल निशंक ने किया.

अब सरयू नदी भी ख़तरे में

रामायण के अनुसार भगवान राम ने इसी नदी में जल समाधि ली थी. सरयू नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले से हुआ है. बहराइच से निकलकर यह नदी गोंडा से होती हुई अयोध्या तक जाती है. पहले यह नदी गोंडा के परसपुर तहसील में पसका नामक तीर्थ स्थान पर घाघरा नदी से मिलती थी. अयोध्या तक यह नदी सरयू के नाम से जानी जाती है, लेकिन उसके बाद यह नदी घाघरा के नाम से जानी जाती है. सरयू नदी की कुल लंबाई लगभग 160 किलोमीटर है. हिंदुओं के पवित्र देवता भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से हो कर बहने के कारण हिंदू धर्म में इस नदी का विशेष महत्व है.

प्रियंका प्रियम तिवारी

नदियों में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण आज तमाम नदियों का अस्तित्व ख़तरे में है. गंगा यमुना जैसी बड़ी नदियों के साथ ही छोटी नदियों की हालत तो और भी ख़राब है. इन छोटी नदियों की साफ़ सफाई की तरफ़ तो किसी का ध्यान भी नहीं है. इन्हीं नदियों में ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सरयू नदी का अस्तित्व भी अब ख़तरे में है. रामायण के अनुसार भगवान राम ने इसी नदी में जल समाधि ली थी. सरयू नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले से हुआ है. बहराइच से निकलकर यह नदी गोंडा से होती हुई अयोध्या तक जाती है. पहले यह नदी गोंडा के परसपुर तहसील में पसका नामक तीर्थ स्थान पर घाघरा नदी से मिलती थी. पर अब यहां बांध बन जाने से यह नदी पसका से क़रीब 8 किलोमीटर आगे चंदापुर नामक स्थान पर मिलती है. अयोध्या तक ये नदी सरयू के नाम से जानी जाती है, लेकिन उसके बाद यह नदी घाघरा के नाम से जानी जाती है. सरयू नदी की कुल लंबाई लगभग 160 किलोमीटर है. हिंदुओं के पवित्र देवता भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से हो कर बहने के कारण हिंदू धर्म में इस नदी का विशेष महत्व है. सरयू नदी का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है. पर अब यह ऐतिहासिक नदी अपनी महत्व खोती जा रही है. लगातार होती छेड़छाड़ और मानवीय दख़ल के कारण इस नदी का अस्तित्व अब ख़तरे में है. इस नदी में लगातार अवांछित तरिक़े से होते जलीय जीव–जंतुओं का शिकार और यहां के चीनी मीलों से निकलने वाला कचरा और प्रदूषित पानी बिना किसी रोक टोक के इस नदी में बहाया जाता है. इस नदी में प्रदूषण कर आलम यह है कि इसमें जीव जंतु भी जीवित नहीं रह पाते.

ऐसा माना जाता है कि है कि इस नदी के पानी में चर्म रोगों को दूर करने की अद्भुत शक्ति है. इस नदी में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के साथ ही ऐसी वनस्पतियां भी हैं, जो नदी के पानी को शुद्ध कर पानी में औषधीय शक्ति को भी बढ़ाती हैं. लेकिन पिछले कुछ समय से इस नदी के साथ लगातार होते छेड़छाड़ के कारण इस नदी का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है. जहां इस नदी में नहाने को पवित्र माना जाता है, और मान्यता है कि इस नदी में नहाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है. पर आज इस नदी का यह हाल है कि पर इस नदी के आस पास रहने वाले लोगों कि शिकायत है कि इस नदी में नहाने से शरीर में खुजली हो जाती है. यहां आस पास के चीनी मीलों का कचरा और चीनी बनाने कि प्रक्रिया में प्रयोग होने वाले केमिकल इस नदी में सीधा सीधा बहा दिया जाता हैं. इसमें बहाए जाने वाले केमिकल का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं होता, बल्कि जानवरों पर भी देखा गया है. प्रदूषण के कारण इस नदी के में रहने वाले जीव जंतु बड़ी संख्या में मर रहे हैं. नदियों को समितियों में बांटा गया है, जिस समिति के हिस्से में जो क्षेत्र आया है वो उसी का दोहन करने में लगा है. सरकार ने नदी से मछली पकड़ने के लिए कुछ मापदंड बनाया है. पर सारे क़ायदे क़ानून को ताक़ पर रखकर लोग मछलियां पकड़ते हैं. नियम क़ानून तो बना दिए जाते हैं, पर सरकार यह देखने कि जहमत नहीं उठाती कि उन नियमों का पालन हो भी रहा है या नहीं. यही वजह है कि लोग नियमों को ताक़ पर रखकर खुलेआम ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से मछलियां पकड़ते हैं. जहां नदियों में एक छोर से दूसरे छोर तक बांध बनाना ग़ैरक़ानूनी है, वहीं यहां यह नज़ारा आम है. यहां हर दस से पंद्रह किलोमीटर की दूरी पर बांध बना हुआ देखा जा सकता है. यहां कई तरीक़े से बांध बंधे हुए हैं. इन बांधों के कारण नदी के पानी का बहाव अवरूद्ध हो रहा है, जिससे मछलियां, कछुए और अन्य जीव जंतु नदी के दोनों बांधों के बीच फंस जाते हैं. जिससे नदी के जीव मर जाते हैं.

बरसात के मौसम में मछलियां नदी के बहाव के ठीक विपरीत दिशा की तरफ अंडे देती है. लेकिन बरसात के खत्म होते ही जब ये मछलियां नदी के बहाव की तरफ वापस जाती हैं तो उस समय नदी पर पुनः बांध बंधना शुरू हो जाता है. ऐसे में मछलियां दो बांधों के बीच में फंस जाती हैं. फिर ये पूरे नदी में नहीं घूम पातीं, जिससे किसी क्षेत्र में ज़्यादा मछलियां मिल जाती है, तो किसी क्षेत्र के लोगों को कुछ नहीं मिलता. इन बांधों के कारण जगह–जगह से वह कर आने वाली गंदगी भी इन बांधों के बीच फंस जाती है, जो सड़कर पूरे पानी को प्रदूषित करती है. इस प्रदूषित पानी में कई विषैले जीवाणु उत्पन्न होते हैं, जो कई बिमारियों के वाहक होते हैं. ये विषैले जीवाणु इंसानों ही नहीं जानवरों को भी नुक़सान पहुंचाते हैं.

priyanka @chauthidunya.com

मानवीय हस्तक्षेप से तंग जानवर जंग पर आमादा

जानवरों के लिए सुरक्षित समझे जाने वाले उत्तराखंड के जंगलों में मानवीय दख़ल से तंग जानवर आबादी की ओर रुख़ कर रहे हैं. हर दिन एक गजराज की अकाल मौत से राजाजी पार्क सहित पूरे इलाक़े में हड़कंप मचा हुआ है. उत्तरकाशी सहित टिहरी में वनाधिकारियों द्वारा टाइगर के खाल और नाख़ून सहित कई अंग बरामदगी से यह बात पता चलती है कि शिकारी इन जंगलों को कब्रगाह बनाने पर तुले हैं. वनाधिकारी गाहे बगाहे कुछ बरामदगी दिखा कर अपने कर्तव्य की इतिश्री ज़रूर कर लेते हैं. जंगलों में घुसकर इन वन्यजीवों के जीवन में खलल पैदा करने वालों को जब कभी बाघ–बाघिन अपना आहार बना लेती है, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा लेडी किलर कह कर बदनाम किया जाता है. वन विभाग द्वारा ऐसी स्थिति में इस टाइगर को गोली मारने के आदेश दिए जाने को वन्य जीव प्रेमी दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे हैं. उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद यहां के वन्य क्षेत्र से सट कर बस्ती बसाने का जो अंतहीन सिलसिला शुरू हुआ है, वह रुकने का नाम नहीं ले रहा है. जंगल में मानव हस्तक्षेप भी बढ़ा है, इससे मानव व वन्यजीवों का संघर्ष भी दिनोंदिन बढ़ रहा है. उत्तराखंड की राजधानी स्थित दून चिकित्सालय इन दिनों बंदरों के काटने से घायलों से पटा पड़ा है. हर दिन लोग बंदरों के हमले से घायल होकर इलाज के लिए पहुंच रहे हैं. बंदरों के गले में रस्सी बांध कर नचाने वाला मानव इन दिनों डोईवाला, लच्छीवाला के जंगलों सहित दून से ऋषिकेश जाते समय हाथियों बंदरों गुलदारों से अपनी राह बचाता फिर रहा है. टाइगर, गुलदारों के लिए जाना जाने वाला उत्तराखंड इन दिनों इन वन्य जीवों के हमले के लिए जाना जाने लगा है. 1 जुलाई 2010 में पहले दिन ही घंघोटा, कोटरा संतूर बाजावाला में गुलदार का जो हमला हुआ, उसमें दो लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा. आठ लोग घायल हुए. 14 अक्टूबर को मोतीचूर में हाथी ने एक महिला की जान ले ली थी. 5 नवंबर को रायवाला के खाड़गांव में हाथी ने दो लोगों को अपने पांव से कुचल कर मौत के घाट उतार दिया था. 9 दिसंबर कोसातमोड़ के पास टस्कर हाथी ने एक महिला की जान ले ली थी. 21 दिसंबर को किद्दू वाला के पास एक गुलदार आवासीय कालोनी में घुस आया था, जिसे भयाक्रांत नागरिकों ने वन कर्मियों को बुलाकर पकड़वाया. 10 जनवरी 2011 को झाझरा के जंगल में गुलदार ने एक बच्ची को अपना शिकार बनाने के लिए हमला किया था. इसके एक दिन बाद ही इसी जंगल में एक गुलदार ने घास काटने गई महिला पर हमला बोला, इन दिनों अनारवाला के नागरिक गुलदार के आतंक से सूर्य ढलते ही घरों में कैद हो जाते हैं. अनारवाला की महिला ग्रामप्रधान निर्मला थापा बताती हैं कि गांव के लोगों का जीना दूभर हो गया है. सूबे का वनविभाग इन वन्यजीवों के हमले पर पूरी तरह तमाशबीन की भूमिका निभा रहा है. जनपद देहरादून की डीएफओ पूरी तरह से वन्यजीवों के पक्ष में खड़ी दिख रही है. उनका कहना है कि हमने जानवरों का घर उजाड़ा है. उसकी सजा मानव बस्तियों पर जानवरों के हमले के रूप में मिल रही है. मानव को अब भी सावधान होकर जंगल में हस्तक्षेप से बाज आना चाहिए. शीतकाल में गुलदार पूरी तरह मानव के लिए काल नज़र आ रहे हैं. वनजीव वैज्ञानिकों का मानना है कि शीतकाल ही उनके प्रजनन का काल है. इसी कारण वे बेकाबू होकर जंगल छोड़ बस्तियों की ओर भागने लगते हैं. उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में इस वर्ष अच्छी बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते उच्च पहाड़ों को बसेरा बनाने वाले वन्य जीव भी नीचे मैदानों का रुख़ कर रहे हैं. वन्य जीव मर्मज्ञ तीन माह जनवरी तक के काल को वन्य जीवों से विशेष सावधानी बरतने की बात कहते हैं. उत्तराखंड के जंगलों में अब भी तीन सौ से अधिक गुलदार रूद्रप्रयाग चमोली, उत्तरकाशी, लैंसडौन, मसूरी, टिहरी, नरेंद्रनगर के जंगलों में होने का सरकारी आंकड़ा है. वन को इन वन्य जीवों के लिए पूरी तरह से संरक्षित करने की आवश्यकता को नकार कर सूबे की सरकार भी बेख़ौफ़ वनों में अवैध कटान एवं मानवीय दख़ल को बढ़ावा दे रही है. यह राज्य की जनता के लिए हर हाल में आत्मघाती है.

राजकुमार शर्मा
feedback@chauthidunya.com

उक्रांद अध्यक्ष पंवार पर निशंक सरकार की पहली गाज गिरी

कल तक सूबे की भारतीय जनता पार्टी से गलबहिया कर सरकार होने का मजा लूटने वाले उत्तराखंड के एक मात्र क्षेत्रिय दल उत्तराखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पंवार पर सूबे की निशंक सरकार से समर्थन वापसी की पहली गाज दून के अफसरों ने ही गिरा दी. अपने कार्यकर्ताओं के दबाव का बहाना बना कर पंवार ने सूबे की निशंक सरकार से एक पखवारा पहले ही समर्थन वापस ले लिया था. इस समर्थन वापसी की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपने के बाद ही उक्रांद का अंदरूनी कलह सतह पर आ गया था. उक्रांद के कोटे से मंत्री दिवाकर भट्ट ने अपने दल के अनुशासन को धता बता कर सरकार से हटने से मना कर दिया था. इस घटना के बाद सूबे के मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने पवार को बुलाकर समझाने के साथ उन्हे आइना भी दिखाया था. सूबे की सरकार चुनाव के बाद उक्रांद के सहयोग से ही सत्ता में आई थी. निशंक ने मुख्यमंत्री बनते ही अपने राजनैतिक कौशल से अपनी सरकार को उक्रांद की बैसाखी से निजात दिलाते हुए उक्रांद का समर्थन जारी रखा था. उत्तराखंड में 2012 में विधानसभा चुनाव होना है. उक्रांद के सभी नेता तीन वर्ष से अधिक समय तक सरकार का मजा लूटते रहे. स्थानीय बोली और राजधानी का बहाना बना कर उक्रांद अध्यक्ष ने एकाएक सरकार से अपने समर्थन वापसी का जो नाटक रचा इससे मुख्यमंत्री की राजनैतिक कौशल के चलते क्षेत्रिय दल में दो फांक की स्थिति बनी. उक्रांद के दिग्गज नेता भट्ट ने सत्ता से अपना मोह न भंग कर के जिस तरह निशंक मोह का उदाहरण प्रस्तुत किया उससे पवार परिवार पर आफत आ गई. निशंक सरकार ने उन्हीं के कोटे से राजस्व मंत्री भट्ट के विभाग के अफसरों को आगे करके

त्रिवेंद्र सिंह पंवार

इस कार्यवाही को अमली जामा पहनाने वाले राजस्व विभाग के अफ़सरों ने पंवार की बेटी के नाम रजिस्ट्री से प्राप्त की गई. ज़मीन को सूबे के मुखिया को खुश करने के लिए ग्राम सभा को तो वापस कर दी, इस भूमि को धोखाधड़ी कर के बिक्रय करने वालों के विरूद्ध अब तक कोई क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्यवाही न हो पाना सरकार की नीयत साफ करता है.

जिस तरह पवार की बेटी के नाम ख़रीदी गई चार बीघा ज़मीन जो मियावाला में स्थित थी, इसे असामी पट्टे की ज़मीन बता कर प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में क़ब्ज़ा कर पवार को बेदखल कर दिया. पवार परिवार का कथन है कि पहले यह ज़मीन शत्रुघ्न, जगदेव, मंगल आदि से क्रय किया था. इस ज़मीन की नवैयत प्रशासन बताता है कि असामी पट्टे की थी और इस पर कार्यवाही कर ग्रामसभा को वापस कर दी गई थी. पवार के रजिस्ट्री को रजिस्ट्रार तकनीकी तौर पर सही मानते हैं, फिर तथ्यों को छिपाने की बात कहते हैं. इस सरकारी कार्यवाही ने जिस तरह के सवाल पैदा कर दिए हैं कि सरकार भी बगले झांकती नज़र आ रही है. इस कार्यवाही को अमली जामा पहनाने वाले राजस्व विभाग के अफसरों ने पवार के बेटी के नाम रजिस्ट्री से प्राप्त की गई ज़मीन को सूबे के मुखिया को खुश करने के लिए ग्राम सभा को तो वापस कर दी. इस भूमि को धोखाधड़ी कर के बिक्रय करने वालों के विरुद्ध अब तक कोई क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्यवाही न हो पाना सरकार की नीयत बताता है. राज्य में कितने लोगों को आसामी पट्टे दिए गए हैं, कितनों ने ग्रामसभा की ज़मीन का सरकार की मंशा के विपरीत कार्यवाही की, इस तरह के कई सवाल यक्ष प्रश्न की तरह अनुत्तरित है.

राजकुमार शर्मा
feedback@chauthidunya.com

चूड़ी मज़दूरों की ज़िंदगी बेहाल

पुरानी कहावत है कि दिया तले हमेशा अंधेरा रहता है. यह बात पूरी तरह देश के कांच उद्योग फिरोज़ाबाद पर लागू होती है. फिरोजाबाद के कांच उद्योग ने अपनी कला से न सिर्फ़ देश की सुहागिनों की कलाइयों को सजाया बल्कि कांच की कलात्मक कारीगरी से विदेशों में भी नाम रोशन किया है. फिरोजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर दो पर आगरा से 40 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है, जो कि देश व प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी आदि से सीधे रेल व सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है. फिरोजाबाद का 1/3 भाग आगरा, मथुरा ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र में सम्मिलित है. पर इस चमकती दुनिया के पीछे के अंधेरे को कोई भी नहीं देखना चाहता. पर हां, इतना ज़रूर है कि फिरोजाबाद के कांच उद्योग को गैस मिलने के कारण यहां के कारखानों का काला धुआं जरूर छंट गया पर आज़ादी के 63 वर्ष बाद भी यहां के मजदूरों की ज़िंदगियों से धुआं नहीं छंटा. फिरोजाबाद कांच उद्योग का उद्भव तहसील जसराना में हुआ था. जसराना ऊसर बाहुल्य क्षेत्र था, वहां ऊसर की मिट्टी के ऊपर रेह मिलती थी. यहां के धोबियों द्वारा कपड़े धोने के लिए इस रेह का प्रयोग किया जाता था. कपड़े साफ़ करने के उद्देश्य से एक कढ़ाव में वे रेह को पानी में मिलाकर कढ़ाव में नीचे से आग लगाकर रात भर गर्म करते थे. सुबह उन्हें कढ़ाव में ऊपर एक पर्त जमी मिलती थी जो कांच जैसी होती थी. अन्य जगहों की रेह आदि एवं केमिकल लेकर यहां पर कांच बनाने का कार्य आरंभ हो गया. बाद में रेह की जगह सोडे ऐश का इस्तेमाल होने लगा. कांच उद्योग के कार्य स्वरूप और आकार ने तो बहुत विस्तार ले लिया है. रूस्तम उस्ताद ने ही हिंदुस्तान में कांच की चूड़ियों के निर्माण के लिए बेलन–भट्ठी का सफ़ल प्रयोग कर चूड़ियों का निर्माण शुरू किया. रूस्तम उस्ताद ने रूस्तम ग्लास के नाम से फिरोजाबाद में पहली चूड़ी की बेलन पॉट भट्ठी की फैक्ट्री स्थापित की थी. चूड़ियों के लिए कांच सोडा ऐश, सिलिका सेंट आदि के मिश्रण को 1450 डिग्री सेंटीग्रेट पर पिघलाकर बनाया जाता है. इस गर्म कांच से महीन व हल्की चूड़ियां बनती हैं. फिरोजाबाद की पहली फैक्ट्री रूस्तम ग्लास आज बंद पड़ी है और करोड़ों का रोज़गार उपलब्ध कराने वाले रूस्तम उस्ताद के वारिस ही आज इस रोज़गार में काफ़ी पिछड़े हुए हैं. फिरोजाबाद का कांच एवं चूड़ी उद्योग आज देश का सबसे बड़ा कांच–उद्योग केंद्र बन गया है. आज फिरोजाबाद में विभिन्न प्रकार की अलंकृत कांच की चूड़ियों के अतिरिक्त ग्लास वेयर्स, टेबलर्स वर्मस रिफिल, लैंप शेड्स, टेज, जग, साइंटिफिक गुड्स, बीड्स, झाड़ फानूस, बल्ब सेल्स, हेड लाइट शीशे, फुलदान तथा किचेन वेयर्स, फिरोजाबाद कांच उद्योग के मुख्य उत्पाद हैं. पूंजी विनियोजन, उत्पादन एवं रोज़गार सृजन की दृष्टि से फिरोजाबाद जनपद में कांच एवं सिरेमिक्स की 410 इकाइयां पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 72 करोड़ रूपए की पूंजी विनियोजन है. यहां लगभग 8 लाख टन कांच के सामानों का वार्षिक उत्पादन किया जाता है. इन उद्योगों में लगभग दो लाख श्रमिक कांच के उपादों एवं चूड़ी आदि की फिनिशिंग, प्रोसेसिंग, चूड़ी जुड़ाई, मुड़ाई, कटाई एवं अलंकरण के कार्यों में लगे हैं. फिरोजाबाद कांच उद्योग की वर्तमान स्थिति के अनुसार फिरोजाबाद में कांच उत्पादन की लगभग 185 इकाइयां स्थापित हैं, जिनमें से 185 औद्योगिक इकाईयां प्राकृतिक गैस का प्रयोग कर रही हैं. लगभग 80 इकाइयां अभी स्टीम कोयले पर आधारित हैं तथा गैस प्राप्त करने हेतु प्रयासरत हैं. लगभग 80–90 इकाइयां ग्लास वीड्स, पोट्टीज आदि अपने उद्योगों का आधुनिकीकरण एवं विविधीकरण करने हेतु प्रयासरत हैं. वर्तमान में फिरोजाबाद में कांच का कुल उत्पादन लगभग 400 से 425 करोड़ रूपया वार्षिक है, जिसमें लगभग 54 करोड़ रूपए का निर्यात शामिल है. जनपद में कुल 53 इकाइयां निर्यातक इकाइयों के रूप में पंजीकृत हैं. जनपद फिरोजाबाद में कांच–उद्योग में कुल पूंजी विनियोजन लगभग 72 करोड़ रूपया है. भारत के निकटवर्ती देशों में चूड़ी का निर्यात कुल उत्पादन का लगभग 15 प्रतिशत है, जबकि 85 प्रतिशत चूड़ी की खपत स्वदेशी बाज़ारों में होती है. कांच के अन्य उत्पादों जैसे आर्ट वेयर, झाड़ फानूस, किचिन वेयर आदि का निर्यात अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा खाड़ी, देशों में किया जाता है. वर्तमान में जनपद की लगभग 53 इकाइयां निर्यात कर रही हैं, जिनका सकल निर्यात लगभग 54 करोड़ रूपया है. प्रशिक्षण एवं तकनीकी विकास के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित कांच उद्योग विकास केंद्र (सीडीजीआई) ही प्रशिक्षण कार्यक्रम या अनुसंधान आदि के कार्य संचालित करता है. यहां कारखानों में गैस के आ जाने से कारखानों की हालत काफ़ी सुधर गई है. चूड़ी का कारोबार हज़ारों से लाखों, लाखों से करोड़ों में तब्दील हो गया है. लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि चूड़ियों के कारोबार को करोड़ों में पहुंचाने वाले यहां के कारीगरों की स्थिति दिन–ब–दिन बदतर होती जा रही है. इसका सबसे बड़ा कारण है, कारखानों में निरंतर काम का न चलना एवं वेतन नियमित न होना. फिरोजाबाद का कांच–मजदूर आज भी अभिलेखों के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्य करता है. इसे बमुश्किल साल में 200 दिन कार्य मिल पाता है. इस कारण यहां के मजदूरों के सामने रोज़ी–रोटी की समस्या मुंह फैलाए खड़ी रहती है. फिरोजाबाद का कांच मजदूर आज भी 2400 सेंटीग्रेड तापमान पर पिघलते हुए कांच के लावे के सामने काम करते हैं. फिरोजाबाद के कांच उद्योग का मजदूर ज़्यादातर टीबी आदि की बीमारियों से ग्रस्त होता है. शिक्षा से कोसों दूर होने के कारण यह इलाज से भी दूर रहता है, दो वक्त की रोटी की जुगाड़ के कारण वह पूरे परिवार को दांव पर लगा देता है. क्योंकि आज भी फिरोजाबाद के कांच औद्योगिक केंद्रों में मजदूरों के स्वास्थ्य, लेबर एक्ट तथा फैक्ट्री एक्ट के नियमों का पालन नहीं हो रहा है. स्थिति यह है कि 40–40 साल तक एक ही संस्थान में कार्य करने वाले मजदूर को दैनिक वेतनभोगी दर्शाकर बिना कोई भविष्यनिधि की सुविधा दिए कारखानों से बाहर कर दिया जाता है.

शिवम तिवारी
feedback@chauthidunya.com